# चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com



**अन्ना का तीसरा अनशन**

पेज-3

**कांग्रेस के पांच क्षत्रप**

पेज-4

**मनरेगा पर सियासत**

पेज-6

**साई की महिमा**

पेज-12



1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 14 नवंबर-20 नवंबर 2011 | मूल्य 5 रुपये

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

# आतंकवाद से लड़ने वाली सबसे बड़ी एजेंसी

# एन आई ए का सच

***आतंकवाद से लड़ने के लिए देश में सबसे बड़ी जांच एजेंसी तो बना दी गई है, पर उसे भी सियासत के एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. 33 महीनों बाद भी एनआईए को एक ठिकाना तक नहीं मिल सका है. वह आतंकियों का ठौर-ठिकाना लेने के बजाय राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की खोज-ख़बर लेने में लगी हुई है. मतलब यह कि सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हाशिए पर है.***

रूबी अरुण

गृहमंत्री पी चिदंबरम ने नॉर्थ ब्लॉक में बैठे बाबुओं और नौकरशाहों को ज़रिया बनाकर देश की आंतरिक सुरक्षा को भी सियासत का खेल बना दिया है. आप इसकी त्रासद बानगी देखना चाहें तो एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी पर नज़र डालें. देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को आतंकवादियों से बचाए-बनाए रखने के लिए गठित की गई राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी का वजूद गृहमंत्री पी चिदंबरम के सियासी दांव-पेंच और देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति लापरवाह नज़रिए का शिकार बन चुका है. गठन के तीन सालों बाद भी एनआईए के पास न तो अपनी कोई पुख्ता टीम है, न बैठने और कामकाज करने का कोई स्थायी ठिकाना. लिहाज़ा, मुंबई पर हुए 26/11 के हमले के बाद देश से आतंकवाद का सफ़ाया करने की नीयत से बनाई गई राष्ट्रीय जांच एजेंसी दर-बदर है और सरकार एवं उसके ताक़तवर मंत्री हिंदुस्तान की अस्मिता बचाने की कोशिश के बजाय अन्ना हजारे, बाबा रामदेव एवं अरविंद केजरीवाल को निपटाने तथा हिंदू संगठनों को आतंकवादी साबित करने की जुगत में हैं. जिस एजेंसी का गठन अमेरिका की सबसे अधिकार संपन्न जांच एजेंसी एफबीआई की तर्ज़ पर इसलिए किया गया था, ताकि वह स्वतंत्र तरीक़े से अपने असीमित अधिकारों के साथ देश से आतंक की जड़ का समूल नाश कर सके, उसके निदेशक को आज तक यही नहीं मालूम कि एनआईए का कार्यक्षेत्र क्या है और उसे किस दिशा में आतंकी मामलों की तफ्तीश करनी है. दुर्भाग्यपूर्ण यह भी कि एनआईए के गठन का प्रस्ताव रखने वाले और उसके पुरज़ोर हिमायती गृहमंत्री पी चिदंबरम आज तक यह भी तय नहीं कर पाए कि आतंकी मामलों की जांच में एनआईए की भूमिका क्या होगी?

> **जिस एजेंसी का गठन अमेरिका की सबसे अधिकार संपन्न जांच एजेंसी एफबीआई की तर्ज़ पर इसलिए किया गया था, ताकि वह स्वतंत्र तरीक़े से अपने असीमित अधिकारों के साथ देश से आतंक की जड़ का समूल नाश कर सके, उसके निदेशक को आज तक यही नहीं मालूम कि एनआईए का कार्यक्षेत्र क्या है और उसे किस दिशा में आतंकी मामलों की तफ्तीश करनी है.**

हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जनाब पी चिदंबरम कुछ भी नहीं कर रहे. उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा पुख्ता करने के नाम पर एनआईए, आईबी और रॉ जैसी ख़ुफ़िया एजेंसियों को इकोनॉमिकल क्राइम्स सुलझाने में लगा दिया है, ताकि वे वक़्त-बेवक़्त वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को यह कहते हुए कठघरे में खड़ा कर सकें कि उनका मंत्रालय हवाला और मनी लांड्रिंग के ज़रिए भारत आने वाले पैसों को नहीं रोक पा रहा है. यही पैसा भारत में ग़दर मचाने वाले आतंकी संगठनों को मज़बूत कर रहा है. आएदिन गृहमंत्री और प्रधानमंत्री यह बयान देते हुए सुने जाते हैं कि अगर आतंकवाद को ख़त्म करना है तो सबसे पहले उसके आर्थिक स्रोतों की कमर तोड़नी होगी. बहरहाल, इन लफ्फाजियों के दरम्यान गृह मंत्रालय खानापूर्ति भी करता रहा. मुंबई धमाकों के बाद से आज तक यानी लगभग तीन सालों में गृह मंत्रालय के अंदर कुल आठ बार इस मसले पर नोटिंग-ड्राफ्टिंग हुई कि देश की अंदरूनी सुरक्षा को कायम रखने के लिए एनआईए के पास एक ऐसी विशेष टीम होनी चाहिए, जिसमें किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर-पोस्टिंग न हो. जो भी अधिकारी-कर्मचारी इस विशेष टीम का सदस्य हो, वह देश की आंतरिक सुरक्षा के मसलों से सीधा और गहरा जुड़ा हो, ताकि ज़िम्मेदारी भी उसी की हो और दोषी भी वही हो. एनआईए का अलग स्वतंत्र फंड हो, सब-इंस्पेक्टर से ऊपर के सभी अधिकारियों के पास जांच के लिए स्पेशल पावर हो, ताकि विशेष स्थितियों में उसे अपने ऊपर के अधिकारियों के आदेश का इंतज़ार न करना पड़े. आतंकी मामलों की जांच में समय सीमा बाधा न बने, इसके लिए एनआईए को 90 दिनों के बजाय 180 दिनों तक आरोपियों को हिरासत में रखने का अधिकार हो.

> **देश की इस टॉप एजेंसी के अधिकारी, जो मुंबई ब्लास्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट सहित कई आतंकी घटनाओं की जांच कर रहे हैं, उनकी जान ख़ुद ही ज़ोखिम में है. देश की सबसे गोपनीय जांच एजेंसी को उसके गठन के 33 महीनों बाद भी गृह मंत्रालय ने बीच बाज़ार में बैठा रखा है.**

एनआईए के ख़ुद के वकील और अपनी अदालतें हों, ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े किसी भी मामले की त्वरित सुनवाई और फ़ैसला हो सके. इन सभी प्रावधानों में से किसी एक पर भी क़ायदे से कार्रवाई करने या आंतरिक सुरक्षा के लिए विशेष टीम बनाने की ज़हमत तो गृहमंत्री ने नहीं उठाई, पर हां...मुंबई ब्लास्ट के बाद नॉर्थ ब्लॉक में बैठने वाले और आंतरिक सुरक्षा के मसलों से जुड़े तक़रीबन दो दर्ज़न वरिष्ठ अधिकारियों के विभाग ज़रूर बदल दिए.

लेकिन, आतंकवाद का ख़ात्मा करने के प्रति चिदंबरम एवं प्रधानमंत्री कितने गंभीर हैं, इसका अंदाज़ा आप महज़ इस बात से लगा सकते हैं कि देश की इस टॉप एजेंसी के अधिकारी, जो मुंबई ब्लास्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट सहित कई आतंकी घटनाओं की जांच कर रहे हैं, उनकी जान ख़ुद ही ज़ोखिम में है. देश की सबसे गोपनीय जांच एजेंसी को उसके गठन के 33 महीनों बाद भी गृह मंत्रालय ने बीच बाज़ार में बैठा रखा है. दिल्ली के जसोला डिस्ट्रिक्ट के स्प्लेंडर मॉल की चौथी और पांचवीं मंजिल पर एनआईए का दफ्तर है, जहां दो सौ पचास अधिकारी-कर्मचारी शीशे की दीवारों के बीच बैठते हैं. पचास लाख रुपये महीने इसका किराया दिया जाता है. दफ्तर के नीचे फास्ट फूड और कैफे काफी डे के आउटलेट्स हैं, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक की शाखाएं हैं, पोर्श का ऑफिस है. मतलब यह कि दिन भर वहां हर किस्म के लोगों का जमावड़ा लगा रहता है. रात आठ बजे के बाद वहां का एल्वेटर काम नहीं करता. चौथी-पांचवीं मंजिल की दूरी सीढ़ियों से तय करनी पड़ती है. रात के आठ बजते ही तीन-चार घंटों के लिए बिजली चली जाती है. दफ्तर का जेनरेटर ज़रूरत के मुताबिक़ लोड नहीं उठा पाता. एनआईए का यह दफ्तर ऐसी जगह पर है, जहां ट्रैफिक की भयावह समस्या है. हालत यह है कि नॉर्थ ब्लॉक या मुख्य दिल्ली आने के नाम से ही अधिकारियों के हाथ-पैर ठंडे हो जाते हैं. रिमांड पर लिए गए आरोपियों की सुरक्षा के इंतजाम की बात भी इस दफ्तर में सोचना हास्यास्पद है. यहां के अधिकारी साफ़ तौर पर कहते हैं कि पूरा महकमा जान जोखिम में डालकर काम कर रहा है. आख़िरकार, एनआईए के अधिकारी जब चिदंबरम से गुहार लगा-लगाकर थक गए तो उन्होंने ख़ुद ही कोशिश शुरू कर दी. एनआईए के अधिकारी पिछले साल भर से सीजीओ कॉम्प्लेक्स में दफ्तर लेने के लिए जूते घिसते रहे, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली. अब जंतर-मंतर के पास बने एनडीएमसी मुख्यालय भवन के एनडीसीसी फेज-दो की छठी और सातवीं मंजिल एनआईए को देने का फ़ैसला कर एनडीएमसी ने आवंटन पत्र तो दे दिया, पर वहां भी अड़ंगे. कॉरपोरेशन अब यह कह रहा है कि पर्यटन मंत्रालय ने इसके लिए पहले ही आवेदन दे दिया था. जब तक पर्यटन मंत्रालय अपना आवेदन वापस नहीं लेता, तब तक एनआईए को यह दो मंजिलें नहीं दी जा सकतीं.

पर वस्तुत: हुआ क्या? आतंकवाद को मिटाने का राग अलापने और कोरे आश्वासन देने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके लाडले गृहमंत्री ने किया क्या? सरकार की काहिली और बदमिजाजी का यह आलम तब है, जबकि पिछले सात सालों में 27 धमाकों में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हज़ारों घायल. उस पर तुर्रा यह कि मनमोहन सिंह सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुबोधकांत सहाय बड़ी बेजारी से यह फरमाते हैं कि लोग अब इन धमाकों के आदी हो चुके हैं. गृहमंत्री की लालफीताशाही ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है. उदाहरण देखिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा को देख रहे वरिष्ठ आईएएस यू के बंसल के पास अपनी कोई स्थायी टीम नहीं है. ज़ाहिर है कि


**(शेष पृष्ठ 2 पर)**


> **किसी भी जांच एजेंसी की रीढ़ की हड्डी या उसका आधार उसका मज़बूत ख़ुफ़िया नेटवर्क होता है, लेकिन एनआईए के पास न तो अपना कोई एक्टिव इंटेलिजेंस है और न उसे अन्य सरकारी ख़ुफ़िया एजेंसियों से समय पर सूचनाएं ही मिल पाती हैं.**

अधिकारियों की कमी के कारण सरकार कई योजनाओं का सफल कार्यान्वयन नहीं करा पा रही है. ममता ने केंद्र से आईएएस अधिकारियों की मांग की है.



# दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

## बाबुओं की कमी

पश्चिम बंगाल में बाबुओं की कमी हो गई है. इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चिंतित हैं. जब वह रेल मंत्री बनी थीं तो अपने विश्वस्त बाबुओं को रेल मंत्रालय में ले आई थीं, लेकिन अब वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और राज्य के लिए आवंटित 314 आईएएस अधिकारियों की जगह केवल 214 आईएएस अधिकारी तैनात हैं. अधिकारियों की कमी के कारण सरकार कई योजनाओं का सफल कार्यान्वयन नहीं करा पा रही है. ममता ने केंद्र से आईएएस अधिकारियों की मांग की है. यही नहीं, पश्चिम बंगाल कैडर के जो 42 अधिकारी बाहर डिपुटेशन पर हैं, ममता उन्हें भी बुलाना चाहती हैं. राज्य के जो अधिकारी केंद्र में डिपुटेशन पर जाना चाहते हैं, उन्हें भी रोकने की कोशिश की जा रही है. जिन अधिकारियों को केंद्र में डिपुटेशन पर जाने की अनुमति नहीं मिली, उनमें पर्यावरण सचिव आरपीएस कहलोन और श्रम सचिव दिलीप रथ भी शामिल हैं.

## सरकारी दफ्तरों में हिंगलिश

दशकों तक सरकार शुद्ध हिंदी और शुद्ध अंग्रेजी पर जोर देती रही, लेकिन अब सरकारी भाषा में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है और कार्यालयों में हिंगलिश के इस्तेमाल की बात की जा रही है. गृह मंत्रालय ने बाबुओं से ऐसी भाषा इस्तेमाल करने की बात कही है, जिसे आसानी से समझा जा सके. इसमें हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है. आधिकारिक भाषा विभाग की सचिव वीना उपाध्याय ने जो दिशानिर्देश जारी किए हैं, उसके अनुसार, अब बाबुओं को अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों के बदले कठिन हिंदी शब्दों की तलाश की आवश्यकता नहीं है. अब वे अपने नोट में अंग्रेजी के शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. उनका कहना है कि हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों की समझ में आने वाली भाषा का उपयोग करना है, न कि हिंदी के नाम पर कठिनतम शब्दों का उपयोग करना, जिन्हें समझने के लिए लोगों को शब्दकोश की आवश्यकता पड़ जाए. विभाग के इस निर्णय से हिंदी विभाग में काम करने वाले बाबुओं को निश्चित रूप से राहत मिलेगी, उनके काम करने की गति तेज हो जाएगी और बार–बार शब्दकोश की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी.

## काम के बोझ तले बाबू

सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) की सफलता के चलते आवेदनों की बाढ़ आ गई है. केवल केंद्र सरकार की बात करें तो एक अनुमान के अनुसार, हर साल लगभग आठ लाख आवेदन विभिन केंद्रीय विभागों को प्राप्त होते हैं. जब इतने आवेदन आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि केंद्रीय सूचना आयोग पर काम का बोझ बढ़ गया है. हालांकि मुख्य सूचना आयुक्त सत्येंद्र मिश्र के साथ–साथ पांच सूचना आयुक्त व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. बाबुओं पर नज़र रखने वाले लोगों को इस बात पर आश्चर्य होता था कि सरकार उनके काम का बोझ कम करने के लिए विभाग में अतिरिक्त नियुक्तियां क्यों नहीं कर रही है, लेकिन अब सरकार को इसका एहसास हो गया है और वह पांच नए सूचना आयुक्त नियुक्त करने के लिए कदम उठा रही है. देर भले हो रही है, लेकिन जल्द ही सूचना आयोग में दस सूचना आयुक्त काम करना शुरू कर देंगे, जिससे विभाग के बाबुओं को कुछ राहत मिलेगी.

dilipcherian@gmail.com

# साउथ ब्लॉक

### शैलेष का तबादला शीघ्र

1991 बैच के आईएएस अधिकारी शैलेष कुमार सिंह को किसी दूसरे मंत्रालय में भेजा जा सकता है. वह अभी शहरी विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर हैं.

### प्रेम प्रकाश रक्षा मंत्रालय में

1998 बैच के आईओएफएस अधिकारी प्रेम प्रकाश रक्षा मंत्रालय में निदेशक बनाए जाएंगे. यह पद नवसृजित है.

### अजय निदेशक बनेंगे

1993 बैच के सीईएस अधिकारी अजय कुमार अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में निदेशक बनाया जा सकता है. वह देवेंद्र कुमार बक्शी की जगह लेंगे.

### मेरी वास बनेंगी सचिव

1977 बैच की आईएएस अधिकारी लोरेट्टा मेरी वास औषधि विभाग में सचिव बनाई जाएंगी. वह मुकुल जोशी की जगह लेंगी.

### अजय को उर्वरक विभाग

1977 बैच के आईएएस अधिकारी अजय भट्टाचार्य उर्वरक मंत्रालय में सचिव बनाए जाएंगे. वह अभी दूरसंचार विभाग में विशेष सचिव हैं.

# एन आई ए का सच

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कहा कि जांच सामूहिक तौर पर हो रही है. अब ऐसे हालात में एनआईए, एनएसजी, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, सीएफएसएल टीम और गृह मंत्रालय जांच में बराबर के साझीदार हुए, तो फिर जब जांच रिपोर्ट बनेगी तो वह किसके पास जाएगी? हरेक के जांच करने, तहकीकात करने का तरीका अलग होगा तो फिर उस पर आख़िरी फ़ैसला किसका होगा? ज़ाहिर है, यहां देश के गृहमंत्री होने के नाते पी चिदंबरम की भूमिका बेहद अहम हो जाती है. या तो वह सबकी ज़िम्मेदारियां निर्धारित करें या फिर खुद इस सामूहिकता में शामिल होकर फ़ैसले लें, पर शायद वह ऐसा नहीं मानते. तभी तो गृहमंत्री बनने के बाद से आज तक उन्होंने एक बार भी इन सभी विभागों के साथ मिलकर कोई बैठक नहीं की. नतीजतन, दिल्ली पुलिस के पास 13 सितंबर, 2008 के तीन बम विस्फोटों की जांच अभी भी अधूरी है. एनआईए की अगुवाई में मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट का मामला आज भी कई सवालों के दायरे में है.

हालांकि विवादों के बाद अब हाईकोर्ट ब्लास्ट की तफ्तीश एनआईए कर रही है, पर इससे दिल्ली पुलिस आहत है. मतलब यह कि अपने ही अधीन आने वाले विभागों में भी चिदंबरम समायोजन नहीं बैठा पा रहे हैं. यह आंकड़ा चौंकाने के साथ दुःखद भी है कि पिछले छह वर्षों में आतंकवादियों ने दिल्ली को पांच बार निशाना बनाया, जबकि देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को 1993 के बाद से 14 बार निशाना बनाया गया. गृह मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के मसलों से जुड़े हैं, कहते हैं कि दरअसल, चिदंबरम साहब ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों की सारी ऊर्जा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निपटाने में लगा दी है. जहां योजनाएं बननी चाहिए थीं, नीतियों पर कार्यान्वयन होना चाहिए था, वहां दूसरे मंत्रालयों को पत्र लिखने में समय बर्बाद किया जा रहा है. ख़ुफ़िया एजेंसियों की गुप्तचर शाखा का इस्तेमाल आतंकी और देश विरोधी गतिविधियों की जानकारी जुटाने में नहीं, बल्कि विपक्षी और अपनी भी पार्टी के नेताओं की अंदरूनी जानकारी जुटाने में किया जा रहा है. एनआईए भी इन्हीं कारगुजारियों का शिकार बन चुकी है. यही कारण है कि 26/11 के बाद से लेकर अब तक इसने किसी भी केस को उसके मुकाम तक नहीं पहुंचाया है. ऐसे में हम देश को सुरक्षित रखने और आतंकवाद के ख़ात्मे का सपना नहीं देख सकते.

feedback@chauthiduniya.com

### पृष्ठ एक का शेष

गृहमंत्री के लिए प्राथमिकता देश की आंतरिक सुरक्षा नहीं है. चलिए, पी चिदंबरम के मनमौजीपन की फेहरिस्त आगे बढ़ाते हैं. किसी भी जांच एजेंसी की रीढ़ की हड्डी या उसका आधार उसका मज़बूत ख़ुफ़िया नेटवर्क होता है, लेकिन एनआईए के पास न तो अपना कोई एक्टिव इंटेलिजेंस है और न उसे अन्य सरकारी ख़ुफ़िया एजेंसियों से समय पर सूचनाएं ही मिल पाती हैं. जबकि एनआईए के गठन के समय जब चिदंबरम साहब ने प्रस्ताव रखा था और संसद से वह प्रस्ताव पारित हुआ था, तब साफ़ तौर पर इस बात पर ख़ास ज़ोर दिया गया था कि इस एजेंसी में देश भर के सबसे उम्दा आईपीएस अफसरों की बहाली होगी और उन्हें देश के विभिन्न राज्यों से चुनकर लाया जाएगा, पर हमारे गृहमंत्री को अपने ही प्रस्तावित और पास किए गए प्रावधान याद नहीं रहे. उन्होंने यहां भी सियासी गोटियां फिट कर दीं. इसमें अलग–अलग राज्यों से ख़ासकर विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित प्रदेशों से ऐसे–ऐसे अधिकारियों को चुनकर लाया गया, जिनसे या तो वहां के मुख्यमंत्री ख़फ़ा थे या फिर जो शासन विरोधी कामों में लिप्त थे. मुद्दा महज़ इतना भी होता तो ज़्यादा फ़िक्र की बात नहीं थी, पर दुर्भाग्य यह है कि इनमें से ज़्यादातर ऐसे अधिकारी हैं, जिनकी पोस्टिंग कभी भी आतंकवाद ग्रस्त इलाक़ों में नहीं रही. एनआईए में आने के बाद भी इन अधिकारियों की न तो स्पेशल प्रोफेशनल ट्रेनिंग हुई और न इन्हें सुपर कॉप किस्म की कोई टीम ही मुहैया कराई गई है. इंटेलिजेंस गैदरिंग के नाम पर तो ये हैं ही खाली हाथ.

गृहमंत्री की बाबूगिरी यहीं ख़त्म नहीं होती. उनके इस ग़ैर ज़िम्मेदाराना रवैये का असर किस ख़ौफ़नाक तरीके से मुल्क को ख़तरे में डाल रहा है. यह भी देखिए ज़रा. घोषणा तो यह की गई कि एनआईए पूरी तरह से स्वायत्त एजेंसी होगी, इसके कार्यक्षेत्र में किसी का भी दखल नहीं होगा, लेकिन जब कोई वारदात होती है और एनआईए की टीम वहां जांच के लिए पहुंचती है तो वहां पहले से ही स्थानीय पुलिस, एनएसजी के अधिकारी अपने–अपने कार्यक्षेत्र का हवाला देकर मामले के अनुसंधान में अपनी क़ाबिलियत दिखा रहे होते हैं. जब दिल्ली हाईकोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ, तब भी यही असमंजस के हालात थे. घटना के बाद जब एनआईए की टीम डायरेक्टर एस सी सिन्हा की अगुवाई में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची तो उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि जांच जब सामूहिक है तो एनआईए की भूमिका इसमें क्या होगी?

**पिछले छह वर्षों में आतंकवादियों ने दिल्ली को पांच बार निशाना बनाया, जबकि देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को 1993 के बाद से 14 बार निशाना बनाया गया. गृह मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के मसलों से जुड़े हैं, कहते हैं कि दरअसल, चिदंबरम साहब ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों की सारी ऊर्जा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निपटाने में लगा दी है. जहां योजनाएं बननी चाहिए थीं, नीतियों पर कार्यान्वयन होना चाहिए था, वहां दूसरे मंत्रालयों को पत्र लिखने में समय बर्बाद किया जा रहा है.**

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 36
दिल्ली, 14 नवंबर–20 नवंबर 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001

कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

अन्ना के आंदोलन की हवा निकालने के लिए कांग्रेस ने सिटीज़न चार्टर बिल की बात सामने लाकर मास्टर स्ट्रोक खेला है. यह बिल ऐसा है, जिसका फ़ायदा देश की जनता को होगा.

## अन्ना का तीसरा अनशन

# कांग्रेस की रणनीति का जवाब है

***अच्छा तैराक नदी के बीच नहीं डूबता, वह तेज़ धार से लड़ते हुए ख़ुद को बचा लेता है. अच्छा तैराक हमेशा किनारे पर डूबता है. वह भी इसलिए, क्योंकि उसे लगता है कि यहां पानी कम है. जन लोकपाल के लिए अन्ना हजारे ने जिस आंदोलन को देशव्यापी बनाया, उसने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया. कांग्रेस पार्टी द्वारा अन्ना को भ्रष्ट बताया गया, उन्हें जेल भेजा गया. दिल्ली में आंदोलन न हो सके, इसके लिए हर तरह के हथकंडे सरकार ने अपनाए. उनके साथियों पर आरोप लगाए गए. आंदोलन में शामिल होने वालों को भी तंग किया गया. अन्ना ने हर मुश्किल का सामना किया और वह सफल भी हुए. अब वक़्त आया है, जब यह आंदोलन अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. यह टीम अन्ना के लिए सबसे चुनौती भरा समय है.***

मनीष कुमार

अन्ना का आंदोलन अब अपने आख़िरी पड़ाव पर आता दिख रहा है. दो स्थितियां बनती हैं. पहली यह कि सरकार अगर एक मज़बूत जन लोकपाल क़ानून लेकर आती है तो अन्ना का आंदोलन फिजल आउट कर जाएगा. दूसरी स्थिति यह बन सकती है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार लोकपाल क़ानून न बनाए. इस स्थिति में अन्ना फिर से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे. देश में फिर से वही माहौल बनेगा, जैसे कुछ दिनों पहले था. कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं. हरियाणा के हिसार में जो हुआ, उससे कांग्रेस सबक लेगी और लोकपाल के मामले में सावधानी बरतेगी, ऐसा तो मानना ही चाहिए, लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं, वे ठीक नहीं हैं.

अन्ना हजारे से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी कई स्तरों पर काम कर रही है. दिग्विजय सिंह अलग अपने बयान दे रहे हैं. दूसरी तरफ़ पार्टी की तरफ़ से ऐसे लोगों को तैनात किया गया है, जो अन्ना हजारे से सीधे संपर्क में हैं. अन्ना को यह समझाया जा रहा है कि उनकी टीम के कुछ लोग उन्हें कांग्रेस के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं, ताकि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को टारगेट बनाया जा सके. सरकार के लोग बताते हैं कि अन्ना हजारे से चल रही बातचीत से यह संकेत मिलता है कि वह अनशन नहीं करेंगे, उन्हें मना लिया जाएगा. अन्ना ने चेतावनी दी है कि अगर शीतकालीन सत्र में जन लोकपाल बिल पास नहीं किया गया तो वह आगामी 5 दिसंबर से दिल्ली में अपना तीसरा अनशन शुरू करेंगे. सरकार ने यह भी तय कर लिया है कि इस बार भी उन्हें दिल्ली में अनशन करने की अनुमति नहीं मिलेगी. मतलब यह कि सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं आएगा. सरकार ने जिस तरह पिछली बार अन्ना हजारे के लिए परेशानियां खड़ी की थीं, इस बार भी वैसा ही होगा. पिछली बार की तरह क्या कांग्रेस पार्टी फिर उन्हीं ग़लतियों को दोहराएगी, क्या वह फिर से जनता की नज़रों में भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी दिखना पसंद करेगी, क्या वह विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इस तरह का जोख़िम उठाएगी? पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने अपनी नासमझी की वजह से बहुत कुछ गंवा दिया, लेकिन इस बार वह अन्ना से निपटने के लिए तैयार दिख रही है. अन्ना हजारे के आंदोलन को कैसे बेअसर बना देना है, इसके लिए सरकार ने अपनी रणनीति बना ली है. सरकार एक लोकपाल बिल का मसौदा सामने लेकर आएगी. सरकार एक सशक्त लोकपाल बनाने के मूड में ही नहीं है, इसलिए इस देश को एक जन लोकपाल नहीं मिलेगा. सरकार जो लोकपाल लेकर आ रही है, उसका मुख्य मक़सद अन्ना हजारे के आंदोलन को कमज़ोर करना है. उस लोकपाल का मक़सद लोगों में भ्रम फैलाना होगा, ताकि लोकपाल के नाम पर सरकार के ख़िलाफ़ लोगों की नाराज़गी कम हो जाए. लोकपाल बिल ऐसा होगा, जिसकी बदौलत कांग्रेस के नेता संसद के अंदर और बाहर बहस कर सकेंगे. कांग्रेस पार्टी के सारे वकील नेता इस काम को बख़ूबी अंजाम देंगे. संसद के अंदर उन्हें दूसरे दलों का भी समर्थन मिलेगा. इसके बाद कांग्रेस पार्टी यह दावा करेगी कि जैसा वादा किया गया था, वैसा ही लोकपाल सरकार ने बना दिया. मतलब यह कि अन्ना हजारे और उनकी टीम द्वारा तैयार किया गया जन लोकपाल बिल संसद में पेश नहीं होगा. कांग्रेस की रणनीति यही है कि एक लुंजपुंज लोकपाल बिल संसद में पेश करके टीम अन्ना के सुझावों और महत्वपूर्ण मांगों को दरकिनार कर दिया जाए और उनके आंदोलन को कमज़ोर कर दिया जाए. विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और कांग्रेस पार्टी की नज़र अल्पसंख्यक मतदाताओं पर है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन मुसलमानों के समर्थन पर निर्भर करेगा. अगर मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से दूर चले गए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत बिहार जैसी हो जाएगी. यही वजह है कि कांग्रेस अन्ना हजारे को संघ का एजेंट बताकर अल्पसंख्यकों को लोकपाल के आंदोलन से दूर रखना चाहती है. इस रणनीति को अंजाम देने की पूरी ज़िम्मेदारी दिग्विजय सिंह के पास है. आगामी विधानसभा चुनावों में भ्रष्टाचार सबसे अहम मुद्दा होगा. अन्ना हजारे और उनकी टीम के लोग अगर उत्तर प्रदेश में रैलियां करेंगे या किसी यात्रा पर निकलेंगे तो कांग्रेस के लिए काफी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं. राहुल गांधी का सारा प्रचार अभियान विफल हो जाएगा. इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी टीम अन्ना के सदस्यों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के मामले उठा रही है और उन्हें भ्रष्ट साबित करने में लगी है. कांग्रेस की रणनीति साफ है कि टीम अन्ना के सदस्यों की साख ख़त्म करके अन्ना का असर कम किया जा सकता है. इस बार कांग्रेस पार्टी सिर्फ़ इतना ध्यान रख रही है कि जो ग़लती मनीष तिवारी ने की थी, वैसी ग़लती फिर से न हो. कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने अन्ना हजारे को ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट बताने की ग़लती थी, जिसकी भर्त्सना देश भर में हुई. बाद में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी. अन्ना हजारे से संपर्क बनाकर, उन्हें अच्छा बताकर कांग्रेस पार्टी उनके निकटतम लोगों पर उंगलियां उठाकर अपना हित साधने की रणनीति पर काम कर रही है.

अन्ना के आंदोलन की हवा निकालने के लिए कांग्रेस ने सिटीजन चार्टर बिल की बात सामने लाकर मास्टर स्ट्रोक खेला है. यह बिल ऐसा है, जिसका फ़ायदा देश की जनता को होगा. सभी मंत्रालयों एवं विभागों को जनता की शिकायतें दूर करने के लिए 15 दिनों का वक़्त मिलेगा. सरकार के मुताबिक़, यह विधेयक सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों में सूचना एवं सहायता केंद्र स्थापित करने का प्रावधान करेगा. लोग अपनी शिकायत और उस पर हो रही कार्रवाई का स्टेटस भी पता कर सकेंगे. प्रस्तावित विधेयक के बारे में जल्द ही जनता की राय ली जाएगी. इसके बाद विधेयक के अंतिम प्रारूप पर कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी और फिर इसे शीतकालीन सत्र में पेश कर दिया जाएगा. इसका प्रारूप कमोबेश सूचना के अधिकार की तरह है. इस बिल को इतनी जल्दबाज़ी में क्यों लाया जा रहा है, इसका भेद जयराम रमेश ने खोल दिया. उन्होंने बताया कि यह क़ानून लोकपाल क़ानून से ज़्यादा व्यापक होगा. रमेश ने कहा कि लोकपाल नौकरशाही में उच्च पदों पर बैठे लोगों तक ही सीमित है, जबकि नागरिक अधिकार शिकायत निवारण विधेयक, 2011 ब्लाक स्तर के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को दूर करेगा. जनता का काम इसी स्तर के अधिकारियों से ज़्यादा पड़ता है. रमेश के कथन से दो बातों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. पहला यह कि सरकारी लोकपाल में निचले स्तर के नौकरशाहों को शामिल नहीं किया जाएगा, जो अन्ना हजारे की एक महत्वपूर्ण मांग है. दूसरी बात यह कि सरकार भ्रष्टाचार का मायने ही बदलना चाहती है. सरकारी कामकाज में ढीलेपन और भ्रष्टाचार में फ़र्क़ होता है. सरकारी योजनाओं के तहत पैसों का जो गबन होता है, उस पर रोक कैसे लगेगी. उदाहरण के तौर पर, मनरेगा जैसी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर काबू कैसे पाया जाएगा. इसके लिए तो लोकपाल की ज़रूरत पड़ेगी. इससे तो यही समझ में आता है कि यह बिल किसी रणनीति के तहत लाया गया है. सरकार इस बिल को शीतकालीन सत्र में इसलिए लेकर आ रही है, क्योंकि उसका मक़सद अन्ना हजारे के आंदोलन को कमज़ोर करना है. जो लोग भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जो लोग छोटे-छोटे अधिकारियों को लोकपाल के तहत लाना चाहते हैं, उनके लिए यह ख़तरे की घंटी है.

कांग्रेस की रणनीति साफ है. सरकार एक ऐसा लोकपाल लेकर आएगी, जिसके पास दिखाने के दांत तो होंगे, लेकिन खाने या काटने के दांत नहीं होंगे. सरकारी लोकपाल असरहीन होगा, जिसके तहत न तो छोटे- छोटे अधिकारी होंगे, न जज होंगे, न सीबीआई होगी, न कोई सांसद होगा और न कोई मंत्री. लोगों ने तो प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने की बात तक करनी बंद कर दी है. चुनावों को देखते हुए सरकार लोकपाल बिल के मसौदे के साथ-साथ और भी कई क़ानून लागू करने का प्रयास करती नज़र आएगी. सत्र गुजर जाएगा और चुनाव भी हो जाएंगे, फिर इन सभी बिलों को महिला आरक्षण बिल की तरह अधर में लटका दिया जाएगा. सरकार लोगों को बिल पेश करने और मसौदा तैयार करने का झांसा देकर अन्ना का आंदोलन कमज़ोर करने की फिराक में है. अन्ना हजारे एक अनुभवी आंदोलनकारी हैं. वह इस बात को भलीभांति समझते हैं कि सरकार से अपनी मांगें कैसे मनवाई जा सकती हैं और सरकार क्या बहाने बना सकती है. अन्ना ने सरकार की हर चाल को भांप लिया है, इसलिए उन्होंने तीसरे अनशन की चेतावनी दी है. तीसरे अनशन की ज़रूरत इसलिए है, क्योंकि सरकार अपनी चालबाज़ी से अन्ना के आंदोलन को गुमराह करने में कामयाब रही. दूसरे राजनीतिक दलों ने भी सरकार की इस मुहिम में सहायता की. संसद में बहस के दौरान कुछ गिनी-चुनी ही पार्टियां थीं, जिन्होंने अन्ना का आंशिक समर्थन किया. अन्ना हजारे को अब यह आभास हो गया है कि सरकार जन लोकपाल या एक सशक्त लोकपाल नहीं लाना चाहती है. अन्ना का तीसरा अनशन निर्णायक होगा. देश की जनता को अगर भ्रष्टाचार से लड़ना है, अगर वह सरकारी तंत्र से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना चाहती है तो अन्ना के अगले अनशन को पहले से ज़्यादा समर्थन की ज़रूरत होगी. उम्मीद यही है कि इस बार भी देश का युवा सड़कों पर उतरेगा और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ निर्णायक लड़ाई में अपना योगदान देगा.

manish@chauthiduniya.com

**कांग्रेस की रणनीति साफ़ है. सरकार एक ऐसा लोकपाल लेकर आएगी, जिसके पास दिखाने के दांत तो होंगे, लेकिन खाने या काटने के दांत नहीं होंगे. सरकारी लोकपाल असरहीन होगा, जिसके तहत न तो छोटे-छोटे अधिकारी होंगे, न जज होंगे, न सीबीआई होगी, न कोई सांसद होगा और न कोई मंत्री. लोगों ने तो प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने की बात तक करनी बंद कर दी है. चुनावों को देखते हुए सरकार लोकपाल बिल के मसौदे के साथ-साथ और भी कई क़ानून लागू करने का प्रयास करती नज़र आएगी.**

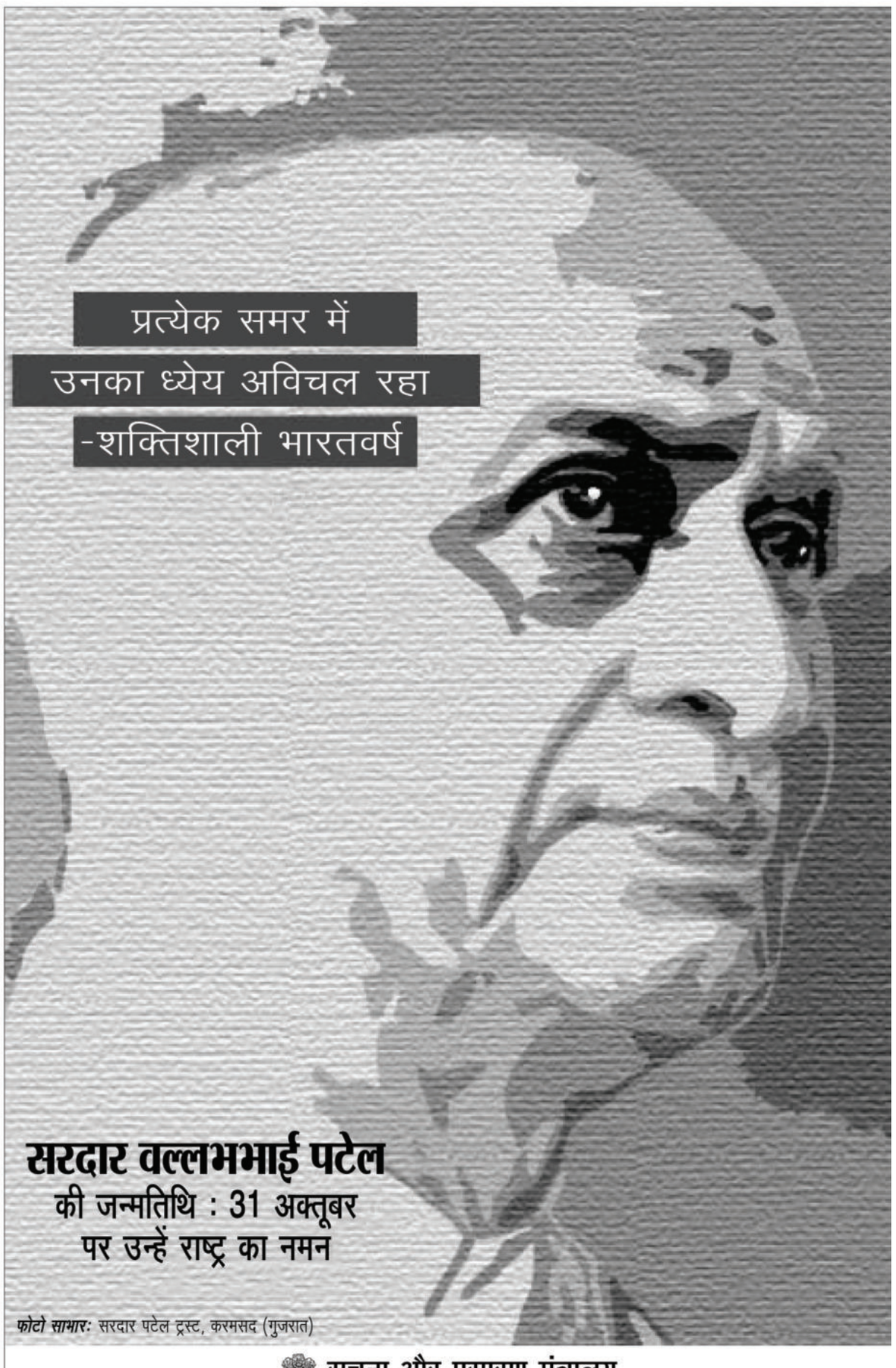

राहुल का कद ऊंचा करने के लिए बुंदेलखंड को विशाल आर्थिक पैकेज दिया गया, राहुल ने पदयात्राएं कीं, दलितों के छप्पर के नीचे बैठे, उनके साथ खाना खाया, भट्ठा पारसौल कांड से प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया.



## उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल समेत कई छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, लेकिन यह अभी सियासी नफ़ा-नुक़सान को देखते हुए स्वतंत्र पार्टी की तरह काम कर रही है.

# छोटे दलों के दलदल में फंसे बड़े-बड़े दल

पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जनक्रांति पार्टी भी सिरदर्द बनी हुई है, जो भाजपा के लोध वोट बैंक में सेंध लगाने की स्थिति में है.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

अजय कुमार

आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र छोटे दलों की उछलकूद से बड़े दल काफी चिंतित नज़र आ रहे हैं. राज्य के तमाम छोटे-छोटे दल बड़े सियासी दलों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं. बड़े राजनीतिक दल अपने फ़ायदे के लिए इन्हें साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन ये समय-समय पर आंख दिखाने से बाज नहीं आते. उन बड़े दलों, जो अब तक इनसे दूरी बनाकर चल रहे हैं, की राह में कांटे बिछाने का प्रयास भी छोटे दल बख़ूबी कर रहे हैं. दरअसल, छोटे दल लोकसभा या विधानसभा चुनाव में बड़े दलों को काफी प्रभावित करते हैं. ख़ासकर उन क्षेत्रों में, जहां बड़े-बड़े दलों के बीच कांटे की टक्कर होती है, वहां कुछ हज़ार वोट हासिल करने की कुव्वत रखने वाले इन छोटे दलों के प्रत्याशी कब किसका खेल बिगाड़ दें, यह कोई नहीं जानता. अगर इनके उम्मीदवारों का संबंध कभी किसी बड़े दल से रहा होता है तो बड़े दलों की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है. इसके अलावा जातीय समीकरण का खेल भी ऐसे प्रत्याशी ख़ूब खेलते हैं. भले ही इससे उन्हें कोई ख़ास फ़ायदा न हो, लेकिन बड़े दलों के उम्मीदवारों का नुक़सान हो जाता है. जाने-अनजाने में ऐसे उम्मीदवारों को कई बार फ़ायदा भी हो जाता है, जो वोट बंट जाने की वजह से कम वोट हासिल करने के बाद भी चुनाव जीत जाते हैं. हालांकि यह अंतर मामूली होता है, लेकिन मत विभाजन होने से कभी-कभी बड़े और चर्चित उम्मीदवार को भी क़रारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है. वैसे इन छोटे दलों की पकड़ स्थानीय स्तर तक सीमित है. यही वजह है कि बड़े दल चुनाव में इन्हें नज़रअंदाज़ करने की भूल नहीं करना चाहते. इसीलिए इन छोटे दलों को मनाने का प्रयास चलता रहता है. प्रदेश में 2012 में विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र हर बड़ा दल इन्हें अपने खेमे में लाकर चिंतामुक्त होना चाहता है. माना यह जा रहा है कि इस बार कुछ जातियों के वोटों में ज़बरदस्त बिखराव हो सकता है. ख़ासकर दलित वोटों में भारी उलटफेर देखने को मिल सकता है. वहीं पिछड़ी जातियों और मुस्लिम वोटों के लिए भी मारामारी हो सकती है. दलित और मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने के लिए खड़े हुए छोटे दल राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं. समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में डॉ. अयूब की पीस पार्टी के अलावा कौमी एकता दल और उलेमा काउंसिल से कड़ी चुनौती मिल रही है. ख़ास बात यह है कि ये तीनों दल मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं. पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. अयूब का कहना है कि उनकी पार्टी पर यह इल्ज़ाम लगाना सरासर ग़लत है कि वह केवल मुस्लिमों की पार्टी है. पीस पार्टी हिंदू-मुसलमानों को साथ लेकर चलने का न सिर्फ़ नारा देती है, बल्कि उस पर अमल भी करती है. वह न तो भाजपा की तरह हिंदुओं को बरगलाती है और न बसपा-सपा और कांग्रेस की तरह मुसलमानों को विकास के नाम पर सब्ज़बाग़ दिखाती है. दलित वोटों पर अपना एकाधिकार मानने वाली बहुजन समाज पार्टी को उदितराज की इंडियन जस्टिस पार्टी से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है. उदितराज बसपा प्रमुख एवं मुख्यमंत्री मायावती से नाराज़ दलितों को गोलबंद करने में जुटे हैं. साथ ही बहुजन लोकपाल का मुद्दा उठाकर वह पढ़े-लिखे दलितों को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. सियासी जानकारों के अनुसार, अगर उनकी कोशिश रंग लाई तो बसपा का परंपरागत दलित वोट बैंक खिसक सकता है. उदितराज कहते हैं, दलितों को मायावती से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद भी मायावती ने उनकी दशा सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ़ कुछ वर्गों का ही भला किया. लिहाज़ा हम बसपा शासन में उपेक्षित दलितों को एकजुट कर रहे हैं और चुनाव में दलित वोटों पर बसपा का एकाधिकार समझने वाली मायावती की ग़लतफ़हमी भी दूर कर देंगे. उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल समेत कई छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, लेकिन यह अभी सियासी नफ़ा-नुक़सान को देखते हुए स्वतंत्र पार्टी की तरह काम कर रही है. हालांकि निर्दलीय विधायक अखिलेश सिंह और बसपा से निलंबित विधायक जितेंद्र सिंह बबलू जैसे बाहुबलियों को अपने खेमे में लाने के कारण पीस पार्टी की काफी आलोचना हो रही है, लेकिन वर्ष 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली पीस पार्टी पर फ़िलहाल सबकी नज़रें टिकी हुई हैं. ऐसे में देखना यह होगा कि प्रदेश विधानसभा चुनाव में यह दूसरे बड़े दलों को कितना फ़ायदा और नुक़सान पहुंचाती है.

दूसरी तरफ़ भाजपा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जनक्रांति पार्टी सिरदर्द बनी हुई है, जो भाजपा के लोध वोट बैंक में सेंध लगाने की स्थिति में है. भाजपा ने कल्याण सिंह की लोध जाति पर पकड़ को कम करने के लिए इसी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को प्रदेश चुनाव की कमान सौंपी है, लेकिन वह कल्याण सिंह की धार को कितना भोथरा कर पाती हैं, यह तो चुनाव के बाद ही पता लग पाएगा. इसके अलावा धुर विरोधी अशोक प्रधान, जो न सिर्फ़ कल्याण सिंह की बिरादरी से हैं, बल्कि उनके वर्चस्व वाले क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं, को भी आगे किया जा रहा है. इसी तरह अमर सिंह का लोकमंच, पूर्वांचल विकास पार्टी एवं अपना दल जैसे राजनीतिक संगठन भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं. कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ समझौता कर लिया है और क्षेत्रीय आधार पर भी वह कुछ छोटे दलों से हाथ मिलाना चाहती है. एक तरफ छोटे-छोटे दल चार-छह सीटें जीतकर सौदेबाज़ी का सपना (अगर चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है) पाले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ़ इस बार छोटे दलों के प्रति चुनाव आयोग की नज़रें टेढ़ी हैं. आयोग के अनुसार, यदि किसी दल ने आठ प्रतिशत से कम मत हासिल किए तो उसकी मान्यता ख़तरे में पड़ सकती है.

feedback@chauthiduniya.com

# कांग्रेस के पांच क्षत्रप

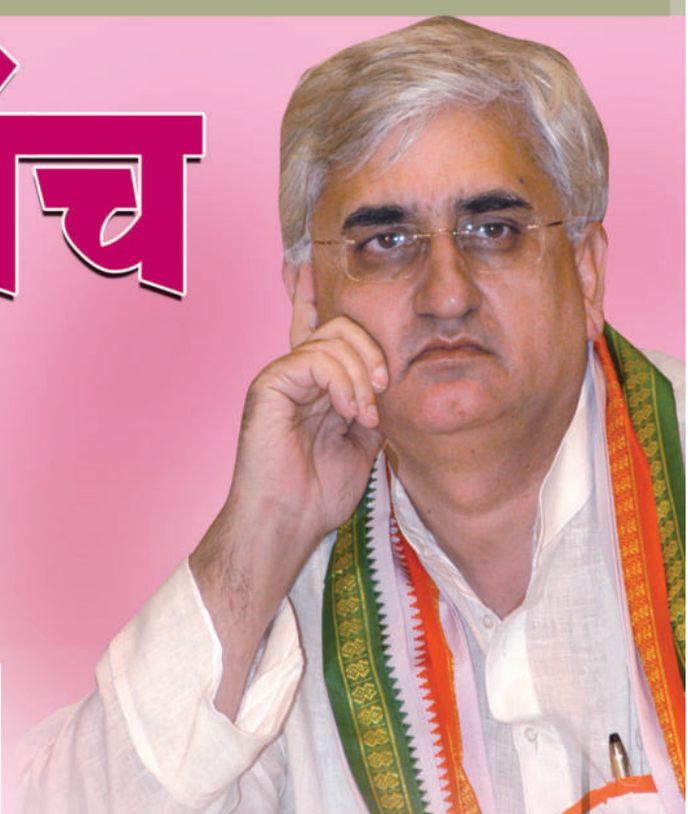

## माया-मुलायम के गढ़ में सेंध का मंसूबा

**प्रदेश में कांग्रेस के पांच-पांच महारथियों की आमद से राहुल गांधी की बांछें खिल गई हैं. उन्हें अपने गढ़ अमेठी की चिंता नहीं रह गई है. उनका रथ माया और मुलायम के गढ़ में घुसकर वार करेगा. राहुल के तरकश के लिए ऐसे तीरों का इंतज़ाम किया जा रहा है, जो अचूक हों. राहुल गांधी के तूफ़ानी दौरे का खाका तैयार किया जा रहा है. मायावती सरकार पर तीखे तेवर अपनाने की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी. श्रीप्रकाश जायसवाल की देखरेख में खिंचे खाके के अनुरूप राहुल जालौन से बदायूं, बिजनौर से इटावा, चित्रकूट से सीतापुर, बलिया से गोंडा और पीलीभीत से महाराजगंज तक दौरा करेंगे. देखना यह है कि राहुल के लिए कांग्रेस के धुरंधरों द्वारा बनाया जा रहा खाका कितना कारगर होगा. वह मायावती और मुलायम सिंह के मज़बूत किले को तोड़ पाने में सफल हो पाएंगे या नहीं.**

राजनीति में कब किसका पलड़ा भारी हो जाए, माहौल कब किस करवट बैठ जाए, कहा नहीं जा सकता. इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तर प्रदेश है, जहां कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी अकेले दम पर सियासत का खेल खेल रहे थे, जनता उन्हें सिर आंखों बैठा रही थी, लेकिन अन्ना के आंदोलन ने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है. सूबे के सियासी गलियारों में इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा. राहुल की यात्राओं की चमक फीकी पड़ गई. जो कांग्रेसी उन्हें अगला प्रधानमंत्री मानकर चल रहे थे, वे अब इस बात को कहने से भी कतराते हैं. कांग्रेस की जनसभाओं में अब उतनी भीड़ नहीं होती, जितनी उपचुनावों के दौरान हो रही थी. सोनिया और राहुल के रोड शो को लोग अभी तक भुला नहीं पाए हैं, लेकिन अब उसका उल्टा हो रहा है. राहुल का कद ऊंचा करने के लिए बुंदेलखंड को विशाल आर्थिक पैकेज दिया गया, राहुल ने पदयात्राएं कीं, दलितों के छप्पर के नीचे बैठे, उनके साथ खाना खाया, भट्ठा पारसौल कांड से प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया, मगर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिल सकी. मिशन 2014 को डूबते देख कांग्रेस आलाकमान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम गठित की है, जिसमें श्रीप्रकाश जायसवाल, सलमान खुर्शीद, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह और प्रदीप जैन शामिल हैं. ये पांचों चुनाव की ज़िम्मेदारी संभालेंगे. कांग्रेस का चुनाव प्रबंधन इस बार लखनऊ के बजाय जोन स्तर पर होगा. प्रदेश को 10 जोनों में बांटकर हर जोन में एक केंद्रीय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है, उसे सहयोग करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दो नेताओं को सह कोआर्डिनेटर बनाया गया है. केंद्रीय मंत्रियों को बतौर प्रभारी कोआर्डिनेटर नियुक्त किया गया है. हर प्रेक्षक को लगभग 40 विधानसभा क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. प्रेक्षकों के कार्यालय जोनल मुख्यालय पर होंगे और वे वहीं रहकर चुनाव की निगरानी करेंगे. मेरठ, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद एवं झांसी में पार्टी के जोन कार्यालय स्थापित करने की कवायद शुरू हो गई है.

विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों या संगठन के लोगों को दिल्ली या लखनऊ की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी. बेहतर और प्रभावी चुनाव प्रबंधन के लिए ही प्रदेश को दस जोनों में बांटा गया है और उसका आधार बनाया गया पिछले साल निकाली गई संदेश यात्रा को. जोन एक में सहारनपुर एवं मेरठ मंडल हैं. इसका मुख्यालय मेरठ में होगा. इसके प्रेक्षक मोतीलाल शर्मा हैं, जिनके साथ पीसीसी से सह कोआर्डिनेटर के रूप में राजेंद्र शर्मा एवं जुग्गम कुरैशी को नियुक्त किया गया है. जोन दो में अलीगढ़ एवं आगरा मंडल के अलावा बुलंदशहर का कुछ हिस्सा शामिल है. इसका मुख्यालय आगरा में होगा. इसके प्रेक्षक अश्क अली टाक होंगे. उनके सहयोग के लिए सोमांश प्रकाश, सईदुज्जमा एवं रणबीर राना को लगाया गया हैं. मेरठ एवं आगरा जोन के प्रभारी कोआर्डिनेटर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद होंगे. जोन तीन में मुरादाबाद एवं बरेली मंडल हैं. इसका मुख्यालय बरेली में होगा. इसके प्रेक्षक मुज़फ्फर अली बनाए गए हैं, उनका साथ देंगे पीसीसी के सतीश त्यागी एवं हसन आरिफ अंसारी.

जोन चार में पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद एवं लखनऊ मंडल शामिल हैं. इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा. इसके प्रेक्षक भाई जगताप होंगे. उनके साथ पीसीसी के बलदेव चौधरी एवं अरशद आजमी रहेंगे. जोन तीन एवं चार का प्रभारी आरपीएन सिंह को बनाया गया है. जोन पांच में उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली जिला एवं फैजाबाद मंडल शामिल हैं. इसका मुख्यालय कानपुर में होगा. इसके प्रेक्षक रामेश्वर नीखरा होंगे और उन्हें साथ देंगे पीसीसी के हाफिज मोहम्मद उमर एवं आरती वाजपेयी. जोन छह में बाराबंकी जिला, देवी पाटन एवं बस्ती मंडल शामिल हैं. इसका मुख्यालय बस्ती में होगा. इसके प्रेक्षक अशोक राम होंगे. उनके साथ पीसीसी से श्यामलाल पुजारी एवं सुषमा सिंह को लगाया गया है. जोन पांच एवं छह के प्रभारी श्रीप्रकाश जायसवाल बनाए गए हैं. जोन सात में गोरखपुर एवं आजमगढ़ मंडल शामिल हैं. इसका मुख्यालय गोरखपुर में होगा. चंदन बागची इसके प्रेक्षक होंगे. उनके साथ कमला साहनी एवं प्रजानाथ शर्मा को लगाया गया है. जोन आठ में आजमगढ़, भदोही ज़िला एवं वाराणसी मंडल शामिल हैं. इसका मुख्यालय वाराणसी में होगा. इसके प्रेक्षक शकीलुज्जमा होंगे. उनके साथ पीसीसी के कमला सिंह एवं अभय अवस्थी लगाए गए हैं. जोन सात एवं आठ के प्रभारी सलमान खुर्शीद होंगे. जोन नौ में सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट जिला एवं इलाहाबाद मंडल शामिल हैं. इसका मुख्यालय इलाहाबाद में होगा और प्रेक्षक बनाए गए हैं इक़बाल अहमद सरादगी, जिनका साथ देंगे पीसीसी के जे एन विश्वकर्मा एवं इमरान आफरीन. जोन दस में झांसी, चित्रकूट एवं कानपुर मंडल शामिल हैं. इसका मुख्यालय झांसी में होगा. इसके प्रेक्षक मदन मोहन झा हैं. जोन नौ एवं दस के प्रभारी बनाए गए हैं प्रदीप जैन आदित्य.

दर्शन शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

बाढ़ राहत के नाम पर केवल लूट हुई है और इसकी उच्चस्तरीय जांच ज़रूरी है. दो-दो साल से पैसा पड़ा है, पर सरकार केवल अपना ढिंढोरा पीटने में लगी है.



बिहार

## कोसी पुनर्वास योजना

# नीति और नीयत दोनों में खोट

सरोज सिंह

कोसी के बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए बिहार सरकार ने दुनिया भर में ढिंढोरा पीटा और बताया कि प्रकृति के इस क़हर से पूरी संजीदगी के साथ लड़ा जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आगे इस तरह की विपदा आने पर जान-माल का ज़्यादा नुकसान न हो. सरकार की वाहवाही हुई और यह संदेश गया कि वास्तव में नीतीश सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के दर्द को महसूस किया है, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई कुछ नई सूचनाओं से पता चलता है कि सरकार केवल दिखावटी आंसू गिरा रही है और बाढ़ पीड़ितों के दर्द का एहसास उसे रत्ती भर भी नहीं है. सरकार हर काम में भले ही पैसे का रोना रोए, पर हक़ीक़त यह है कि कोसी पुनर्वास योजना के लिए मिले धन का उपयोग करने में वह काफी पीछे है. आरटीआई की सूचना बताती है कि कोसी आपदा से प्रभावित सहरसा जिले में विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्यों की विकास निधि से प्राप्त 83 करोड़ 25 रुपये का इस्तेमाल सामुदायिक भवन और मवेशी शेल्टर बनाने में मंथर गति से अभी शुरू ही हुआ है. यह वित्तीय वर्ष 2008-09 की कर्णांकित राशि है. हद तो यह है कि अभी पूरी धनराशि में से केवल छियालिस करोड़ पैंतीस लाख छियासी हज़ार नौ सौ तीस रुपये ही आवंटित किए गए हैं. मतलब यह कि दो सालों में केवल लगभग आधी राशि आवंटित कर सूची बनाई गई और काम की प्रक्रिया शुरू की गई है.

सामुदायिक भवन और मवेशी शेल्टर कब बनेगा, इसका अंदाज़ा सरकार की इसी गति से लगाया जा सकता है. एक बानगी ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव डॉ. बी राजेंद्र के 20 जुलाई, 2011 के पत्र पर डालिए, जो उन्होंने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष विपिन कुमार को लिखा है. पत्र में कहा गया है, सहरसा ज़िले के बाढ़ग्रस्त आठ प्रखंडों के 35 कार्यस्थलों पर इन परियोजनाओं के निर्माण हेतु संबंधित सूची उपलब्ध कराई गई है. इसी क्रम में ज़िला पदाधिकारी सुपौल के प्रासंगिक पत्र द्वारा इस जिले के सात प्रखंडों की 39 पंचायतों एवं 39 गांवों में विषयांकित परियोजना के निर्माण के लिए सूची उपलब्ध कराई गई है. सूची के क्रमांक 1 से 14 और क्रमांक18,19,20,21,33,35 एवं 39 पर दर्शाए गए कार्यस्थल क्रमश: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और सांसद निधि से बनने वाले कार्यस्थलों की सूची में सम्मिलित हैं. इस प्रकार उक्त क्रमांकों के कुल 21 कार्यस्थलों को छोड़कर शेष बचे 18 कार्यस्थलों पर इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारंभ कराई जाए. मतलब यह कि दो साल का वक़्त केवल प्रक्रिया शुरू करने में लग गया. अगर इस बीच कोसी में बाढ़ आ जाती तो फिर क्या होता? पैसे धरे रह जाते और लोगों का भारी नुकसान हो जाता.

राजद सांसद रामकृपाल यादव कहते हैं कि सरकार की बदनीयती का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि एक तरफ वह नरेंद्र मोदी के पैसे लौटा रही है और दूसरी तरह पुनर्वास के लिए जमा धन पर कुंडली मारकर बैठी हुई है. उनका आरोप है कि बाढ़ राहत के नाम पर केवल लूट हुई है और इसकी उच्चस्तरीय जांच जरूरी है. दो-दो साल से पैसा पड़ा है, पर सरकार केवल अपना ढिंढोरा पीटने में लगी है. बाढ़ पीड़ितों की परेशानी से उसका कुछ लेना-देना नहीं है. पूर्व विधान पार्षद पी के सिन्हा मानते हैं कि सरकार के पास कोसी के बाढ़ पीड़ितों को राहत देने की कोई योजना ही नहीं है. अगर होती तो करोड़ों रुपये इस तरह पड़े न रह जाते. राहत के नाम पर झूठा प्रचार चल रहा है. इस राशि के अलावा कोसी पुनर्वास योजना के लिए विश्व बैंक की बहुचर्चित साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये की घोषित सहायता पर भी ग्रहण लगता नज़र आ रहा है. विश्व बैंक ने पुनर्वास योजना के लिए दी जाने वाली यह सहायता ऑनर ड्रीवेन रिहेबिलिटेशन कोलेबरेटिव (ओडीआरसी) से करने की शर्त थोप दी है, जबकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है. विश्व बैंक और कोसी पुनर्वास आयोग के बीच इस मसले को लेकर पैदा विवाद शीघ्र न सुलझा तो अगले महीने से एक मिलियन डॉलर की घोषित सहायता पर रोक लग सकती है. आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि इस वर्ष जनवरी में विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट बी जोलियक पटना आए थे तो उन्होंने कोसी पुनर्वास आयोग के लिए एक मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की थी, जिसमें से एक हज़ार करोड़ पहले चरण में उपलब्ध हो चुके हैं. करीब साढ़े तीन हज़ार करोड़ की धनराशि अभी मिलनी है, जिससे पुनर्वास योजना के दूसरे चरण का कार्य होना है. इसके बाद विश्व बैंक ने इस धनराशि की पहली किस्त के रूप में 220 मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की, लेकिन अब तक यह राशि सरकार के खाते में नहीं आई है. यह सहायता राशि कोसी पुनर्वास आयोग को ख़र्च करनी है, लेकिन आयोग के वर्तमान परियोजना निदेशक ने ओडीआरसी से कार्य कराने से इंकार कर दिया है.

आयोग का मानना है कि ओडीआरसी निबंधित संस्था नहीं है, ऐसे में इसके तहत राशि ख़र्च होना नियम सम्मत नहीं होगा. सूत्र बताते हैं कि पिछले सप्ताह विश्व बैंक के अधिकारियों ने राज्य के मुख्य सचिव नवीन कुमार के समक्ष यह मामला उठाया था और शीघ्र हल निकालने की अपील की थी. विश्व बैंक से मिलने वाली सहायता राशि से कोसी इलाके में क्षतिग्रस्त मकानों-सड़कों का पुनर्निर्माण, बिजली, सिंचाई एवं पंचायती राज व्यवस्था में सुधार, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आजीविका की व्यवस्था, तटबंधों का सुदृढ़ीकरण, खेतों में जमी बालू की गाद की सफाई आदि कार्य कराए जाने हैं. अगर गतिरोध नहीं टूटा तो इस पूरी परियोजना पर ग्रहण लग सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

कश्मीर

## सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम

# देश सर्वोपरि है राजनीति नहीं

फोटो–प्रभात पाण्डेय

जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफसपा) को लेकर सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन के बीच मतभेद उभर कर सामने आ गए हैं. कांग्रेस के अंदरख़ाने भी इस मुद्दे पर कोई आपसी सहमति नहीं है. मालूम हो कि हाल में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मांग की कि राज्य के कुछ क्षेत्रों से अफसपा हटा दिया जाए. उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से श्रीनगर, जम्मू, बड़गाम और सांबा आदि ज़िलों में शांतिपूर्ण माहौल है, इसलिए वहां से यह क़ानून हटा लेना चाहिए. हालांकि उन्होंने कहा कि इन ज़िलों से यह क़ानून हटाने का मतलब यह नहीं है कि सेना की भूमिका कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका बयान वाक़ई चौंकाने वाला है. यह अधिनियम हटने के बाद क्या वास्तव में सेना वही भूमिका निभा पाएगी, जो पहले से निभाती आ रही है, ऐसा लगता तो नहीं है. सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया. उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा कि सेना ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी है. हालांकि उन्होंने साफ़ तौर पर नहीं कहा कि अभी यह अधिनियम यहां से हटाने का समय नहीं आया है, लेकिन एक अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के बयान और सेना मुख्यालय से मिली जानकारी से सेना की सोच का अनुमान लग जाता है. उक्त अधिकारी के मुताबिक़ अगर सैनिकों को इस क्षेत्र में विशेष अधिकार नहीं मिलता है तो उनकी हर कार्रवाई पर मानवधिकार संगठन और राजनीतिक दल उंगली उठाएंगे. सेना का तो काम करना मुश्किल हो जाएगा.

हक़ीक़त यह है कि सीमा पार अभी भी 50 से अधिक आतंकी शिविर चल रहे हैं. इसके अलावा क़रीब 100 से अधिक आतंकी सीमा पार से घुसपैठ करने के लिए तैयार बैठे हैं. आतंकी पहले की तुलना में ज़्यादा हाईटेक होते जा रहे हैं. उनके पास से न केवल उच्चस्तरीय हथियार, चाकू, कटर एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिल रहे हैं, बल्कि उच्च तकनीक आधारित विस्फोटक तैयार करने में भी वे माहिर हो चुके हैं. उनका प्रशिक्षण कमांडो स्तरीय रहा है. यही नहीं, सीमावर्ती इलाक़ों में चीनी सैनिकों की मौजूदगी और आतंकियों को मदद देने की उनकी कोशिशों के चलते सीमा पर चुनौतियां पहले से अधिक बढ़ गई हैं. साथ ही अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी ऐसा है, जिसमें इस अधिनियम को हटाना देश के हित में नहीं है. पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को सहयोग दे रहा है. हाल में हक्कानी नेटवर्क के सहयोग देने के सुबूत भी मिले हैं. कश्मीर में आतंकवाद पाकिस्तान के समर्थन से ही चलाया जाता है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा, तब तक स्थितियां सामान्य होने की कोई गुंजाइश नहीं है. कुछ समय के लिए पाकिस्तान विराम ले सकता है, जो उसकी रणनीति का ही हिस्सा होता है जिसका इस्तेमाल वह एक बड़ी आतंकी कार्रवाई के लिए करता है. पहले भी ऐसा हो चुका है. हक्कानी नेटवर्क से रिश्ते के ख़ुलासे के बाद से पाकिस्तान पर अमेरिका का बहुत दबाव है. ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कुछ समय तक अपनी भारत विरोधी गतिविधियों को विराम दे सकता है और उसका इस्तेमाल बड़ी घुसपैठ की तैयारी के लिए कर सकता है. ऐसे में यदि चार ज़िलों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम हटा दिया जाता है तो कश्मीर को फिर किसी बड़ी आतंकी घटना का शिकार बनना पड़ सकता है.

अब प्रश्न यह उठता है कि इन बातों की जानकारी होते हुए भी उमर अफसपा को कश्मीर के कुछ ज़िलों से हटाने की बात क्यों कर रहे हैं. वजह साफ़ है कि उनकी यह मांग केवल राजनीति से प्रेरित है. पहली बात तो यह है कि वह इस मुद्दे को उठाकर अपने ऊपर लगे आरोपों से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं. इसके अलावा इससे वह विपक्ष के साथ-साथ सहयोगी पार्टी कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते हैं. ग़ौरतलब हो कि कश्मीर की जनता इस क़ानून को अपने ऊपर अत्याचार का साधन मानती है. जब उमर इसे हटाने की मांग करेंगे तो वह जनता की नज़रों में हीरो बन जाएंगे. हालांकि वह जानते हैं कि उनकी मांग से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसे हटाने का अधिकार केंद्र के पास है न कि राज्य के पास. लेकिन इसका राजनीतिक फ़ायदा तो उठाया ही जा सकता है. वैसे भी मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसे आगामी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में जनसमर्थन मिल सके. इसलिए उन्होंने इसी मुद्दे को जनभावना को अपने पक्ष में करने का हथियार बना लिया है. उन्हें कश्मीर की जनता की सुरक्षा की चिंता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह इस मुद्दे को उठाने से पहले सभी दलों के नेताओं से इस पर विचार-विमर्श करते. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. कारण कोई भी हो, उमर की इस मांग के कारण कश्मीर की राजनीति में उबाल आ गया है. प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं के माथे पर बल पड़ने लगे हैं. उन्हें लगता है कि उमर मनमानी कर रहे हैं और गठबंधन धर्म का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं. प्रदेश कांग्रेस प्रमुख सैफुद्दीन सोज़ ने कहा कि उमर ने ऐसी मांग करने से पहले कांग्रेस के नेताओं से विचार-विमर्श नहीं किया. हालांकि सोज़ भी इस अफसपा पर राजनीति ही कर रहे हैं और वह चाह रहे हैं कि इसे लेकर कोई विवाद हो, जिससे कांग्रेस को मुख्यमंत्री बदलने का मौक़ा मिल जाए. हालांकि सोज़ अपने मक़सद में कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के दल के एक नेता ने उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया है. प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ताज मोहिउद्दीन का कहना है कि उमर ने इस मुद्दे पर उनसे विचार-विमर्श किया था. इस मुद्दे के कारण न केवल प्रदेश में कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस के बीच का आंतरिक विवाद उभर कर सामने आया है, बल्कि कांग्रेस के अंदर पनप रहे आपसी मतभेद भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं.

अब सोज़ और मोहिउद्दीन के बयानों में जो विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है, उससे तो यही लगता है कि प्रदेश कांग्रेस के भीतर एकता नहीं है. या तो सोज़ ने अपने सहयोगियों से विचार-विमर्श किए बिना उमर पर आरोप लगा दिया या फिर यह मोहिउद्दीन की अपनी कोई चाल है, जो उमर का समर्थन करके सफल हो सकती है. दोनों ही स्थितियों में यह साबित होता है कि प्रदेश कांग्रेस के भीतर दरार है. उमर ने आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह दांव खेला है और वह कुछ हद तक सफल भी हो सकते हैं, लेकिन यह तो कहा ही जा सकता है कि जहां मामला देश की सुरक्षा का हो वहां राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बलि दी जानी चाहिए. कश्मीर में अफसपा पर राजनीति हो रही है जो देश हित में नहीं है. आख़िरकार देश सुरक्षित रहेगा तभी राजनीति होगी और देश ही असुरक्षित होगा तो राजनीति कहां करेंगे.

राजीव कुमार
feedback@chauthiduniya.com

अगर राहुल गांधी ख़ुद को आदर्श नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों में केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान देना होगा.

# मनरेगा पर सियासत

फ़िरदौस ख़ान

देश में आज भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, मगर अफ़सोस की बात यह है कि सियासी पार्टियां जनहित के बजाय पार्टी हित के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं. कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में कोताही बरतने का आरोप लगाते ही इस पर सियासी रंग चढ़ना शुरू हो गया है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को पत्र लिखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का उल्लेख करते हुए इसकी सीबीआई जांच कराने की बात कही. इससे ख़फ़ा मायावती ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर जयराम रमेश पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच से साफ़ इंकार कर दिया. राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के दौरे में ग्रामीण इलाक़ों के लोगों से बातचीत कर केंद्रीय योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की थी. इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में मायावती सरकार जानबूझ कर केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में कोताही बरत रही है, ताकि इससे केंद्र की छवि धूमिल हो. उनका यह बयान आने के बाद केंद्र ने अपनी योजनाओं को लेकर गंभीरता बरतते हुए मनरेगा निरीक्षण टीम भेज दी. टीम ने उत्तर प्रदेश के गोंडा, कुशीनगर, मिर्ज़ापुर, बलरामपुर और बहराइच ज़िलों में क़रीब पांच हज़ार करोड़ रुपये के घोटाले की बात कही. हालांकि इस योजना के क्रियान्वयन में ख़ामियों और धन के दुरुपयोग की बात राज्य सरकार ने भी स्वीकार की है. अगर पांच ज़िलों में यह हालत है तो बाक़ी 67 ज़िलों की स्थिति क्या होगी, सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है.

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले और सीएमओ हत्याकांड के मामले में चर्चित कुशीनगर के बसपा विधायक राम प्रसाद जायसवाल का नाम एक बार फिर घोटाले से जुड़ता नज़र आ रहा है. उनके भतीजे प्रदीप कुमार जायसवाल की पत्नी सावित्री कुशीनगर की ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं. सावित्री ने नियमों को ताक़ पर रखकर 30 मीटर लंबे पुल का निर्माण कराया था, जो छह महीने बाद ही टूट गया. इस पर सावित्री के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कराया गया. कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने 30 लाख रुपये जमा कराकर अपनी गर्दन बचा ली. ऐसे अनेक मामले हैं, जिनमें बसपा नेताओं ने करोड़ों के वारे-न्यारे किए हैं. सरकारी अफ़सर भी इस मामले में पीछे नहीं हैं. बाराबंकी ज़िले के गांव मजरा मीरापुर में तो एक अधिकारी ने अपने फॉर्म हाउस में पानी ले जाने के लिए 17 करोड़ रुपये से एक माइनर का ही निर्माण करा लिया. ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने इलाक़े का दौरा किया तो उन्हें बताया गया कि गांव से गुज़र रही शारदा सहायक नहर के माइनर का ज़्यादातर पानी एक अधिकारी के फॉर्म हाउस तक ही आ पाता है, जबकि उनके खेत पानी को तरस रहे हैं.

मनरेगा को गंभीरता से न लेने वाले राज्यों की फ़ेहरिस्त में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है. योजना का बजट ग़ैर ज़रूरी चीज़ों के लिए ख़र्च किया जा रहा है. प्रदेश सरकार ने मनरेगा की निगरानी के नाम पर डिजिटल कैमरों पर लाखों रुपये ख़र्च कर डाले, जबकि उनका इस्तेमाल विकास के लिए होना था. इतना ही नहीं, फ़र्ज़ी जॉबकार्ड बनाकर भी मज़दूरों के हिस्से की रक़म हड़पी जा रही है. ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं, जिनमें मज़दूर सिर्फ़ काग़ज़ों में ही काम कर रहे हैं यानी रजिस्टर में तो मज़दूरों के नाम दर्ज हैं, लेकिन कार्यस्थल पर मशीनों से काम लिया जा रहा है. मनरेगा की आदर्श जलाशय योजना के तहत बने प्रदेश के हज़ारों तालाबों में मज़दूरों की जगह जेसीबी और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करके गोलमाल किया गया. मज़दूरों को उनकी मज़दूरी का भुगतान न किए जाने के मामले भी सामने आते रहते हैं. कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि मनरेगा के धन का उपयोग खिलौने, टेंट और कैलेंडर आदि ख़रीदने में किया गया. उन्होंने कहा कि मायावती ग़लत फ़ैसलों का समर्थन करती हैं और भ्रष्टाचार को प्रश्रय देती हैं. यह योजना ग्रामीणों को रोज़गार दिलाने के बजाय नेताओं और अफ़सरों की जेबें भरने का साधन बनकर रह गई है. देश के अन्य राज्यों में भी कमोबेश यही हालत है. भाजपा शासित मध्य प्रदेश में भी मनरेगा में घोटाले के मामले सामने आए हैं. टीकमगढ़ ज़िले में मनरेगा में आठ करोड़ रुपये से ज़्यादा का घोटाला प्रकाश में आया है. फ़रवरी 2006 से जून 2009 के बीच इसमें सर्वाधिक गड़बड़ियां पाई गईं. ग्राम पंचायतों के सचिवों और सरपंचों ने बैंक से राशि तो निकाल ली, लेकिन कोई काम नहीं हुआ. यह सारी रक़म इन लोगों ने हड़प ली. इसी तरह दतिया ज़िले के गांव हथलई में कुंओं का निर्माण सिर्फ़ क़ाग़जों पर ही किया गया. इतना ही नहीं, किसानों के अधबने कुंओं को भी योजना में पूरा दर्शा दिया गया. मनरेगा के तहत पार्क एवं शमशान घाट के निर्माण का कार्य भी नहीं कराया गया. इस मामले में कांग्रेस शासित राज्य भी पीछे नहीं हैं. हरियाणा के अंबाला ज़िले में 2006 से 2009 तक मनरेगा के कार्यान्वयन पर 44 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए. वन विभाग द्वारा नारायणगढ़ खंड के लालपुर एवं हमीदपुर, साहा खंड के संभालखा, शहज़ादपुर खंड के रतौर, मानकपुर एवं बब्याल आदि गांवों में कराए गए कार्यों की जांच की गई तो वे कार्य अधूरे पाए गए, जिन्हें काग़ज़ों में पूरा दिखाया गया था. राज्य सरकार हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो से इसकी जांच करा रही है. क़ाबिले-ग़ौर यह है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए अंबाला ज़िले को बीती 2 फ़रवरी को प्रधानमंत्री का एक्सीलेंस अवॉर्ड मिला था. यह सम्मान वन विभाग और डीआरडीओ द्वारा तय समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए दिया गया था. राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले के पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामान की सप्लाई के ही 58 लाख रुपये से ज़्यादा की रक़म का भुगतान कर दिया. इसमें से ज़्यादातर रक़म का भुगतान ख़ुद को और अपने रिश्तेदारों को किया गया. मामला सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाली ग्राम पंचायत झरनी का है.

दरअसल, राजनेता भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी शासित राज्यों के भ्रष्टाचार पर ख़ामोशी अख्तियार कर लेते हैं. भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी को ही लीजिए. रथयात्रा निकालने के शौक़ीन आडवाणी भ्रष्टाचार को लेकर देश में रथयात्रा पर निकले हैं, लेकिन वह भाजपा शासित राज्यों के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुप्पी साध जाते हैं. मसलन, कर्नाटक में भूमि घोटाले में शामिल बीएस येदुरप्पा एवं अन्य भाजपा नेताओं की संलिप्तता पर वह एक शब्द तक नहीं बोलते. अगर राहुल गांधी ख़ुद को आदर्श नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों में केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान देना होगा. वहां योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में उन्हें सख्ती बरतनी होगी. ऐसा करने से जहां इन प्रदेशों में जनता का भला होगा, वहीं इससे कांग्रेस का जनाधार भी बढ़ेगा. अगर राहुल इन राज्यों में केंद्रीय योजनाओं को ठीक से लागू न करा पाए तो जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेगी.

firdaus@chauthiduniya.com

## मनरेगा क्या है

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 की शुरुआत 2 फ़रवरी, 2006 को ग्रामीण क्षेत्रों में की गई. इसका मक़सद ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इसके तहत हर परिवार के एक वयस्क सदस्य को एक साल में कम से कम 100 दिनों का रोज़गार दिए जाने की गारंटी है. इसका एक लक्ष्य टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन करना भी है. यह दुनिया में अपनी तरह का पहला अधिनियम है, जिसके तहत रोज़गार की गारंटी दी जाती है. पहले चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े ज़िलों में लागू किया गया. दूसरे चरण में वर्ष 2007-08 में इसमें 130 और ज़िलों को शामिल किया गया, जबकि एक अप्रैल 2008 से इसका विस्तार सभी शेष ग्रामीण ज़िलों तक कर दिया गया. इसका आधार अधिकार और मांग को बनाया गया, जिसकी वजह से यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया. इसके तहत समयबद्ध रोज़गार गारंटी और 15 दिनों के भीतर मज़दूरी का भुगतान करना आदि शामिल है. इसका 90 फ़ीसदी ख़र्च केंद्र सरकार वहन करती है, इसलिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे रोज़गार प्रदान करने में कोताही न बरतें. इसके अलावा इस बात पर भी ज़ोर दिया जाता है कि रोज़गार शारीरिक श्रम आधारित हो, जिसमें ठेकेदारों और मशीनों का कोई दख़ल न हो. इसमें महिलाओं की 33 फ़ीसदी श्रम भागीदारी सुनिश्चित की गई है. श्रम मद में 40 फ़ीसदी और सामग्री मद में 60 फ़ीसदी ख़र्च किए जाने की अधिकतम सीमा तय की गई है. पहले इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना था. बाद में इसका नाम बदल कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना किया गया.

## मेरी दुनिया.... आतंक से सुरक्षा

वे बुज़ुर्ग और नौजवान जिन्होंने कभी गांव नहीं देखा है या फिर अपने गांव को छोड़कर मजबूरन शहर चले गए हैं, वे इसे ज़्यादा पसंद करते हैं.



## शेखावाटी

# चलें गांव की ओर

सभी फोटो– प्रभात पाण्डेय

**क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देकर इलाक़े की तस्वीर बदलने वाले मोरारका फाउंडेशन ने फार्म पर्यटन पर भी ज़ोर दिया है. फार्म पर्यटन के ज़रिए युवा किसानों और गांवों को इससे जोड़ना और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाना ही फाउंडेशन का उद्देश्य है. इस क्रम में पर्यटकों को शेखावाटी में फार्म पर्यटन का ज्ञानवर्धक और रोचक अनुभव दिलाने के लिए कई किसान परिवारों को तैयार किया गया. लक्ष्मणा का बास के किसान राजकुमार काजला के यहां तीन दिनों के लिए ठहरने आए फ्रांस के 29 पर्यटकों ने देशी सभ्यता को क़रीब से जाना. सिंहासन के ठाकुर गिरवर सिंह के घर साल भर में फ्रांस से 65 पर्यटक आए और राजस्थानी संस्कृति को देख-समझ कर गए.**

रीतिका सोनाली

राजस्थान के झुंझनू का कठराथल गांव, दूर तक नज़र आते लहलहाते खेत, चरते पशु और रंग-बिरंगे पक्षी, कच्ची पगडंडियों के किनारे बने मिट्टी और घास-फूंस के छोटे-बड़े घर, सौंधी ख़ुशबू वाली आबोहवा और प्रकृति के प्रेम से सराबोर वातारण. इन सबके बीच सुशीला देवी और कान सिंह का घर किसी चित्रकार की कल्पना-सा प्रतीत होता है. घर की दीवारों पर सुंदर रंग-बिरंगी राजस्थानी चित्रकारी बरबस आकर्षित करती है. घर की मुंडेर पर गमलों की कतार और घर के पीछे फैले खलिहान, गांव में सैर के लिए बथान में बंधे घोड़े और सुरक्षा के लिए दो बड़े पालतू कुत्ते. इन सबमें ख़ास यहां का प्राकृतिक फ्रिज जिसे ज़मीन में ही गड्ढा कर ईंट की दीवार बनाकर छर्रे और मिट्टी से तैयार किया गया है. घर के कमरे जहां बाहर से मिट्टी के हैं, वहीं अंदर आराम का पूरा साजो-सामान है, सोफ़ा, बैड, डायनिंग टेबल और ज़मीन पर बिछी क़ालीन. यहां सुकून का ख़ास इंतज़ाम है. घर के आंगन में झूला ख़ूबसूरती में चार चांद लगाता है. यह घर किसी पेंटिंग का सजीव चित्रण लगता है. यह घर ग्रामीण पर्यटन के लोकप्रिय ठिकानों में से है. इस क्षेत्र से पिछले चार सालों से जुड़ी सुशीला देवी और उनके परिवार की ज़िंदगी ग्रामीण पर्यटन ने बदल दी है. पहले उनके पास खेतीबाड़ी के अलावा कोई और काम नहीं था. पढ़े-लिखे उनके दोनों बेटों का खेती में जी नहीं लगता था. वे शहर जाकर काम करना चाहते थे, दुनिया देखना चाहते थे, लेकिन अब दुनिया चलकर उनके पास आती है. मोरारका फाउंडेशन ने गांव में ही रहकर नए प्रकार के काम करने का आइडिया दिया, जो बच्चों को भी पसंद आया और उन्हें भी. शुरू में घर छोटा होने, सीमित संसाधन होने की वजह से समस्या भी आई, पर धीरे-धीरे सब ठीक हो गया. सुशीला देवी के बच्चे अब फाउंडेशन द्वारा दी गई ट्रेनिंग की बदौलत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं और घर आए मेहमानों को इलाक़े की सैर करवाते हैं, वहां के कला-साहित्य और दूसरी लोक कृतियों से परिचित करवाते हैं. विदेशियों के साथ संचार की कोई समस्या नहीं रह गई. विदेशी पर्यटकों को और क्या चाहिए था. घर की महिला के हाथों से बना शुद्ध पारंपरिक भोजन वह भी पारंपरिक तरीक़े से. सुशीला देवी कहती हैं कि देशी पर्यटकों में ग्रामीण पर्यटन को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है. वे बुज़ुर्ग और नौजवान जिन्होंने कभी गांव नहीं देखा है या फिर अपने गांव को छोड़कर मजबूरन शहर चले गए हैं, वे इसे ज़्यादा पसंद करते हैं. इसके अलावा हनीमून जोड़े और शहर में रहने वाले परिवार भी ख़ूब चाव से यहां ठहरते हैं.

मेहमानों को अपनी संस्कृति को अधिक क़रीब से दिखाने के लिए सुशीला देवी घर पर ही मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, लोक नृत्य, कठपुतली का खेल और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती हैं. सुशीला देवी को इस बात पर गर्व होता है कि विदेश से आने वाले लोग उन्हें सुपरवुमैन कहते हैं, क्योंकि वे सुशीला देवी के बड़े परिवार का प्रबंधन देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं. यही नहीं सुशीला देवी से मेहमान भारतीय मेहमान नवाज़ी, पशुओं का दूध काढ़ना, चारा देना और खेतों पर काम करने जैसा सुखद अनुभव भी लेकर जाते हैं. लेकिन सुशीला देवी और उन जैसे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने वाले किसान परिवारों के लिए यह सब आसान नहीं था. ग्रामीण पर्यटन के लिए गांव वालों के सामने कुछ ख़ास चुनौतियां थीं, जैसे प्रशिक्षित लोगों की कमी, आर्थिक तंगी, लोगों में उत्साह की कमी, ग्रामीण परिवेश की वजह से लोगों का अल्प विकास, सहभागिता की कमी, बिजनेस प्लानिंग क्षमता की कमी, भाषाई समस्या, बुनियादी शिक्षा की कमी, संचार का माध्यम, प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड. लेकिन मोरारका फाउंडेशन ने स्थानीय लोगों और उनके पूरे परिवार को ख़ास ट्रेनिंग दी, जिसकी वजह से सारी चुनौतियां ख़त्म हो गईं. ग्रामीण पर्यटन को राजस्थान में 500 से ज़्यादा चिन्हित परिवारों से जोड़कर मोरारका फाउंडेशन ने यहां की सभ्यता और संस्कृति को विश्व पटल पर उकेरने में बड़ी भूमिका निभाई है. पर्यावरण हित को ध्यान में रखते हुए प्रकृतिजन्य पर्यटन का विकास करवाया है. ग्रामीण समुदायों को पर्यटन का हिस्सा बनाकर उनके आर्थिक और शैक्षिक स्तर का विकास करवाया है, जिससे ग्रामीणों के शहरों की तरफ़ पलायन में कमी आ सके. काफ़ी वक़्त से ग्रामीणों की स्थिति ख़राब होती जा रही थी. इसका मुख्य कारण था कृषि की उपेक्षा, इसके प्रति लापरवाही, इसे किसी अन्य व्यवसाय के मुक़ाबले कम आंकना और युवाओं का इससे न जुड़ना. इसी समस्या को दूर करने का उपाय मोरारका फाउंडेशन ने खोज निकाला फार्म पर्यटन के ज़रिए. क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देकर इलाक़े की तस्वीर बदलने वाले मोरारका फाउंडेशन ने फार्म पर्यटन पर भी ज़ोर दिया है. फार्म पर्यटन के ज़रिए युवा किसानों और गांवों को इससे जोड़ना और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाना ही फाउंडेशन का उद्देश्य है. इस क्रम में पर्यटकों को शेखावाटी में फार्म पर्यटन का ज्ञानवर्धक और रोचक अनुभव दिलाने के लिए कई किसान परिवारों को तैयार किया गया. लक्ष्मणा का बास के किसान राजकुमार काजला के तीन दिन के लिए ठहरने आए फ्रांस के 29 पर्यटकों ने देशी सभ्यता को क़रीब से जाना. सिंहासन के ठाकुर गिरवर सिंह के घर साल भर में फ्रांस से 65 पर्यटक आए और राजस्थानी संस्कृति को देख और समझ कर गए. फार्म पर्यटन पर आए फ्रांस के 21 लोगों को बिडोदी के किसान मनोज शर्मा के यहां दो दिन के लिए ठहरना भारत से विशेष लगाव का अहसास दे गया. शेखावाटी में किसानों को पर्यटकों के स्वागत के लिए ख़ासतौर से तैयार किया गया, ताकि वे पर्यटकों के साथ अच्छी तरह संबंध बना सकें और उन्हें ठहरने के दौरान कोई परेशानी न आए. शेखावाटी क्षेत्र में मीलों का बास के हरीराम मील ने साल भर में 16 फ्रांसीसी मूल के पर्यटकों को ठहराया, तो बीदासर के किसान नेकीराम गोदारा ने कजाकिस्तान से आए दो पर्यटकों और फ्रांस से आए 16 पर्यटकों की दो दिन तक ख़ातिरदारी की. वाहिपुरा के कृष्ण सिंह शेखावत ने 11 और कल्याणपुरा के रामअवतार बुगालिया ने 19 फ्रांसीसी पर्यटकों को दो दिन में अपनी संस्कृति से रूबरू करा दिया. वहीं वाहिदपुरा के सुरेंद्र कुमार ने 4 स्विस पर्यटकों को दो दिन में ही गांव की आबोहवा का क़ायल बना दिया. पिछले कुछ सालों में हज़ारों राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को गांवों में भ्रमण कर ग्रामीण जीवनशैली को नज़दीक से जानने, समझने, परखने का मौक़ा मिला है.

मोरारका फाउंडेशन ने ग्रामीण पर्यटन द्वारा सफलता की एक नई कहानी लिखी है. इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि चूंकि केवल पर्यटन से आजीविका कमाने के अवसर बढ़ जाते हैं जिससे किसान लगातार पर्यटन के कार्य से जुड़कर कृषि जैसे स्वाभाविक और महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ने की भूल कर सकते हैं. इसी वजह से यहां फार्म पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. ग्रामीण पर्यटन से न केवल विकल्प रोज़गार के अवसर विकसित होते हैं, बल्कि कई तरह के फ़ायदे होते हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि गांववालों को आजीविका का साधन मिल जाता है, ख़ासकर ग्रामीण युवा को. इससे जीवन स्तर में सुधार आता है मसलन शिक्षा, सेहत का भी स्तर बेहतर हो जाता है. गांव में ज़मीन की क़ीमत बढ़ती है, व्यापारिक वस्तुओं और पब्लिक सेवाओं के दाम भी बढ़ते हैं. स्थानीय कारोबार जैसे क्षेत्रीय कला, ट्रांसपोर्ट और दुकानदारों इत्यादि को फ़ायदा पहुंचता है. गांव के सीधे-सादे लोग विदेशों-शहरों के समझदार लोगों से बेवकूफ़ न बन जाएं या फिर बड़े शहरों और विदेशों से आने वाले लोगों से बातचीत कर सकें, इसके लिए गांव के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है.

शेखावाटी के गांवों के लोग बड़े समझदार हैं. शहर से आने वाले लोगों से न केवल आय कमा रहे हैं, बल्कि जीने का सलीक़ा भी सीख लेते हैं. गांव के लोग स्वस्थ वातावरण के साथ सफ़ाई व्यवस्था, सड़क, बिजली, दूरसंचार के नए माध्यम और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने वाले आधुनिक उपकरण के इस्तेमाल और जीवन को सुलभ बनाने वाली तकनीकी चीज़ों से रूबरू होते हैं. इसके अलावा शहर से आए बुद्धिजीवियों से प्राकृतिक आवास, जैव-विविधता और ऐतिहासिक स्मारकों, धरोहरों का संरक्षण करने के नए उपायों के बारे में सीखते हैं और प्राकृतिक उद्यानों को सहेजने के प्रति जागरूक होते हैं. परंपराओं को सर आंखों पर रखने वाले गांव के बड़े बुज़ुर्गों को यह चिंता थी कि ग्रामीण पर्यटन से ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति को क्षति पहुंच सकती है और गांव की युवा पीढ़ी आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी संस्कृति से दूर हो जाएगी. मगर फाउंडेशन ने इस डर को दूर किया. फाउंडेशन ने सिखाया कि दरअसल गांव का परिवेश और परंपरागत चीज़ें ही उनके काम की शान हैं और इसे बढ़ावा दे सकती हैं. इस लिहाज़ से बुज़ुर्गों का यह डर भी ख़त्म हो गया कि ग्रामीण पर्यटन के विकास से गांव के परंपरागत व्यापार और उद्योग, रोज़गार और माहौल पर ग़लत असर हो सकता है. मोरारका फाउंडेशन ग्रामीण पर्यटन के प्रति इतनी अधिक रुचि और लगन से कार्य करवा रहा है कि इस क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. अगर आप भी अपने गांव को ग्रामीण पयर्टन से जोड़ना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें.

ritika@chauthiduniya.com

## गाइड ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू कराते हैं

ग्रामीण पर्यटन एवं ऊंची-ऊंची हवेलियों की वजह से नवलगढ़ राजस्थान में जाना पहचाना नाम है. हर साल तक़रीबन 30,000 राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पर्यटक न नवलगढ़ की ख़ूबसूरत हवेलियों, मंदिरों, ऐतिहासिक स्मारकों और जैविक खेती के प्रयासों को देखने समझने आ रहे हैं. यहां के गाइड इन भ्रमणीय स्थलों से पर्यटकों का जोड़ते हैं. यह गाइड पहले अप्रशिक्षित थे, कम पढ़े-लिखे थे. उनके पास समुचित विषयपरख जानकारी जुटाने का न तो कोई स्रोत था और न ही अवसर, इसलिए गाइड सुनी-सुनाई जानकारियों को अनगढ़ तरीक़े से पर्यटकों को पेश करते थे, और पर्यटक मजबूरन उनकी सेवाएं लेते थे. उपेक्षा और सरकारी नियमों की आड़ में उन्हें न तो कोई प्रशिक्षण दिया गया था और न ही कोई सुविधा मुहैया कराई गई थी. ऐसे में मोरारका फाउंडेशन ने आगे बढ़कर स्थानीय नगर पालिका से बात करके इन अप्रशिक्षित गाइडों को विधिवत शिक्षण देना प्रारंभ किया, जिसके तहत स्थानीय हैरिटेज, होटल, स्मारक पर्यटन, व्यापार से जुड़े विशेषज्ञों की मदद से 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया. इसमें नव-लगढ़ के सभी अप्रशिक्षित गाइड समुदाय ने हिस्सा लेकर और शिविर से जुड़कर नवलगढ़ के बारे में पर्यटन की दृष्टि से पूरी जानकारी प्राप्त की. यही नहीं पर्यटन से जुड़े अन्य आयामों के बारे में भी जाना. ट्रेनिंग पाकर ख़ुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे गाइड आबिद ख़ान कहते हैं कि इस प्रशिक्षण से न केवल आत्म विश्वास बढ़ा, बल्कि हम अधिकार पूर्वक पर्यटन से जुड़े विषयों पर पर्यटकों को जानकारी देने में भी सक्षम हो गए हैं. एक अन्य गाइड मनोज शर्मा का कहना है कि हैरिटेज की जानकारी तो मोरारका फाउंडेशन पहले भी हैरिटेज संरक्षण शिविर के माधयम से दे रहा है, पर पर्यटकों को ये जानकारियां किस तरह की पूरी तहज़ीब और संस्कृति के साथ दी जाएं, इसका पता इस शिविर के माध्यम से ही चला. साथ ही बहुत से अनछुए पहलुओं पर चर्चाएं भी उपयोगी सिद्ध हुई हैं. उन्हें सबसे ज़्यादा तो ख़ुशी इस बात की हुई कि अप्रशिक्षित का लेबल अब हमेशा के लिए हट गया है और वह भी अब गर्व के साथ पर्यटकों को नवलगढ़ की विरासत से रूबरू करवा रहे हैं.

वी.बी. बापना, महाप्रबंधक
मोरारका फाउंडेशन, वाटिका रोड, जयपुर- 302015
मोबाइल - 09414063458
ई मेल : vbmorarka@yahoo.com

चौथी दुनिया



करोड़ों या अरबों रुपये भारत सरकार इस तरह के टैक्सों से वसूल कर लेती है. आप आश्चर्य करेंगे कि क्या होता है इतनी बड़ी रकम का?



भारत के नए-नए वामपंथी लोग यह दिखाना चाहते हैं कि एनएसएस के प्रत्येक दौर के सर्वे के बाद यहां ग़रीबों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती है.

चौथी दुनिया





महावीर प्रसाद आर मोरारका

# करों द्वारा प्राप्त सरकारी आय

बाज़ार से ली गई खाद्यादि सामग्रियों के सिवाय आप बहुत सा और दैनिक ख़र्च भी करते हैं. टेलीफोन का किराया, बिजली का चार्ज, पानी का चार्ज इत्यादि आप देते हैं. मकान भाड़े में नगरपालिका के कर आपको देने पड़ते हैं. बहुत से नागरिक इन करों को अनावश्यक और व्यर्थ समझते हैं और देने में बड़ी आनाकानी करते हैं अथवा दु:खी होते हैं. पर ग़ौर करने पर ज्ञात होगा कि नगरपालिका द्वारा लगाए गए टैक्स कितने उपयोगी हैं और आपको उसका कितना ज़्यादा मुआवज़ा मिलता है. सड़कें, उनके दोनों तरफ़ फुटपाथ, सड़क की बिजलियां, पानी के नल, गटर इत्यादि कितनी ही सुविधाएं नगरपालिका द्वारा संचालित हैं. यह सब आपके, हमारे द्वारा दिए गए हाउस टैक्स से ही संभव हो सकता है. ये सुविधाएं देखते ही टैक्स देने वालों को ज़रूर संतोष का अनुभव होता है. नगरपालिकाएं ये तमाम काम लागत क़ीमत पर ही करती हैं. कोई मुनाफ़ा अपने लिए नहीं रखतीं. इसी तरह आयकर इत्यादि जो कर दिए जाते हैं, उनके संबंध में भी कहा जा सकता है कि उनसे भी जनता को उसके मूल्य जितनी सुविधाएं मिल जाती हैं. ये सब देख-जानकर ज़रूर ही आपके मन में जाएगा कि अगले साल जब इनकम टैक्स ऑफिसर टैक्स का निर्धारण आदेश भेजेंगे तो आपको फ़ौरन टैक्स देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए. दु:ख है, आपको इस स्थिति का संपूर्ण ज्ञान कराते हुए कि इन हाउस टैक्स या इनकम टैक्स इत्यादि टैक्सों में से भी, नगरपालिकाओं या सरकार से भी पूंजीवादी हमेशा अपना हिस्सा हड़प ही लेते हैं. आपको आश्चर्य होता होगा कि यह कैसे होता है? उसी तरह, जब ज़मीन और पूंजी निजी संपत्ति है तो सब नगर पालिकाओं को और सरकार को कुछ न कुछ ख़रीदना ही पड़ता है, जिसमें इन पूंजीपतियों के मुनाफ़े का भाग सम्मिलित होता ही है. नगरपालिकाएं सड़कों पर रोशनी के लिए बिजली के बल्ब ख़रीदेंगी ही. वे उन्हीं निजी संपत्ति वालों से तो ख़रीदने पड़ेंगे. इसी तरह सैकड़ों हज़ारों चीजें नित्य नगरपालिकाओं और सरकार को ख़रीद भी करनी होती हैं और हर एक में उन पूंजीपतियों का साझा निश्चित है. इस तरह से हाउस टैक्स या अन्य टैक्सों में से भी बहुत बड़ा भाग इन पूंजीपतियों की जेब में चला ही जाता है.

इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार धनिकों पर ज़्यादा दर पर टैक्स लगाती है, ग़रीबों पर कम दर पर या बिल्कुल नहीं. इन्हीं टैक्सों की वजह से अपनी कमाई का आधा या दो तिहाई हिस्सा धनिकों को हर साल सरकार के सुपुर्द कर देना पड़ता है. इसके बदले में इन धनिकों को कोई विशेष सुविधा सरकार या राष्ट्र नहीं देता तो भी सिर्फ़ उन धनिकों की आय का आधा या दो तिहाई भाग का एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण ही है. शुरू-शुरू में इस तरह संपत्ति हड़प लेना इनको बहुत बुरा लगा था, पर अब तो यह व्यवस्था आदतन इतनी स्वाभाविक बन गई है कि कोई भी इसकी चर्चा नहीं करता. हर साल फरवरी के आख़िरी दिन वित्त मंत्री संसद में नया क़ानून बना देते हैं. उसके अनुसार, आयकर, सुपर कर या अन्य कई तरह के कर जनता से लिए जाते हैं. इस सालाना क़ानून का नाम है वित्तीय क़ानून. पर असल में है यह निर्धनीय क़ानून, क्योंकि इस क़ानून द्वारा हर साल जनता का वित्त उससे लिया जाता है. भारत के संविधान में या और किसी क़ानून अथवा किसी रिवाज में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है. यह आधा या दो तिहाई तक है. उसे 90 प्रतिशत, 99 प्रतिशत या पूरा का पूरा टैक्स कर दिया जाए तो भी कोई रोकने वाला नहीं है. सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि कौन-कौन से व्यक्तियों पर कितना-कितना कर लगना चाहिए. सब लोगों पर समान दर से ही टैक्स लगाया जाए, यह कतई ज़रूरी नहीं है. यही एक तरीक़ा, जो राष्ट्र ने अपनाया है, समान वित्त वितरण की दिशा में पहला क़दम है. इन प्रत्यक्ष करों के अलावा परोक्ष कर भी हैं, जैसे बिक्री कर, ख़रीदी कर, उत्पाद शुल्क आदि. ये कर ग़रीब-अमीर सब पर समान रूप से लागू हैं. ये टैक्स विशेष सेवा के लिए नहीं होते, ये तो राष्ट्र की आय बनाने के साधन मात्र हैं. या यों कहें, सबसे सबके लिए कुछ ले लिया जाता है. यही साम्यवाद है.



करोड़ों या अरबों रुपये भारत सरकार इस तरह के टैक्सों से वसूल कर लेती है. आप आश्चर्य करेंगे कि क्या होता है इतनी बड़ी रकम का? सरकार इन्हीं के द्वारा आपकी, हमारी रक्षा के लिए सेना का ख़र्च चलाती है. फौज, पलटन, नौसेना, वायुसेना, न्यायालय-कचहरियां इत्यादि जो-जो सुविधाएं आपको, हमको प्राप्त हैं, वे सब इन्हीं की तो बदौलत हैं. इस तरह इन क़ानूनों से सरकार सिर्फ़ वित्त का पुनर्वितरण करती है. धनिकों से कुछ अधिक लेती है, ग़रीबों से कम, बिल्कुल ग़रीबों से नहीं के बराबर लेती है और सबको समान रूप से बांट देती है. पाने वाले के गुण-दोष कुछ भी नहीं देखे जाते. सबको उचित रूप से प्राप्त हो जाता है. इस कार्य में भी कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है. सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी हद तक इस वितरण को या इसी तरह वित्त संग्रह को अमल में ला सकती है. आप वे दिन भूले नहीं होंगे, जब आयकर की दर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा रुपये में एक आना थी. ज़्यादा से ज़्यादा आय वाला व्यक्ति भी अपनी कमाई के सोलहवें हिस्से से ज़्यादा देने के लिए उत्तरदायी नहीं था. उस वक्त कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचा गया था कि टैक्स का उद्देश्य किसी जमाने में समान वित्त वितरण का क़दम हो जाएगा. इसके अलावा हर वर्ष राष्ट्र को बहुत बड़ी रकम ब्याज के रूप में देनी पड़ती है. 10-20 या 50 वर्ष पहले जब-जब राष्ट्र पर महायुद्ध या ऐसी ही कोई विपत्ति आई होगी, तब-तब राष्ट्र ने जनता से उधार रुपया लिया था. आप जानते हैं उधार देने वाले वे ही पूंजीपति लोग होते हैं, जिनके पास अपनी ज़रूरत के अलावा कुछ बचा हुआ होता है. जब राष्ट्र ने रुपये उधार लिए थे, तब 3 या 4 प्रतिशत ब्याज देने का क़रार किया गया था. आज हर वर्ष सरकार जो टैक्स का संग्रह करती है, उसमें से एक बहुत बड़ा भाग इस ब्याज को चुकाने में लगता है. यह ब्याज इन्हीं धनिकों की जेबों या कोषों में जाता है. जब यह रकम उधार ली गई थी, तब वे तमाम वस्तुएं भी इन पूंजीवादियों ने ही बेची थीं, जिनमें प्रत्येक का मुनाफ़ा सम्मिलित था. बाद में हर वर्ष ब्याज भी यही लोग लेते रहते हैं. कहने का तात्पर्य यही है कि निजी संपत्ति होने की वजह से आज भी टैक्स का अच्छा-खासा भाग घूम-फिरकर फिर इन्हीं पूंजीपतियों के यहां चला जाता है.

feedback@chauthiduniya.com

*महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.*



## कमल मोरारका का ब्लॉग

www.kamalmorarka.com

# लोकपाल समस्या का समाधान नहीं है

जब हमने समाज में सुधार के लिए संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया है तो फिर इसके लिए किसी तरह की कोई जल्दबाज़ी करने की आवश्यकता नहीं है. हमें सांसदों और विधायकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयास करना है, जिससे शासन की गुणवत्ता में सुधार होगा. अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार को एक बड़ी समस्या माना है और इस पर अंकुश लगाने के लिए लोकपाल का सुझाव दिया है, लेकिन यह सुझाव कोई आदर्श सुझाव नहीं है. भ्रष्टाचार रोकने के लिए देश में कई संस्थाएं हैं और किसी अन्य संस्था की ज़रूरत भी नहीं है. जब लोकपाल का गठन होगा तो सैकड़ों-हज़ारों अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और देश को एक दूसरी नौकरशाही का सामना करना पड़ेगा. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले विभागों में से किसी को समाप्त करने के बाद लोकपाल बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा. भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सैकड़ों नए पद सृजित करना कोई समझदारी का काम नहीं है.

प्रधानमंत्री स्वयं लोकपाल हैं. उन्हें भ्रष्टाचार में संलिप्त किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए. इसके लिए किसी तरह की जांच-पड़ताल या सबूत की आवश्यकता नहीं है. अगर उन्हें लगता है कि कोई मंत्री ठीक से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है या किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसे तुरंत पद से हटा देना चाहिए. मंत्रियों की नियुक्ति आईएएस अधिकारियों की तरह किसी प्रतियोगिता के माध्यम से नहीं होती है. उन्हें तो प्रधानमंत्री इस विश्वास के साथ नियुक्त करते हैं कि वे शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने में अपना योगदान करेंगे. अगर वे सही तरीक़े से शासन चलाने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें पद से ज़रूर हटा देना चाहिए. प्रधानमंत्री के संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश लोकपाल हो सकते हैं. देखा जाए तो न्यायालय के पास प्रधानमंत्री के विरुद्ध कितनी शिकायतें जाती है? अगर शिकायतें जाएं तो मुख्य न्यायाधीश उन्हें देख सकते हैं, उन पर विचार कर सकते हैं और अगर सही लगे तो उन पर निर्णय भी ले सकते हैं. अन्ना हजारे इसे नहीं समझ रहे हैं. सरकार एक नई संस्था बनाकर केवल ख़ुश हो सकती है और कुछ नहीं. इसमें बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी सरकार लोकपाल बिल लाएगी. एक और संस्था उसी तरह से अप्रभावी साबित होगी, जैसे कि देश की अन्य संस्थाएं. अन्ना हजारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपनी प्रबोधक शक्ति का इस्तेमाल सत्ता में बैठे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए करना चाहिए. वे सादा जीवन-उच्च विचार को अपना कर एक उदाहरण पेश कर सकते हैं, जिस पर लोग अमल कर सकें. मौजूदा समय में भारतीय व्यवसायी पश्चिम का अनुकरण कर उच्च जीवनशैली अपना रहे हैं और निजी विमानों का उपयोग करते हैं. भारतीय नेता भी ऐसा ही करना चाहते हैं. वे ऐसी सुविधाओं का उपभोग करना चाहते हैं, जो उनके लिए नहीं हैं. जनता शिकायत करती है कि इस ग़रीब देश में भी विधायकों एवं सांसदों को मुफ्त सरकारी आवास, यात्रा भत्ता और अच्छा वेतन दिया जाता है. इसके बावजूद देखा जाए तो 1990 के बाद से नेता इन सुविधाओं से ख़ुश नहीं हैं. वे व्यवसायियों की तरह ब्रांडेड वस्तुएं इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने विमानों से यात्रा करना चाहते हैं, जो उनका अधिकार नहीं है. सामान्य सी बात है कि अगर वे व्यवसायियों के ऐसे व्यवहारों का समर्थन करते हैं तो फिर किस तरह आप इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे. न्यायालय को इसके लिए हस्तक्षेप करना है, ताकि ऐसे मंत्रियों और व्यवसायियों को जेल भेजा जा सके. अन्ना हजारे की किसी भी मांग में ये सारी चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक कॉरपोरेट और नेताओं के बीच साठगांठ समाप्त नहीं होगी, कोई लोकपाल कुछ नहीं कर सकता है. वह भी अन्य संस्थाओं की तरह असफल हो जाएगा.

**मौजूदा समय में भारतीय व्यवसायी पश्चिम का अनुकरण कर उच्च जीवनशैली अपना रहे हैं और निजी विमानों का उपयोग करते हैं. भारतीय नेता भी ऐसा ही करना चाहते हैं. वे ऐसी सुविधाओं का उपभोग करना चाहते हैं, जो उनके लिए नहीं हैं.**

feedback@chauthiduniya.com

# पाठकों की दुनिया

## सर्वश्रेष्ठ पत्र

### अत्याचार से कब मुक्ति मिलेगी

भारत में एक ओर नारी की पूजा होती है, दूसरी ओर उसे डायन कहकर मौत के घाट उतार दिया जाता है. आख़िर यह सब कब तक चलता रहेगा? महिलाओं को इस अत्याचार से कब मुक्ति मिलेगी? पुरुषों में कोई डायन क्यों नहीं होता है? पुरुष प्रधान समाज में कोई भी महिला आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती. जो ऐसा करती है, उसे डायन क़रार दिया जाता है. एक महिला को डायन कहकर मारने वाले पुरुष यह क्यों भूल जाते हैं कि उनकी मां-बहनें भी तो महिलाएं हैं. सामाजिक और सरकारी तौर पर इससे रोकने का प्रयास जारी है, लेकिन सफलता तब तक नहीं मिलेगी, जब तक महिलाएं अत्याचार सहती रहेंगी, आवाज़ नहीं उठाएंगी.

*-सुषमा सिंह,* संत नगर, दिल्ली.

### लोकतंत्र की अवहेलना

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कुछ लोग ख़ुद को लोकतंत्र का विकल्प साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर राजनीति में कुछ गिरावट आई है तो हम उसे सुधार सकते हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं कि लोकतंत्र के समकक्ष कोई दूसरा तंत्र खड़ा कर लिया जाए. ऐसा करना देश हित में नहीं होगा और गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. अभिव्यक्ति के नाम पर राष्ट्र के मूल सिद्धांतों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी. **-कुणाल कुमार,** *मधुबनी, बिहार.*

### विरासत ख़त्म करने की कोशिश

देश में अब ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक विरासत को सैरसपाटे के अड्डों में बदलने की कोशिश की जा रही है. अमृतसर के जलियां वाला बाग़ भी इस एजेंडे से बाहर नहीं है. केंद्र सरकार पांच करोड़ रुपये की लागत से इसे आधुनिक बनाना चाहती है. परिसर स्थित कुएं के चारों तरफ़ मार्बल लगाकर इसकी प्राचीनता को ढक दिया गया. दीवारों में मौजूद गोलियों के निशान भी छुपाने की कोशिश की गई. देशभक्तों के ख़ून से रंगे इस स्थान को पिकनिक स्थल बनाने का प्रयास किया गया. यहां होने वाली सभाओं, जुलूस और अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई. यहां देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं. इसके मूल रूप को बदलना का उचित नहीं है. **-प्रेम सिंह,** *ई-मेल से*

### ऐसी निष्पक्षता नहीं देखी

चौथी दुनिया की नई पाठक हूं. समस्त लेख बहुत स्तरीय और सारगर्भित लगे. लेखों ने यह कहने पर मजबूर कर दिया कि आपके अख़बार जैसी निष्पक्षता कहीं नहीं देखी. साधारण बोलचाल की भाषा में लिखा गया लेख-प्रधानमंत्री जी, इस्तीफ़ा मत दीजिए ने राजनीतिक पक्ष एवं उसके गैर ज़िम्मेदाराना रवैये पर सोचने को मजबूर कर दिया. लेखों में मानवीय पीड़ा को दर्शाया गया है, न कि धर्म को पक्ष-विपक्ष समझ कर रखा गया. आज ऐसी ही निष्पक्षता की ज़रूरत है.

**-हुैरन फ़ैयाज़,** *बिजनौर, उत्तर प्रदेश.*

### आधुनिक शिक्षा ज़रूरी

देश में लगभग 20 फ़ीसदी मुस्लिम आबादी है. इस लिहाज़ से विधानसभाओं, लोकसभा, सरकारी नौकरियों और प्रशासनिक अमले में भी आबादी के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए. मुसलमानों का आधुनिक तालीम और सियासी एवं आर्थिक क्षेत्र में कम रुझान होना इसका सबसे बड़ा कारण है. इसलिए मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा पर ध्यान देना होगा.

**-मो. रफ़ीक़ चौहान,** *ई-मेल से.*

### विश्वसनीयता पर सवाल

सत्ताधारी यूपीए के बाद भारतीय जनता पार्टी भी भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में है. भाजपा शासित कर्नाटक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ी. भाजपा की विश्वसनीयता न केवल आम जनता, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच भी कम हुई है. पार्टी में व्यक्तिवाद हावी है. नेताओं के लिए प्रधानमंत्री पद पाना मुख्य लक्ष्य बन गया है. प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर आडवाणी बनाम मोदी का द्वंद्व चल रहा है. भाजपा और आरएसएस अन्ना के सहारे चुनावी नैया पार लगाना चाहते हैं.

**-प्रताप नारायण सिंह,** *बेगूसराय, बिहार.*

### अन्ना को समर्थन का अर्थ

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-संघ ने अन्ना का सबसे बड़ा नुक़सान किया, पढ़ा. यदि कोई संगठन अन्ना को समर्थन देता है तो इससे अन्ना का उससे संबंध कैसे सिद्ध हुआ? भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम को समर्थन देने का अधिकार हर व्यक्ति-संगठन को है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता कि अन्ना का उससे गठजोड़ है.

**-अमित,** *ई-मेल से.*

राजकमल प्रकाशन समूह

राजकमल प्रकाशन राधाकृष्ण लोकभारती प्रकाशन

**चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.**

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

**पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :**

**चौथी दुनिया**

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

ई मेल : feedback@chauthiduniya.com



संतोष भारतीय

## जब तोप मुक़ाबिल हो

# जस्टिस काटजू की बातों पर हंगामा क्यों

आख़िर जस्टिस काटजू ने ऐसा क्या कह दिया कि दिल्ली में तूफ़ान खड़ा हो गया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने महान सरदार हैं, वे सब तन कर खड़े हो गए, जैसे लगा कि उनका बलात्कार होने वाला है और उन्हें अपनी इज्ज़त की रक्षा करनी है. जस्टिस काटजू ने जो कहा, उसे इस देश का हर आदमी सही मानता है, क्योंकि पत्रकार की ज़िम्मेदारी किसी भी सिपाही, किसी भी डॉक्टर और किसी भी न्यायाधीश से कम नहीं होती. पत्रकारिता एक ऐसा हथियार है, जिससे हर बुराई का सामना किया जा सकता है. पत्रकारिता विश्वास का वह संबल है कि जब कहीं भी आशा न रहे तो लोग पत्रकार के पास जाते हैं और ऐसे में अगर पत्रकार पैसे लेकर ख़बरें छापने लगे, अगर पत्रकारों के नेता अपने संवाददाताओं से कहें कि तुम हमारे लिए इतनी उगाही करके लाओ तथा टेलीविजन पर बैठने वाले लोग मूर्खता भरी बातें करें तो फिर जस्टिस काटजू अगर प्रधानमंत्री को पत्र न लिखें तो क्या करें? जस्टिस काटजू ने लिखा है कि पत्रकारों को समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र की जानकारी होनी चाहिए और यह सिर्फ़ शास्त्रीय जानकारी नहीं होनी चाहिए. समाज में क्या चल रहा है, समाज में क्या कैसे घटता है, समाज में अंतर्विरोध कैसे पैदा होते हैं, समाज में कौन सी शक्तियां किन शक्तियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं, समाज में कौन दबाता है और कौन दबता है, समाज में कौन विद्रोह करता है, व्यक्ति विद्रोह क्यों करता है, विद्रोह करने के लिए कौन लोग उकसाते हैं और क्या विद्रोह सत्य पर आधारित होता है या नकली कारणों पर, यह सारी जानकारी अगर एक पत्रकार को नहीं है तो वह पत्रकारिता के क्षेत्र में रहने लायक नहीं है. वैसे तो हर प्रोफेशन में काफ़ी भीड़ होती है, जो किसी न किसी तरह अपना स्थान बना लेती है और गीदड़ की तरह हुंआ-हुंआ कहकर अपने को शेर होने का भ्रम पैदा करती है, लेकिन वह भ्रम उस दिन टूट जाता है, जब असली शेर सामने आ जाता है.

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथी अपनी ग़लती को देखना नहीं चाहते हैं. मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सरदारों में अधिकांश ऐसे हैं, जिन्हें हिंदुस्तान के सामाजिक बदलाव के इतिहास की जानकारी ही नहीं है, जिन्हें हिंदुस्तान में परिवर्तन की प्रक्रिया का सामान्य ज्ञान भी नहीं है. उसके फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को तो दूर जाने दीजिए, उन्हें यह पता नहीं है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में वे कौन से देश थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज यहां तक पहुंचा दिया, जहां पर हम खड़े होकर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं. ये सारे लोग भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने की बात करते हैं. इनके लिए लोगों के दु:ख-दर्द, तकलीफ़, आंसू, बीमारी, भूख और मौत, यह सब कुछ टीआरपी है. अगर किसी चीज़ से टीआरपी नहीं मिलती तो ये टेलीविजन में उसे जगह नहीं देना चाहते हैं. इसलिए उनकी ख़बरों में बिहार ग़ायब है, उड़ीसा ग़ायब है, बंगाल ग़ायब है, नॉर्थ-ईस्ट ग़ायब है और दक्षिण भारत तो पूरा ग़ायब है. दिल्ली में बैठकर ये अपने को महान संत समझते हैं.

आज जस्टिस काटजू ने तालाब में पत्थर फेंका है. हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस पत्थर की प्रतिक्रिया इतनी भयानक होगी. दरअसल, प्रधानमंत्री को उनका पत्र लिखना लोगों के मन की तकलीफ़ को शब्दों में बांधना है. बस एक पत्थर से हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सरदार डरते हैं. उन्हें लगा कि उनके ऊपर कुछ अंकुश आ जाएगा. जस्टिस काटजू अगर कहते हैं कि पत्रकारों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए तो क्या ग़लत कहते हैं, क्योंकि अगर यह ज्ञान नहीं होगा तो आप ख़बरों को नौकरी बनाएंगे. अगर आपको यह ज्ञान नहीं होगा तो आपके लिए उड़ीसा, बिहार एवं मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाक़े और राजस्थान, ये सब विषय होंगे ही नहीं, आप प्राइम टाइम में हीरो-हीरोइन और फिल्मों के बारे में बात करेंगे. प्राइम टाइम में जब सारे लोग टेलीविजन को टकटकी बांधकर देखते हैं, उस समय आप उन्हें बहकाने वाले शो के प्रोमोज़ चलाएंगे और इतना ही नहीं, पैसा लेकर किसी भी घटना की अच्छाई या बुराई के बारे में बात करेंगे. मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि इन सब बातों से दर्द होता है. दर्द इसलिए होता है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो पत्रकारिता को पत्रकारिता की तरह जीना चाहते हैं, जो पत्रकारिता को लोगों के दु:ख-दर्द का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जो पत्रकारिता को इस देश को बदलने का हथियार बनाना चाहते हैं.

**इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथी अपनी ग़लती को देखना नहीं चाहते हैं. मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सरदारों में अधिकांश ऐसे हैं, जिन्हें हिंदुस्तान के सामाजिक बदलाव के इतिहास की जानकारी ही नहीं है, जिन्हें हिंदुस्तान में परिवर्तन की प्रक्रिया का सामान्य ज्ञान भी नहीं है. उसके फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को तो दूर जाने दीजिए, उन्हें यह पता नहीं है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में वे कौन से देश थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज यहां तक पहुंचा दिया, जहां पर हम खड़े होकर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं. ये सारे लोग भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने की बात करते हैं.**

यह मैं किसी कमिटेड जर्नलिज्म की बात नहीं कर रहा हूं. मैं किसी भारतीय जनता पार्टी या वामपंथी पार्टी के अख़बार जैसी पत्रकारिता की बात नहीं कर रहा हूं. मैं उस पत्रकारिता की बात कर रहा हूं, जिसके वाहक गणेश शंकर विद्यार्थी, गांधी जी, पराड़कर जी, अज्ञेय जी, धर्मवीर भारती और सुरेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोग थे. आज के बौने लोग ऊंची एड़ी की सैंडिल पहन कर, चाहे वे लड़के हों या लड़कियां, टेलीविजन के सामने बैठते ही लगता है कि जैसे उनके मुंह में सरस्वती का वास है. वे इस तरह बोलते हैं कि देश का हर आदमी हंसता है. कोई भी टेलीविजन की ख़बरों पर भरोसा नहीं करता है. अगर कहीं कोई घटना घटती है और ये उसका लाइव दिखा रहे होते हैं, फिर भी हम उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि विश्वास का हनन ख़ुद टेलीविजन पत्रकारिता ने हिंदुस्तान में कर दिया है.

मैं जब टेलीविजन पत्रकारिता की बात करता हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि प्रिंट में सारे लोग ठीक हैं. प्रिंट में भी इसकी एक प्रतिस्पर्धा चल रही है. यहां भी वे चीजें कहीं नहीं दिखतीं, जिनसे लोगों की ज़िंदगी का रिश्ता हो. जिस तरह टेलीविजन वाले ग़रीबों के चेहरे को नहीं दिखाते कि सुंदर चेहरा न होने पर लोग चैनल बदल देंगे, वे एफ टीवी या एम टीवी पर चले जाएंगे, उसी तरह इन अख़बारों को लगता है कि अगर सुंदर-सुंदर चीजें प्रकाशित नहीं करेंगे और ग़रीबी की दास्तान प्रकाशित करेंगे तो लोग हमारा अख़बार नहीं ख़रीदेंगे. इससे बड़ी बेवक़ूफी और क्या हो सकती है. इसलिए देश के लोग विकल्प की तलाश में हैं. वह विकल्प की तलाश ही अख़बारों की साख कम कर रही है, टेलीविजन की साख कम कर रही है और पूरी पत्रकारिता की साख कम कर रही है और दूसरी तरफ देश की आम जनता बैठकर आपस में ऐसी ही प्रतिक्रियाएं एक-दूसरे से बांटती है. जस्टिस काटजू ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में ये तमाम चीजें व्यक्त की हैं. पत्रकारिता में रहने वाले लोग सोचें कि उन्हें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह की ख़बरें सामने लानी चाहिए. उन्हें सोचना चाहिए कि जिन चीजों को वे दिखा रहे हैं, वे लोगों के मन पर कितना ग़लत असर डाल रही हैं और इसलिए वह दिन दूर नहीं लगता, जब पत्रकारों को पकड़-पकड़ कर लोग सड़कों पर धकियाएंगे, इसलिए नहीं कि पत्रकार ने कोई सही चीज़ लिखी है, बल्कि इसलिए कि पत्रकार ग़लत चीजें क्यों लिख रहे हैं.

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र से कम से कम हम सहमत हैं. अगर किसी ख़बर में, किसी रिपोर्ट में और किसी स्टोरी में उसका सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण न हो तो वह बेकार है. अगर लिखने वाले को यह समझ न हो कि वह जो लिख रहा है, उसका देश से कोई रिश्ता है या नहीं अथवा वह जो रिपोर्ट कर रहा है, उससे कहीं ऐसा तो नहीं कि दंगा भड़क जाएगा. अगर वह इन चीजों को नहीं समझता तो उसे पत्रकारिता में आने से रोकना चाहिए. हम जस्टिस काटजू की भावना से भी सहमत हैं और उनके लिखे पत्र से भी. हम आशा करेंगे कि जो बहस जस्टिस काटजू ने शुरू की है, वह ईमानदार तरीके से चलेगी और उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट, कोई सार्थक नतीज़ा हमारे सामने आएगा. इस बहस में देश की जनता को भी शामिल होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है.

**संपादक**

editor@chauthiduniya.com



मेघनाद देसाई

# भारतीय राजनीति का खालीपन

पिछले साल दीवाली के समय अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे. ओबामा के जाने के आधे घंटे के भीतर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को आदर्श हाउसिंग घोटाले में संलिप्तता के कारण त्यागपत्र देना पड़ा. इसके लिए सोनिया गांधी ने चव्हाण को मजबूर किया था. अगर ज्योतिष पर विश्वास किया जाए तो इस दीवाली में भी कांग्रेस अथवा यूपीए में कुछ परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसके कोई चिह्न दिखाई नही पड़ा. कुछ लोग कह सकते हैं कि यूपीए के दूसरे कार्यकाल में सरकार की उसी टीम को क्या हो गया, जिसने प्रथम कार्यकाल में अच्छा काम किया था. अभी यूपीए सरकार की कैबिनेट में तीन ऐसे लोग हैं, जो वित्तमंत्री रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही है. आरबीआई महंगाई कम करने के लिए लड़ने वाली एजेंसी बनकर रह गया है. पिछले एक साल से कांग्रेस के प्रवक्ता कहते आ रहे हैं कि अगले छह महीनों में इस बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा. इसके अलावा अन्ना हजारे का मुद्दा है, जो अप्रैल में शुरू होकर अगस्त महीने में फिर से चर्चा में रहा था. कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जिसके बारे में कहा जा सके कि जिस बात की मांग अन्ना हजारे कर रहे हैं, उस पर वह बिल्कुल खरा उतरता है. न केवल कांग्रेस, बल्कि किसी भी दल में वैसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है. अन्ना हजारे के आसपास जो पांच-दस लोग हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. किरण बेदी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इस बात पर गौर करना चाहिए कि राजा एवं कनिमोई द्वारा किया गया भ्रष्टाचार और किरण बेदी के भ्रष्टाचार में काफी अंतर है. एक तरफ हजारों करोड़ का घोटाला है तो दूसरी तरफ मामला कुछ सौ अथवा हजार रुपयों का है. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही है और जो थोड़ा-बहुत भ्रष्टाचार कम भी हुआ है, उसके लिए सरकार को श्रेय नहीं दिया जा सकता है.

कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि भाजपा की स्थिति भी कुछ ठीकठाक नहीं है. कांग्रेस को तो भाजपा की प्रशंसा करनी चाहिए, न कि उस पर हमला, क्योंकि भाजपा के कारण ही उसे लाभ होता रहा है. जनता के पास कोई चारा ही नहीं होता है. कहा जा सकता है कि एक तरफ नागनाथ तो दूसरी तरफ सांपनाथ, ऐसे में जनता करे तो क्या करे. लालकृष्ण आडवाणी रथयात्रा कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में येदुरप्पा सहित कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं. आरएसएस ने भाजपा का कार्यभार संभाल लिया है. उसने एक तरफ तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया, वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी को लोकसभा सदस्य बनाने की बात भी कर दी. इसके बाद गडकरी को इस बात पर विचार करना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री पद पर मोदी की दावेदारी को कैसे रोका जाए. जिन्हें सारी बातों की जानकारी नहीं है, वे इस बात पर संदेह कर सकते हैं कि कहीं कांग्रेस ने भाजपा को कमजोर करने के लिए आरएसएस को रिश्वत तो नहीं दे दी है, लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं कि आरएसएस किसी तरह के प्रोत्साहन के बगैर भी ऐसा कर सकता है. बहरहाल, भारतीय राजनीति में एक भयावह खालीपन पैदा हो गया है. भारत को अपनी विकास दर सात फीसदी से ऊपर रखनी होगी, तभी वह अपने परमाणु रिएक्टर सही तरीके से बना सकता है और साथ ही पाकिस्तान की हरकतों को निष्प्रभावी कर सकता है, लेकिन सरकार के कारनामों से डर सा लगता है. 32 रुपये प्रतिदिन कमाने वालों को बीपीएल के अंतर्गत न मानने वाला मामला इस बात का प्रमाण है. भारत के नए-नए वामपंथी लोग यह दिखाना चाहते हैं कि एनएसएस के प्रत्येक दौर के सर्वे के बाद यहां गरीबों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती है. इनमें से कई अमीर हो सकते हैं. कई इतने अमीर हैं जो कर भी देते हैं, लेकिन जब उनके सामने 32 रुपये प्रतिदिन सरीखे मामले आते हैं तो उनका दिल बैठ जाता है. वे अपने देश की तरक्की देखना चाहते हैं. साथ ही यह भी महसूस करते हैं कि भारत की दुर्दशा के लिए कुछ लोग ही जिम्मेदार हैं. आजकल जो हो रहा है, उसके लिए केवल सरकार को दोषी बताया जाता है, लेकिन यह सही नहीं है. अगर सरकार को सही करना है तो यहां के नागरिकों को यह सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से सरकार अच्छा कर सकती है. इसके लिए जनता को ही पहल करनी होगी. देखा जाए तो कांग्रेस में अच्छे नेतृत्व का अभाव नहीं है. अभी भी कांग्रेस में भाजपा से अधिक अच्छे नेता हैं, लेकिन क्या कांग्रेस आंतरिक लोकतंत्र को समाप्त करने पर तुली नहीं है. ऐसा न होता तो राहुल गांधी के अलावा किसी और के विषय में भी बात की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है. दूसरी तरफ यहां की जनता भी अगर राहुल गांधी के उत्तराधिकार की बात स्वीकार करती है तो फिर क्या किया जा सकता है. भारत के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री देश से बाहर रहते हैं तो उस समय कैबिनेट की बैठक में उनकी जगह पर कौन होता है. चुप रहना हमेशा अच्छा नहीं होता है. कभी-कभी यह काफी घातक होता है.

**अगर सरकार को सही करना है तो यहां के नागरिकों को यह सोचना पड़ेगा कि किस तरीक़े से सरकार अच्छा कर सकती है. इसके लिए जनता को ही पहल करनी होगी. देखा जाए तो कांग्रेस में अच्छे नेतृत्व का अभाव नहीं है. अभी भी कांग्रेस में भाजपा से अधिक अच्छे नेता हैं, लेकिन क्या कांग्रेस आंतरिक लोकतंत्र को समाप्त करने पर तुली नहीं है. ऐसा न होता तो राहुल गांधी के अलावा किसी और के विषय में भी बात की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है.**



feedback@chauthiduniya.com

क़ब्र और आसपास के कमरों में भिन्न-भिन्न प्रकार की लाइटें लगाने के साथ-साथ वातावरण शुद्ध रखने के लिए फूलों-फलों से युक्त एक बगीचा भी लगाया गया है.



सूचना का अधिकार जानने का अधिकार जीने का अधिकार चौथी दुनिया की पहल

# आपके सवाल, समस्या और समाधान

चौथी दुनिया का आरटीआई अभियान जन-जन तक पहुंच रहा है, इसका सबूत हैं पाठकों के पत्र. हमारे पाठक और आम जन अपनी समस्याएं अब हमसे बांटने लगे हैं. यह अच्छी बात है कि देश का आम नागरिक अब जागरूक हो रहा है, सतर्क है और सवाल पूछ रहा है. यह शुभ संकेत है, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए. हम अपने पाठकों को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे इसी तरह अपनी प्रतिक्रियाओं एवं समस्याओं से हमें अवगत कराते रहेंगे. इस अंक में हम अपने कुछ पाठकों के पत्र शामिल कर रहे हैं, जिनमें अलग-अलग तरह की समस्याओं का जिक्र है और जिनके बारे में जानना अन्य लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा. इसके अलावा हम इस अंक में स्ट्रीट लाइट के संबंध में एक आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपनी गली-मोहल्ले में ख़राब पड़ी स्ट्रीट लाइट ठीक कराने के लिए कर सकते हैं. आगामी अंकों में भी हम आपकी समस्याओं का इसी तरह समाधान बताएंगे. आप आरटीआई क़ानून का जमकर इस्तेमाल करते रहिए.

## पाठकों के पत्र

*आरटीआई कार्यकर्ता बनना चाहता हूं*

मैं चौथी दुनिया का नियमित पाठक हूं. यह सूचना अधिकार क़ानून की संपूर्ण जानकारी आम लोगों के बीच पहुंचाने का कार्य कर रहा है. इसके लिए धन्यवाद. मैं आरटीआई कार्यकर्ता बनना चाहता हूं, कृपया उचित सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करें.

**-जितेंद्र गौतम,** *फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश.*

***यह अच्छी बात है कि आप इस क़ानून का इस्तेमाल करना चाहते हैं. आप चौथी दुनिया में नियमित प्रकाशित होने वाले आरटीआई स्तंभ को पढ़ते रहें. इसमें सूचना अधिकार क़ानून से जुड़ी सभी जानकारियां देने की कोशिश की जाती है, जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगी.***

*ग़लत पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं*

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा में पिछले पांच वर्षों से कंप्यूटर विषय की जो पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, उनमें सैकड़ों ग़लतियां हैं. इस बारे में बोर्ड एवं संबंधित विभाग को पच्चीस से अधिक पत्र, ई-मेल एवं फैक्स भेजे जा चुके हैं, लेकिन पुस्तक चयन समिति, लेखकों, अधिकारियों एवं राज्य में ठेके पर पढ़ा रही निजी कंपनी के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है. क्या आप इस मामले में सहयोग कर सकते हैं?

**-मनुज निर्वाण,** *ई-मेल से.*

***आपने इस संबंध में जो भी पत्राचार संबंधित विभाग या अधिकारियों के साथ किया है, उस पर एक आरटीआई आवेदन देकर सिर्फ़ यह पूछें कि आपके पत्रों या शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है.***

*फाइल की प्रति चाहिए*

मैंने एक आवेदन जनसंपर्क निदेशालय, रायपुर में दिया था. जवाब देने के बजाय दस्तावेज़ निरीक्षण और उसके लिए पैसा जमा कराने की बात कही जा रही है. क्या मैं उक्त फाइल की कॉपी नहीं मंगा सकता, क्योंकि फाइल की भाषा समझना कठिन है.

**-विकास शर्मा,** *रायपुर, छत्तीसगढ़.*

**आप शुल्क जमा करके फाइल की फोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हैं.**

**चौथी दुनिया ब्यूरो**
*feedback@chauthiduniya.com*

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

**चौथी दुनिया**
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

## आवेदन का प्रारूप
*(स्ट्रीट लाइट के संबंध में)*

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन
महोदय,
निम्नलिखित स्ट्रीट लाइटें कई दिनों से काम नहीं कर रही हैं:-
.....

इसके लिए कई शिकायतें की जा चुकी हैं (प्रति संलग्न है), लेकिन इन शिकायतों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इस संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:-
1. नगर निगम ने इस क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव का ठेका किसे दिया है? उस ठेके से संबंधित पत्रावली की प्रति दें.
2. नागरिकों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद कितने दिनों के अंदर ख़राब लाइटों की मरम्मत हो जानी चाहिए? इससे संबंधित कांट्रैक्ट या कोई आदेश दिया गया हो तो उसकी प्रति दें.
3. यदि लाइटों की मरम्मत उपरोक्त समय सीमा के अंदर नहीं होती है तो ठेकेदार के ख़िलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? इससे संबंधित कांट्रैक्ट या कोई आदेश दिया गया हो तो उसकी प्रति दें.
4. किन परिस्थितियों में ठेकेदार के भुगतान में कटौती की जाती है? इससे संबंधित कांट्रैक्ट या कोई आदेश दिया गया हो तो उसकी प्रति दें.
5. क्या मेरे द्वारा की गई शिकायतों के संदर्भ में ठेकेदार के भुगतान में कटौती की जाएगी, यदि नहीं तो क्यों?
6. यदि हां, तो कितने दिनों के अंदर नगर निगम यह कटौती कर लेगा?
7. किन परिस्थितियों में कांट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है? इससे संबंधित कांट्रैक्ट या कोई आदेश दिया गया हो तो उसकी प्रति दें.
8. क्या मेरे द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर कांट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है?
9. यदि हां, तो कितने दिनों के अंदर नगर निगम कांट्रैक्ट रद्द कर देगा?
10. अगर ठेकेदार अपना काम सही ढंग से नहीं करता है तो नगर निगम के पास कौन-कौन सी शक्तियां हैं, जिनका प्रयोग करके वह ठेकेदार को सही ढंग से काम करने के लिए बाध्य कर सकता है?
मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.
यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.
भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....
संलग्नक.....
(यदि कुछ हो तो)

## ज़रा हट के

# ब्लैक डेथ का राज़

लंदन के क़ब्रिस्तान से मध्यकालीन शवों से निकाले गए प्लेग रोगाणुओं से पता चलता है कि ब्लैक डेथ के लिए ज़िम्मेदार जीवाणु इंसान के लिए घातक क्यों साबित हुए और ब्लैक डेथ के बाद महामारी का सिलसिला क्यों जारी है. एक अध्ययन से पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के लोगों में रोगाणु से लड़ने की क्षमता नहीं थी. 14वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ यानी प्लेग से यूरोप में लाखों लोग मारे गए थे. विकासवादी संदर्भ में यरसिनिया पेस्टिस का डीएनए बताता है कि वह काफी सफल जीवाणु था. शोध से पता चलता है कि पिछली 6 सदियों में इस रोगाणु में कोई बदलाव नहीं हुआ है. जर्मनी की टुइबिंगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवं शोधकर्ता योहानेस क्राउजे कहते हैं, मानव इतिहास में ब्लैक डेथ पहली प्लेग महामारी थी. मनुष्य भोले-भाले थे और इस रोग का सामना करने के लिए सक्षम नहीं थे. मानव इतिहास में किसी अन्य वायरस या बग ने उतनी जनसंख्या का सफाया नहीं किया, जितना ब्लैक डेथ ने. चीन से यूरोप आई इस महामारी ने 1347 से 1351 तक जमकर कहर ढाया, जिससे यूरोप की 3 करोड़ आबादी ख़त्म हो गई.

क्राउजे के मुताबिक़ , फिर से रचे गए जिनोम के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मध्यकालीन प्लेग सभी प्रकार के आधुनिक मानव पैथोजेनिक प्लेग की जड़ है. क्राउजे कहते हैं कि अमेरिकी रेड इंडियंस को हमेशा चेचक का खतरा रहता था, जबकि यूरोपीय लोगों को कभी नहीं रहा. जो लोग परिवर्तन के कारण कम अति संवेदनशील थे, वे शायद बच गए और यह फ़ायदेमंद तब्दीली शायद फैल गई हो. ऐसी संभावना है कि सामाजिक परिस्थितियों के कारण ब्लैक डेथ ज़्यादा जानलेवा साबित हुई होगी. 18वीं और 19वीं सदी की तुलना में उस समय की स्थिति बहुत ख़राब थी, ग़रीबी एवं कुपोषण का बोलबाला था और साफ-सफाई की अवधारणा ही नहीं थी. मानव इतिहास में प्लेग, हैजा, टीबी, फ्लू, टाइफॉयड, चेचक एवं मलेरिया आदि बीमारियां कभी न कभी महामारी के रूप में पूरी दुनिया में दहशत फैला चुकी हैं. 430 ईसा पूर्व में एथेंस में फैले टाइफॉयड से एक चौथाई आबादी ख़त्म हो गई थी. यह बुखार मरीज को किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने से पहले ही मार डालता था. 19वीं शताब्दी में चीन और भारत में प्लेग ने महामारी का रूप लिया. अकेले भारत में ही इसने एक करोड़ लोगों की जान ली.

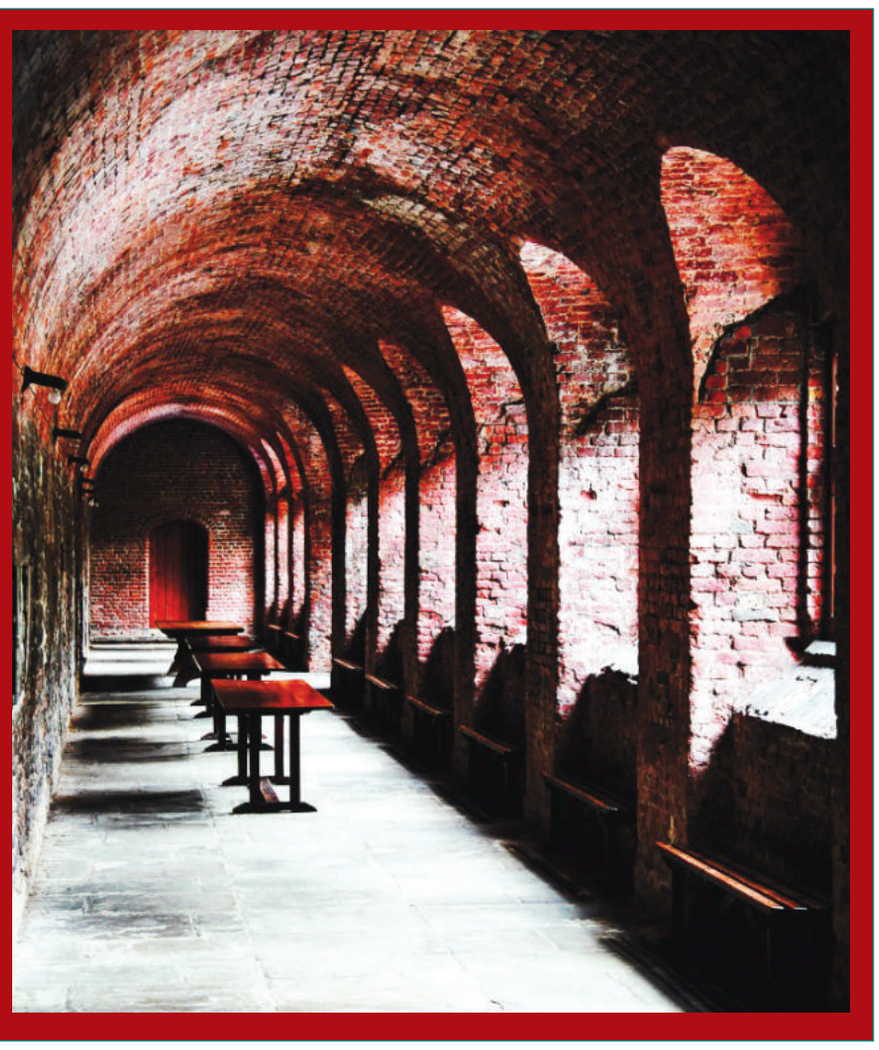

# मरने की आलीशान तैयारी

हरियाणा के कलानौर निवासी एक शख्स ने लाखों रुपये की लागत से अपनी आलीशान क़ब्र बनवाई है और अब उन्हें मौत का इंतज़ार है. सेना में मेजर रहे ग्राम संतोख रापे कोट निवासी लालमसीह ने अपने मकान की दो कनाल भूमि पर क़रीब सात लाख रुपये ख़र्च करके एक आलीशान क़ब्र बनवाई है. संगमरमर जड़े एक छतरीनुमा कमरे में निर्मित इस 8 फुट लंबी, 5 फुट चौड़ी एवं 7 फुट गहरी क़ब्र के चारों तरफ़ लोहे के चैनल लगे हैं. क़ब्र ढकने के लिए संगमरमर की बड़ी-बड़ी प्लेंटे रखी हुई हैं. यही नहीं, वहां 30 हज़ार रुपये की लागत से बना एक ताबूत भी फिट किया गया है, जिस पर ख़ूबसूरत मीनाकारी है. क़ब्र के इर्द-गिर्द बने कमरे भी ख़ूबसूरत हैं. क़ब्र की छत पर ईसाई धर्म का चिन्ह क्रॉस लगाया गया है. क़ब्र और आसपास के कमरों में भिन्न-भिन्न प्रकार की लाइटें लगाने के साथ-साथ वातावरण शुद्ध रखने के लिए फूलों-फलों से युक्त एक बगीचा भी लगाया गया है. लालमसीह का पूरा परिवार, जिसमें पांच बेटे एवं दो बेटियां हैं, विदेश में रहता है. अपने गांव की मिट्टी से प्यार करते हुए लालमसीह इसी क़ब्र में सुपुर्द-ए-खाक होने का मन बना रखा है. उन्होंने क़ब्र पर एक पत्थर भी लगवाया है, जिसमें जन्मतिथि 7 जुलाई, 1929 अंकित है, जबकि मृत्यु की तिथि के लिए जगह खाली छोड़ दी गई है. लालमसीह इन दिनों बीमार हैं और इलाज करा रहे हैं.

**चौथी दुनिया ब्यूरो**
*feedback@chauthiduniya.com*

# राशिफल

**मेष** (21 मार्च से 20 अप्रैल)
न चाहते हुए भी झंझटों में फंसना पड़ सकता है. यह सप्ताह आपको बहुत व्यस्त रखेगा. काफी समय से चल रही दौड़-भाग एवं मेहनत के बावजूद लाभ न मिलने और अधूरे काम पूरे न हो पाने के कारण स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा. अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आगे चलकर सुधार आ जाएगा.

**वृष** (21 अप्रैल से 20 मई)
परिवर्तनशील समय आ गया है. अत: अवांछित वस्तु को बदल देना उचित होगा. कार्यक्षेत्र या व्यापार में महत्वपूर्ण काम समय पर बनते नज़र आएंगे. स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं रहेगा, ख़र्च भी बढ़ सकते हैं. आपके अथक प्रयासों और सूझबूझ से किसी काम में सफलता हाथ लग सकती है.

**मिथुन** (21 मई से 20 जून)
यह समय आपके लिए तनावपूर्ण और असुविधाजनक है. सप्ताह मध्य में घर के किसी प्रमुख सदस्य से बहसबाज़ी हो सकती है. यदि आप अपने काम पर जा रहे हैं तो रास्ते में कोई व्यक्ति आपके साथ वाद-विवाद खड़ा कर सकता है.

**कर्क** (21 जून से 20 जुलाई)
सप्ताह के आरंभ में जो भी काम करेंगे, वह उत्साह के साथ संपन्न हो जाएगा. आपके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि होगी. किसी नए नेतृत्व या कार्यक्षेत्र में आपकी पहुंच बन जाएगी. मांगलिक कार्य में सफलता मिलेगी. यह सप्ताह कारोबार-कामकाज के लिए बहुत अनुकूल और शुभ साबित होगा.

**सिंह** (21 जुलाई से 20 अगस्त)
बौद्धिक कार्यों का निष्पादन होगा और कामकाज का विस्तार भी. मन में अशांति और असुरक्षा के बावजूद आप अपने सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पूरे करेंगे. किसी शुभ समाचार से आपका उत्साह बढ़ जाएगा. कारोबार आगे बढ़ाने के लिए आपके पुराने संबंध काम आएंगे.

**कन्या** (21 अगस्त से 20 सितंबर)
कोई महत्वपूर्ण कार्य बनने से ख़ुशी होगी. व्यक्तिगत समस्याएं कुछ चिंताएं पैदा कर सकती हैं. अर्थव्यवस्था ठीक करने और मान-प्रतिष्ठा क़ायम रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है. यदि आप कारोबार में साझेदारी की योजना बना रहे हैं तो उसमें प्रगति हो सकती है.

**तुला** (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
आंशिक धन लाभ की आशा में कहीं व्यय न हो जाए, इस बात का ध्यान रखें. विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यह सप्ताह आपके लिए सफलता का संकेत दे रहा है. कुछ अच्छे काम बनने और संतोषजनक धन प्राप्ति से ज़रूरी ख़र्चे और ज़िम्मेदारी निपटाने में सहायता मिल सकती है.

**वृश्चिक** (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
किसी से बहसबाज़ी न हो, इस बात का ख्याल रखें. सप्ताह के आरंभ में मिली सफलता आपको हर्षित करेगी. काफी समय से अटका काम बन जाने से आपकी मनोदशा बहुत उत्साहपूर्ण रहेगी. मित्रों एवं परिवारीजनों का सहयोग मिलेगा.

**धनु** (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
व्यक्तिगत, राजकीय एवं सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी. मकान और वाहन आदि से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा. किसी मूल्यवान वस्तु-आभूषण आदि की प्राप्ति हो सकती है. देश-विदेश से अच्छे समाचार या उपहार आदि मिलने की प्रबल संभावना है.

**मकर** (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
आजीविका एवं व्यवसाय में अर्थ लाभ की उम्मीद रखें. कामकाज में अस्थिरता एवं अनिश्चितता बनी रहेगी. आपके गिरते स्वास्थ्य को लेकर सगे-संबंधियों को चिंता हो सकती है. जो भी आर्थिक दबाव या ज़रूरी ख़र्च आपके ऊपर आ रहे हैं.

**कुंभ** (21 जनवरी से 20 फरवरी)
वरिष्ठजनों या माता-पिता के प्रति उत्तरदायित्व पूरा करने का उपक्रम बनेगा. चंद्रमा के अच्छे गोचर से यह सप्ताह आपके लिए शुभ सिद्ध होगा. व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान होगा, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मित्रों एवं परिवारीजनों के बीच आपकी ख्याति बढ़ेगी.

**मीन** (21 फरवरी से 20 मार्च)
किसी प्रियजन से मुलाक़ात का उत्साह रहेगा. आर्थिक एवं व्यापारिक कार्य संपन्न करने में परिवारीजनों और शुभचिंतकों का पूरा सहयोग मिलेगा. सप्ताह मध्य में कुछ दोस्त भी सकारात्मक रुख़ लेकर मिल सकते हैं. यथेष्ट लाभ के लिए ज़रूरी है कि आप योजनाबद्ध तरीक़े से अपने सभी कार्य पूरे करने की कोशिश करें.

**पंडित सुदर्शन**
*feedback@chauthiduniya.com*

नेपाल सरकार के इस क़दम की सराहना की जानी चाहिए. विश्व स्तर पर सरकार की इस पहल का अमेरिका ने स्वागत किया है तथा पूर्व माओवादियों के पुनर्वास के लिए यथासंभव मदद देने का भी भरोसा नेपाल सरकार को दिलाया है.

## राष्ट्रमंडल के राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन

# वैश्विक चुनौतियों का डटकर सामना करें

राजीव कुमार

राष्ट्रमंडल देशों के राष्ट्र प्रमुखों की 21वीं बैठक ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 28 से 30 अक्टूबर के बीच संपन्न हुई. भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह अपनी अंतरराष्ट्रीय व्यस्तता के कारण इस सम्मेलन में शिरकत नहीं कर पाए. इसके कारण भारत का प्रतिनिधित्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया. 54 सदस्यों वाले इस संगठन की बैठक के शुरू होने की घोषणा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इस मांग के साथ की कि सदस्य राष्ट्रों को मानवाधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए तथा इसके उल्लंघन के ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ अपनाने की आवश्यकता है. इस बैठक में अन्य संगठनों की बैठकों की तरह ही वैश्विक वित्तीय संकट, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, व्यापारिक चुनौतियों तथा आतंकवाद की समस्याओं पर चर्चा की गई. चूंकि इसके सदस्य देशों में बहुत सारे देश टापू राष्ट्र हैं, जिनपर जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक भयावह असर पड़ने वाला है. इस कारण यह मुद्दा तो इस सम्मेलन में उठना लाज़िमी था. ऐसे भी जलवायु परिवर्तन आधुनिक विश्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है और समय रहते अगर इससे निपटने के लिए कड़े क़दम नहीं उठाए गए तो प्रकृति के प्रकोप से विश्व को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा. इस सम्मेलन में तो इसे गंभीरता से लिया गया, लेकिन इस पर कितना अमल किया जाता है यह आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अभी तक जिस मंथर गति से इसके कारण उत्पन्न समस्याओं पर काम किया जाता रहा है, उससे तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि विकास की अंधी दौड़ में कहीं हम विनाश को निमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं. वैसे भी जब तक कुछ विकसित देश इस ओर ध्यान नहीं देते हैं तब तक इस पर नियंत्रण रखना मुश्किल है, क्योंकि सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन तो इन्हीं देशों द्वारा किया जाता है. अब ज़रूरत इस बात की है कि विकासशील देश एकजुट होकर इन विकसित देशों पर दबाव डालें. जब तक उनका आर्थिक हित प्रभावित नहीं होता है, तब तक ये इस ओर गंभीरता नहीं बरतेंगे.

इस बैठक में एक अन्य मुद्दा आतंकवाद का रहा. भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों की आलोचना की और संयुक्त राष्ट्रसंघ में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि (सीसीआईटी) की वार्ता को नतीजे तक पहुंचाने के लिए प्रयास तेज़ करने का सदस्य देशों से आह्वान किया है. संगठन ने सदस्य राष्ट्रों से आह्वान किया है कि वे अपनी भूमि का इस्तेमाल हिंसा फैलाने या आतंकवादी गतिविधियों के लिए न होने दें और आतंकवादियों को मिलने वाली वित्तीय मदद के विरुद्ध क़ानून बनाएं. भारत के लिए यह सबसे ज़रूरी समझौता होगा, क्योंकि अपने पड़ोसी मुल्क की कारगुज़ारियों से यह देश सबसे अधिक प्रभावित है. पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से रिश्तों के रोज़ नए प्रमाण मिल रहे हैं. अगर इस संधि को अमल में लाया गया तो पाकिस्तान पर कुछ अंकुश तो अवश्य लगेगा. ग़ौरतलब है कि सीसीआईटी में आतंकवाद के सभी स्वरूपों को ग़ैरकानूनी घोषित करने तथा उन्हें संरक्षण देने वाले राष्ट्रों के प्रति कड़ा रुख़ अपनाने की बात कही गई है. इसके अलावा इस बैठक में हिंद महासागर में बढ़ती समुद्री डकैती की घटनाओं पर भी चिंता जताई गई है तथा इसे रोकने के लिए एकजुट होकर क़दम उठाने की बात कही गई है. समुद्री डकैती पर अंकुश लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया. साथ ही साइबर सुरक्षा के लिए बेहतर क़ानून बनाने पर भी ज़ोर देने की बात इस बैठक में की गई.

इस बैठक की एक ख़ास बात रही कि विशिष्ट व्यक्तियों के समूह (ईपीजी) की सिफ़ारिशों पर अलग-अलग मतों का. 11 सदस्यीय ईपीजी ने 106 सिफ़ारिशें की थीं, जिसमें दो सिफ़ारिशों पर अधिक चर्चा हुई. इसमें एक राष्ट्रमंडल देशों के लिए एक नैतिक संहिता (चार्टर ऑफ वैल्यू) बनाने से संबंधित था तो दूसरा राष्ट्रमंडल मानवाधिकार आयुक्त नियुक्त करने का. नैतिक संहिता बनाने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए तो लगभग सभी देश राज़ी हुए, लेकिन मानवाधिकार कमिश्नर की बात को और अधिक चर्चा की ज़रूरत के साथ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. भारतीय प्रतिनिधि हामिद अंसारी का कहना था कि इस मुद्दे पर जल्दबाज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है. मानवाधिकार कमिश्नर की नियुक्ति से संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संबंधी कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी. भारतीय उप राष्ट्रपति ने राष्ट्रमंडल देशों को विकास के मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की सलाह भी दी तथा दूसरे देशों के घरेलू मामलों में आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की आलोचना भी की. इन मुद्दों के अलावा इस बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा वित्तीय संकट से जूझ रहे विश्व की सहायता करने के लिए सदस्य देशों से अपील भी की गई. ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जुलिया गिलार्ड ने जी-20 की बैठक में वित्तीय संकट के मुद्दे को उठाने की बात कही.

भारत ने इस बैठक का उपयोग कई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए भी किया. भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव आदि कई देशों के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक मुलाक़ात की. भारत के विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने भी इस दौरे का सदुपयोग किया. उन्होंने राष्ट्रमंडल बैठक से इतर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रियों से बात की तथा उनके देश द्वारा निकाली गई यात्रा परामर्श पर आपत्ति दर्ज की. ग़ौरतलब है कि इन देशों ने अपने नागरिकों के लिए छुट्टियों में जारी यात्रा परामर्श में भारत के लिए प्रतिकूल टिप्पणी की थी. इससे भारत का पर्यटन उद्योग प्रभावित होता है. कृष्णा की इन बातों पर ग़ौर करने की बात तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने की. ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने कहा कि वे अपने नागरिकों को इस बात की सूचना देने के लिए क़ानूनी तौर पर बंधे हुए हैं कि किस देश की यात्रा पर जाना उनके लिए कितना सुरक्षित है. इसके अलावा ऐसा करना बीमा कंपनियों की नीतियों के कारण भी ज़रूरी है. लेकिन इस मुद्दे पर ग़ौर करने की बात तीनों विदेश मंत्रियों ने की. इस बैठक में भारत के लिए एक और ख़ुशी की बात यह रही कि भारत के कमलेश शर्मा को दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रमंडल महासचिव नियुक्त किया गया. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान ने भी भारतीय अधिकारी का समर्थन किया. हालांकि इस बैठक को सफल बताया गया है और भारतीय उप राष्ट्रपति ने भी इसे सफल ही माना है, लेकिन इसकी सफलता की बात तभी कही जा सकती है जब जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है, उन पर अमल भी किया जाए. बैठकें तो होती ही रहती हैं. इसकी बैठक भी हर दो साल के बाद होती है, लेकिन जब तक सकारात्मक नतीजे सामने नहीं आएंगे तब तक इसकी बैठकों की सफलता का दावा करना बेमानी होगा. इस संगठन को चाहिए कि आर्थिक रिश्ते सुधारने की कोशिश करे तथा आपसी सहयोग के आधार पर वैश्विक चुनौतियों से निपटने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखलाए. अगर इस संगठन को अपनी प्रासंगिकता बरक़रार रखनी है तो फिर चार्चाओं को ज़मीनी हक़ीक़त में बदलना होगा, वरना यह एक-दो वर्षों में होने वाली उत्सव बनकर रह जाएगी.

feedback@chauthiduniya.com

## नेपाल
# शांति के लिए समझौता

नेपाल की राजनीतिक पार्टियों के बीच का समझौता एक सराहनीय क़दम कहा जा सकता है. इस समझौते के तहत पूर्व माओवादियों में से कुछ को सेना में भर्ती किया जाएगा. जिन्हें सेना में नहीं लिया जा रहा है उन्हें सहयोग राशि दी जाएगी, ताकि वे नए जीवन की शुरुआत कर सकें. इस समझौते में नेपाल की तीन प्रमुख पार्टियों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी), नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के नेताओं ने भाग लिया. गृह युद्ध की समाप्ति के बाद से ही इस बात पर चर्चा जारी है कि जो माओवादी मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं, उनका क्या किया जाए. माओवादी प्रमुख पुष्प कमल दहल ने कहा था कि उन्हें सेना में जगह दी जाए, लेकिन सेना उनके प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थी. सेना को अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन भी प्राप्त था, जिसके कारण समझौता नहीं हो पाया था. ग़ौरतलब है कि 2006 में नेपाल में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद 19600 माओवादी संयुक्त राष्ट्रसंघ के शिविरों में रह रहे हैं. इस समझौते के अनुसार इनमें से एक तिहाई माओवादियों को सेना में भर्ती किया जाएगा. इसके अलावा क़रीब 12000 माओवादियों को मुफ्त शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. साथ ही उन्हें स्वरोज़गार के लिए 5 से 8 लाख तक की सहयोग राशि दी जाएगी, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें. इस समझौते में एक ख़ास बात यह है कि सेना में शामिल किए गए माओवादियों को किसी लड़ाई में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उन्हें निर्माण कार्य, जंगलों में पहरा देने तथा बचाव कार्यों में लगाया जाएगा. हो सकता है कि यह सेना और राजनीतिक पाटियों के दबाव का नतीजा हो. जिन छापामारों के ख़िलाफ़ सेना कार्रवाई कर रही थी, उन्हें अपने साथ किसी लड़ाई में शामिल करने से वे हिचक रहे हैं. माओवादी प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पत्रकारों से कहा कि हमने शांति प्रक्रिया में एक और पड़ाव पार कर लिया है और अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती इसे लागू करने की है. हालांकि कुछ माओवादियों ने इस समझौते का विरोध किया है, लेकिन प्रचंड के इस समझौते में शामिल होने से यह उम्मीद तो की ही जा सकती है कि वह उन्हें समझा लेंगे.

नेपाल में हुए इस राजनीतिक समझौते का फ़ायदा भारत को भी होगा. नेपाल के माओवादी छापामारों का संबंध भारत के माओवादियों के साथ भी है. अगर वहां के माओवादी शस्त्र त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होते हैं तो इसका असर भारतीय माओवादियों पर भी पड़ेगा. साथ ही भारतीय माओवादियों को उनसे मिलने वाली सहायता भी रुकेगी. अभी नेपाल के प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई की भारत यात्रा से भी दोनों देशों के बीच संबंध और मज़बूत होने के आसार दिखाई पड़ रहा है. भट्टाराई ने नेपाल में भारत की सामरिक और आर्थिक दोनों तरह की भूमिका की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था. भट्टाराई की भारत यात्रा के समय किए गए समझौतों से ऐसा लगता है कि नेपाल अब चीन से नहीं भारत से ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए है. बीच में ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार का झुकाव भारत की अपेक्षा चीन के प्रति होता जा रहा है. लेकिन अब ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है. हालांकि सावधान रहने की आवश्यकता तो हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि चीन कभी नहीं चाहेगा कि नेपाल और भारत के बीच का संबंध मधुर हो. नेपाल में शांति तथा लोकतंत्र की बहाली भारत के हित में है और इस देश के राजनीतिक दलों के बीच हुआ यह समझौता शांति बहाली का मार्ग प्रशस्त करेगा. बहरहाल, नेपाल के राजनीतिक दलों के बीच हुए इस समझौते की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इस पर कितनी जल्दी अमल होता है. जिन माओवादियों को सुरक्षा बलों में शामिल किया जाएगा, उनके साथ पहले से कार्यरत सुरक्षा बलों के व्यवहार का ठीक होना भी ज़रूरी है. ऐसा न हो कि उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़े. ऐसी स्थिति में सेना और सरकार पर दोहरी ज़िम्मेदारी है. अगर इसका निर्वहन सही ढंग से हो पाया तो वे लोग जो इस समझौते का विरोध कर रहे हैं, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी तथा आगे उन्हें भी मुख्यधारा में शामिल होना पड़ेगा. लेकिन अगर इस समझौते को सही तरह से लागू नहीं किया गया तो फिर माओवादियों के दूसरे धड़े को सरकार के विरोध का मौक़ा मिल जाएगा. इस समझौते की सफलता के लिए सरकार को तत्परता से क़दम उठाना चाहिए. भारत सरकार को भी नेपाल का सहयोग करना चाहिए, ताकि आगे का रास्ता सरल हो सके.

राजीव कुमार
feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
स्पेशल रिपोर्ट
नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

बाबा-अगर शांकर भाष्य में नहीं है तो कोई हर्ज नहीं. यदि ज्ञानं के स्थान पर अज्ञानं रख देने से उसका बेहतर मतलब निकलता है तो क्या कोई आपत्ति है?



# साई बाबा और संस्कृत ज्ञान

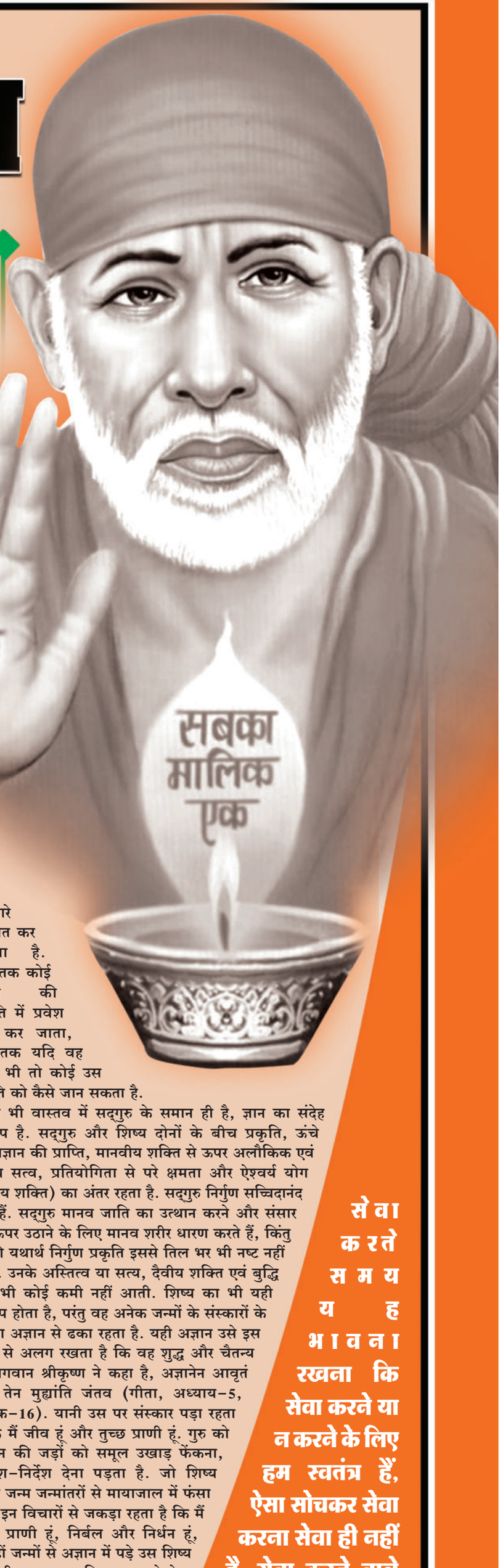


बात उन दिनों की है, जब शिरडी में द्वारकामाई मस्जिद में भीड़ बहुत अधिक नहीं लगती थी. उन दिनों किसी को विश्वास नहीं होता था कि साई बाबा संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं. उनके परम प्रिय भक्त नाना साहब चांदोरकर संस्कृत बहुत अच्छी तरह जानते थे. उन्होंने गीता पर कई भाष्यों का अध्ययन किया था और उन्हें गर्व था कि वह संस्कृत के ज्ञाता हैं. वह भी यही समझते थे कि साई बाबा संस्कृत नहीं जानते हैं. एक दिन साई बाबा और चांदोरकर अकेले बात कर रहे थे. चांदोरकर साई बाबा के चरण दबा रहे थे और कुछ गुनगुना रहे थे. साई बाबा पूछ बैठे, नाना, क्या गुनगुना रहे हो? चांदोरकर बोले, मैं संस्कृत के एक श्लोक का पाठ कर रहा हूं.

कौन सा श्लोक?

भगवतगीता से है.

जरा जोर से पाठ करो.

नाना साहब चांदोरकर ने जोर से पाठ किया,

तद्विद्धि प्रणिपतेन परिप्रश्नेन सेवया,
उपदेक्ष्यंति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्व दर्शिन:

बाबा-नाना, क्या तुम इस श्लोक का अर्थ समझते हो?

नाना-हां.

बाबा-यदि तुम समझते हो तो मुझे बताओ.

नाना-इसका अर्थ यह है कि गुरु को साष्टांग दंडवत-प्रणाम करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, उनसे प्रश्न करते हुए सीखो कि यह ज्ञान क्या है. तब सद्वस्तु (ब्रह्म) का सत्य ज्ञान प्राप्त किए हुए ज्ञानी तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे.

बाबा-मैं श्लोक के पूरे पद का इस तरह से संग्रह किया हुआ सारांश नहीं चाहता, मुझे प्रत्येक शब्द का व्याकरणिक प्रभाव, महत्व और अर्थ बताओ.

तब नाना साहब ने साई बाबा को एक-एक शब्द समझाया.

बाबा-नाना, क्या केवल साष्टांग दंडवत-प्रणाम करना पर्याप्त है?

नाना-मैं प्रणिपात शब्द का अर्थ साष्टांग दंडवत-प्रणाम करने के सिवाय दूसरा नहीं जानता.

बाबा-परिप्रश्न क्या है?

नाना-प्रश्न पूछना.

बाबा-प्रश्न का क्या अर्थ है?

नाना-वही, प्रश्न पूछना.

बाबा-यदि परिप्रश्न और प्रश्न का एक ही अर्थ है तो व्यास ने परि उपसर्ग क्यों लगाया? क्या उसका सिर फिर गया था?

नाना-मैं परिप्रश्नेन शब्द का दूसरा कोई अर्थ नहीं जानता.

बाबा-सेवा शब्द से किस प्रकार की सेवा का तात्पर्य है?

नाना-वही, जो हम लोग हमेशा करते हैं.

बाबा-क्या ऐसी सेवा पर्याप्त है?

नाना-मैं नहीं जानता कि सेवा शब्द का इससे अधिक क्या महत्व है.

बाबा-अगली पंक्ति उपदेक्ष्यंति ते ज्ञानं में ज्ञानं के स्थान पर दूसरा कोई और शब्द रखकर पढ़ सकते हैं?

नाना-हां, अज्ञानं रखकर भी पढ़ सकते हैं.

## श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

बाबा-ज्ञानं के बदले अज्ञानं शब्द ले लेने से क्या इस श्लोक का कोई अर्थ निकलता है?

नाना-नहीं. शांकर भाष्य में ऐसी कोई श्लोक रचना नहीं है.

बाबा-अगर शांकर भाष्य में नहीं है तो कोई हर्ज नहीं. यदि ज्ञानं के स्थान पर अज्ञानं रख देने से उसका बेहतर मतलब निकलता है तो क्या कोई आपत्ति है?

नाना-मैं नहीं समझता कि अज्ञानं शब्द रख देने से शब्दों की व्याख्या, पदच्छेद, अन्वय और अर्थ कैसे कर सकते हैं.

बाबा-कृष्ण अर्जुन को ज्ञानी या तत्वदर्शी के पास जाकर साष्टांग दंडवत, परिप्रश्न और सेवा करने का निर्देश क्यों देते हैं, जबकि कृष्ण स्वयं तत्वदर्शन और ज्ञान ही हैं?

नाना-हां, वह थे तो, लेकिन मैं इसे नहीं समझ सकता हूं कि कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञानियों के पास जाने का निर्देश क्यों दिया.

बाबा-नाना, क्या तुम जैसा संस्कृत का विद्वान भी इसे नहीं समझ पा रहा है?

नाना चांदोरकर की अब तक अवमानना हो चुकी थी. उनके गर्व का सिर नीचा हो चुका था. तब साई बाबा ने समझाना शुरू किया:-

1. ज्ञानी के सामने केवल साष्टांग दंडवत-प्रणाम करना ही पर्याप्त नहीं है. हमें सद्गुरु के प्रति पूर्ण रूप से शरणागति में जाना ही पड़ेगा.

2. केवल प्रश्न करना ही पर्याप्त नहीं है. गुरु या सद्गुरु से किसी कारणवश अथवा उनसे आलस्यवश ग़लत उत्तर मिल जाने पर तर्क-वितर्क करने के उद्देश्य से ही प्रश्न करना कदापि उचित नहीं है, वरन् सदैव अनुचित और अवांछनीय है. प्रश्न अवश्य गंभीर होना चाहिए. मोक्ष या आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही प्रश्न किया जाना चाहिए. यही परिप्रश्नेन का अर्थ है.

3. सेवा करते समय यह भावना रखना कि सेवा करने या न करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, ऐसा सोचकर सेवा करना सेवा ही नहीं है. सेवा करने वाले को अवश्य ही अपने मन में यह भावना रखनी चाहिए कि मैं अपने शरीर का मालिक नहीं हूं. शरीर गुरु का है, उस पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं, क्योंकि शरीर गुरु को समर्पित हो चुका है और केवल गुरु की सेवा करने के लिए ही यह शरीर जीवित है. अगर यह किया जाए तो सद्गुरु तुम्हें दिखाएंगे कि श्लोक में आया हुआ शब्द अज्ञानं क्या है.

नाना साहब चांदोरकर की समझ में नहीं आया कि गुरु अज्ञान की शिक्षा देता है. तब बाबा ने उन्हें समझाने के लिए कहा कि ज्ञान अथवा आत्मज्ञान का उपदेश अपने भीतर के अज्ञान का नाश करने पर ही प्रभावशील हो सकता है और अज्ञान का नाश करने के लिए उसे जानना आवश्यक है. साई बाबा ने इसे स्पष्ट करने के लिए गीता पर संत ज्ञानेश्वर के भाष्य का यह उदाहरण दिया:-

1. मग अज्ञान निमालिया मीच एक असे अपैसया सनिद्र स्वप्न गेलिया, आपण जसें.

2. ते अज्ञान जे समूल तुटे, तैं भ्रान्ती चे मसैरे फिटे.

गीता के श्लोक 18-66 पर भाष्य करते हुए संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि अज्ञान और नींद हटा दिए जाएं तो तुम स्वयं ही तो हो. अंधेरे को दूर हटा देना ही प्रकाश है. द्वैत की भावना मिटा देना ही तो अद्वैत है. जब कभी हम द्वैत को मिटाने की बात करते हैं, तब हम अद्वैत के बारे में ही तो बोलते हैं. जब कभी हम अंधेरे को मिटा देने की बात करते हैं, तब हम प्रकाश की ही बात करते हैं. यदि हमें अद्वैत का अनुभव करना है, तब अपने भीतर रहने वाली द्वैत भावना का उन्मूलन करना ही होगा. वही अद्वैत की स्थिति है. द्वैत में रहने वाला ऐसा कौन है, जो अद्वैत के बारे में बात कर सकता है. जब तक कोई अद्वैत की स्थिति में प्रवेश नहीं कर जाता, तब तक यदि वह बोले भी तो कोई उस स्थिति को कैसे जान सकता है.

शिष्य भी वास्तव में सद्गुरु के समान ही है, ज्ञान का संदेह स्वरूप है. सद्गुरु और शिष्य दोनों के बीच प्रकृति, ऊंचे आत्मज्ञान की प्राप्ति, मानवीय शक्ति से ऊपर अलौकिक एवं दैवीय सत्व, प्रतियोगिता से परे क्षमता और ऐश्वर्य योग (दैवीय शक्ति) का अंतर रहता है. सद्गुरु निर्गुण सच्चिदानंद होते हैं. सद्गुरु मानव जाति का उत्थान करने और संसार को ऊपर उठाने के लिए मानव शरीर धारण करते हैं, किंतु उनकी यथार्थ निर्गुण प्रकृति इससे तिल भर भी नष्ट नहीं होती. उनके अस्तित्व या सत्य, दैवीय शक्ति एवं बुद्धि में कभी कोई कमी नहीं आती. शिष्य का भी यही स्वरूप होता है, परंतु वह अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण अज्ञान से ढका रहता है. यही अज्ञान उसे इस दृष्टि से अलग रखता है कि वह शुद्ध और चैतन्य है. भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है, अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यांति जंतव (गीता, अध्याय-5, श्लोक-16). यानी उस पर संस्कार पड़ा रहता है कि मैं जीव हूं और तुच्छ प्राणी हूं. गुरु को अज्ञान की जड़ों को समूल उखाड़ फेंकना, उपदेश-निर्देश देना पड़ता है. जो शिष्य अनंत जन्म जन्मांतरों से मायाजाल में फंसा हुआ इन विचारों से जकड़ा रहता है कि मैं तुच्छ प्राणी हूं, निर्बल और निर्धन हूं, सैकड़ों जन्मों से अज्ञान में पड़े उस शिष्य के उसी अज्ञान का निवारण करने के लिए सद्गुरु उसे शिक्षा देते हुए बताते हैं कि तुम ईश्वर हो, तुम शक्तिशाली, ऐश्वर्य संपन्न हो. तब कहीं वह अत्यल्प मात्रा में समझता है कि मैं ईश्वर हूं. अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ, वह कहां है, शिष्य को यही ज्ञान कराना गुरु का परम कर्तव्य है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

**सेवा करते समय यह भावना रखना कि सेवा करने या न करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, ऐसा सोचकर सेवा करना सेवा ही नहीं है. सेवा करने वाले को अवश्य ही अपने मन में यह भावना रखनी चाहिए कि मैं अपने शरीर का मालिक नहीं हूं. शरीर गुरु का है, उस पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं, क्योंकि शरीर गुरु को समर्पित हो चुका है और केवल गुरु की सेवा करने के लिए ही यह शरीर जीवित है. अगर यह किया जाए तो सद्गुरु तुम्हें दिखाएंगे कि श्लोक में आया हुआ शब्द अज्ञानं क्या है. नाना साहब चांदोरकर की समझ में नहीं आया कि गुरु अज्ञान की शिक्षा देता है. तब बाबा ने उन्हें समझाने के लिए कहा कि ज्ञान अथवा आत्मज्ञान का उपदेश अपने भीतर के अज्ञान का नाश करने पर ही प्रभावशील हो सकता है और अज्ञान का नाश करने के लिए उसे जानना आवश्यक है.**

## श्री साई महिमा

श्री साई राम परम सत्य, प्रकाश रूप,
परम पावन शिरडी निवासी, परम ज्ञान आनंद
स्वरूप, प्रज्ञा प्रदाता, सच्चिदानंद स्वरूप,
परम पुरूष योगीराज, दयालु देवाधिदेव हैं,
उनको बार बार नमस्कार.

## आरती श्री शिरडी के साईबाबा की

आरती श्री साई गुरूवर की, परमानंद सदा सुरवर की
जाकी कृपा विपुल सुखकारी, दुख, शोक, संकट, भयहारी
शिरडी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया
कितने भक्त चरण पर आए, वे सुख शांति चिरतंन पाए
भाव धरे मन में जैसा, पावत अनुभव वो ही वैसा
गुरू की लगावे तन को, समाधान लाभत उस मन को
साई नाम सदा जा गावे, सो फल जग में शाश्वत पावे
गुरूबारसर करि पूजा सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा
राम, कृष्ण, हनुमान रूप में, दे दर्शन जानत जो मन में
विविध धर्म के सेवक आते, दर्शन से इच्छित फल पाते
जय बोलो साई बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरू की
साईदास आरती को गावे, घर में बसि सुख मंगल पावे.

भगवान श्रीकृष्ण को परिजात यानी हरसिंगार, पलाश, मालती, कुमुद, करवरी, चणक, नंदिक और वनमाला के फूल प्रिय हैं.

अनंत विजय

# लेखको, माफ़ी मांगो

पिछले दिनों लखनऊ में हिंदी के महान रचनाकारों में से एक श्रीलाल शुक्ल जी का निधन हो गया. मैं श्रीलाल जी से दो बार मिला. एक बार राजकमल प्रकाशन के लेखक से मिलिए कार्यक्रम में और दूसरी बार राजेंद्र यादव की जन्मदिन की पार्टी में. लेखक से मिलिए कार्यक्रम में तो बेहद ही औपचारिक सी मुलाक़ात थी, लेकिन कवि उपेंद्र कुमार के घर पर हुई राजेंद्र यादव की पार्टी में तो मेरा अनुभव एकदम ही अलहदा था. किस वर्ष की बात है यह ठीक से याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध की बात है. यादव जी की पार्टी चल रही थी. दिल्ली का पूरा साहित्यिक समाज वहां मौजूद था. पार्क स्ट्रीट के बंगले में हो रही पार्टी में जमकर रसरंजन भी हो रहा था. रसरंजन के बाद खाने का इंतज़ाम था. पार्टी अपने शबाब पर थी. जमकर रसरंजन हो रहा था. नामवर जी, अजित कुमार, श्रीलाल शुक्ल एक ही टेबल पर जमे हुए थे. हम लोग खाना खाने पहुंचे तो देखा कि श्रीलाल जी भी आ रहे हैं. कतार में खड़े सभी लोगों ने श्रीलाल जी के लिए जगह छोड़ दी. शुक्ल जी ने खाना लिया और प्लेट लेकर गेट की ओर बढ़ चले. सभी लोग अपनी मस्ती में थे, रसरंजन का भी असर था. खाना लेकर श्रीलाल जी जब गेट से बाहर हो गए तो हम दो–तीन लोग लपके, लेकिन श्रीलाल जी कहां मानने वाले थे वह तो सड़क पार करके जाकर डिवाइडर पर बैठ गए. अब सोचिए कि हिंदी का इतना बड़ा लेखक पार्टी से निकलकर डिवाइडर पर बैठकर खाना खा रहा है. पार्क स्ट्रीट पर ठीक–ठाक ट्रैफिक होता है, लेकिन पार्टी के शोरगुल से बेफ़िक्र श्रीलाल जी खाने में मगन थे. हम लोग उनके आसपास खड़े थे. मैं मंत्रमुग्ध सा उनको देख रहा था. हिंदी के इतने बड़े साहित्यकार से इतने नज़दीक से मिलने का मौक़ा. जब खाना ख़त्म होने लगा तो उन्होंने कहा कि सब्ज़ी चाहिए. ख़ैर हमारे कहने पर माने और ख़ुद चलकर अंदर आ गए, लेकिन तबतक रसरंजन का असर काफ़ी हो चुका था. किसी तरह हम उनको लेकर अंदर आए और फिर वहां बिठाया. यह मेरे लिए एक स्वप्न सरीखा था. राग दरबारी जैसी कालजयी कृति के रचियता से बातचीत कर मैं धन्य हो रहा था.

ख़ैर पार्टी ख़त्म हो गई और हम अपने अपने घर चले गए, लेकिन तबतक कई लोगों से श्रीलाल जी के बारे में बात कर काफ़ी जान चुका था. कई सालों बाद जब तद्भव के प्रवेशांक में श्रीलाल शुक्ल पर रवींद्र कालिया का संस्मरण पढ़ा तो यादव जी के जन्मदिन की घटना एक बार फिर से स्मरण हो आया. कालिया जी ने लिखा था– लखनऊ में मेरे एक आईएएस मित्र हैं, एक बार उनसे मिलने उनके निवास स्थान पर गया. बाहर एक चौकीदार तैनात था. मैंने उससे पूछा, साहब हैं? हां हैं. क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं. उसने निहायत सादगी से जवाब दिया. श्रीलाल शुक्ल जब इलाहाबाद नगर निगम के प्रशासक थे, तो अक्सर उनसे भेंट होती थी, उनका चौकीदार भी कुछ–कुछ लखनऊ के मित्र के चौकीदार जैसा था. एक बार उनसे मिलने गया और चौकीदार से यह पूछने पर कि श्रीलाल जी घर पर हैं या नहीं, उसने बताया, साहब हैं. क्या कर रहे हैं– मैंने पूछा. बाहर बग़ीचे में बैठे हैं और टकटकी लगाकर चांद की तरफ़ देख रहे हैं. उसने बग़ीचे की ओर संकेत करते हुए कहा था. बाद में कालिया जी को श्रीलाल जी ने पत्र लिखकर उपरोक्त प्रसंग पर हल्की सी नाराज़गी भी दिखाई थी और लिखा था कि काल्पनिक आईएएस मित्र की बजाय सीधे–सीधे उनका नाम भी लिख देते तो कुछ नहीं हो जाता. तद्भव का वह अंक बेहतरीन था, लेकिन वह अंक मेरे पास नहीं हैं. बाद में राजकमल से ही अखिलेश के संपादन में श्रीलाल शुक्ल की दुनिया के नाम से वह पुस्तकाकार छपा. श्रीलाल जी को जानने के लिए वह किताब मुकम्मल है. तक़रीबन दस साल बाद लखनऊ जाना हुआ. श्रीलाल जी से मिलने के लिए उनके घर फोन किया. यह याद नहीं कि किसने उठाया, लेकिन यह बताया गया कि उनकी तबीयत ख़राब है और मुलाक़ात मुमकिन नहीं है.

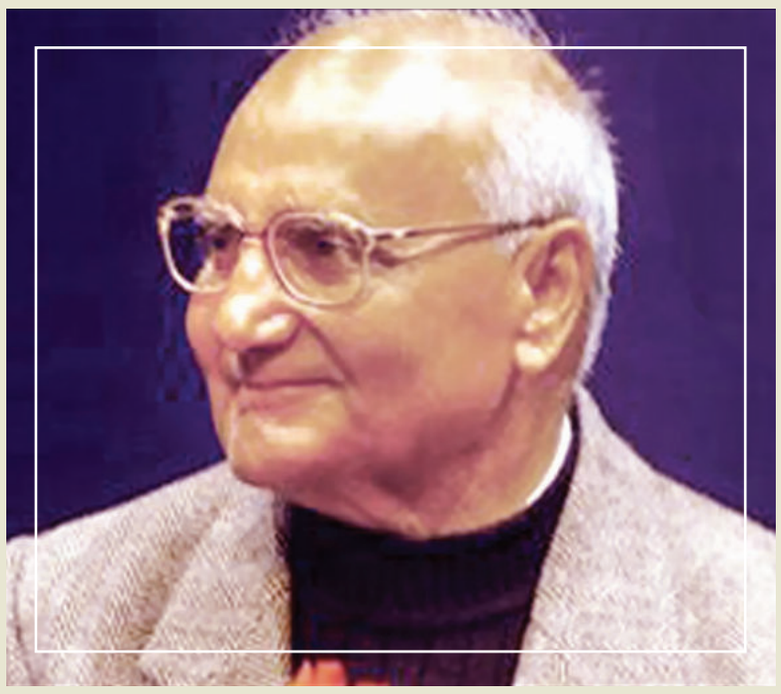

**जब श्रीलाल जी बीमार थे और लखनऊ के अस्पताल में भर्ती थे तो अचानक एक दिन दिल्ली के कुछ लेखकों की ओर से एक अपील जारी हुई, जिसमें कहा गया कि सरकार की ओर से श्रीलाल जी के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए. अपील पर दस्तख़त करने वालों में अशोक वाजपेयी, राजेंद्र यादव, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, कुंवर नारायण, नामवर सिंह, चंचल चौहान, पंकज बिष्ट एवं रेखा अवस्थी के नाम प्रमुख हैं. इस मुहिम के अगुवा मुरली मनोहर प्रसाद थे. श्रीलाल जी वरिष्ठ आईएएस अफ़सर थे और उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव के पद से रिटायर हुए थे. लिहाज़ा उनके पास सीजीएचएस की सुविधा होनी चाहिए.**

श्रीलाल जी के निधन से एक और हसरत मन में ही रह गई. दो हज़ार दो में मेरे श्वसुर (अब स्वर्गीय) प्रो. प्रियवत नारायण सिंह जी ने मुझे राग दरबारी का पहला संस्करण भेंट किया. मेरे लिए यह एक अमूल्य भेंट थी. मेरे पास राग दरबारी का पेपर बैक संस्करण था. राग दरबारी का पहला संस्करण 1968 में राजकमल प्रकाशन प्रा. लिमिटेड दिल्ली–6 से छपा था. उस संस्करण पर उपन्यास का मूल्य 15 रुपये अंकित है. पहले संस्करण का कवर रिफार्मा स्टूडियो, दिल्ली ने बनाया था. लेकिन जब मुझे राग दरबारी का पहला संस्करण मिला तो उसका कवर नहीं था. मैंने यूं ही राजकमल प्रकाशन के मालिक अशोक महेश्वरी को पहले संस्करण की प्रति के बारे में चर्चा की. उन्होंने सुनते ही प्रस्ताव रखा कि मैं उनको पहले संस्करण की प्रति दे दूं, बदले में वह मुझे राग दरबारी की पांच प्रतियां दे देंगे. मैंने विनम्रतापूर्वक उनके प्रस्ताव को मना कर दिया. थोड़ी निराशा उनके चेहरे पर अवश्य दिखी, लेकिन मेरी भावनाओं को उन्होंने समझा. मेरे पास राग दरबारी का कवर नहीं था. मैंने अशोक जी से एक कवर मांग लिया. अब मेरे पास जो राग दरबारी है वह पहला संस्करण है, लेकिन कवर बाद के संस्करण का है. मैं जब भी लखनऊ जाता था तो सोचता था कि इस बार श्रीलाल शुक्ल से मिलूंगा और उनसे किताब पर दस्तख़त लूंगा और कवर के बारे में मालूम करूंगा, लेकिन श्रीलाल जी के निधन के बाद यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी.

लेकिन श्रीलाल जी की बीमारी और उनके निधन के बहाने मैं एक और बात शिद्दत से उठाना चाहता हूं. जब श्रीलाल जी बीमार थे और लखनऊ के अस्पताल में भर्ती थे तो अचानक एक दिन दिल्ली के कुछ लेखकों की ओर से एक अपील जारी हुई, जिसमें कहा गया कि सरकार की ओर से श्रीलाल जी के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए. अपील पर दस्तख़त करने वालों में अशोक वाजपेयी, राजेंद्र यादव, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, कुंवर नारायण, नामवर सिंह, चंचल चौहान, पंकज बिष्ट एवं रेखा अवस्थी के नाम प्रमुख हैं. इस मुहिम के अगुवा मुरली मनोहर प्रसाद थे. श्रीलाल जी वरिष्ठ आईएएस अफ़सर थे और उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव के पद से रिटायर हुए थे. लिहाज़ा उनके पास सीजीएचएस की सुविधा होनी चाहिए. इसके अलावा उनका भरा–पूरा समृद्ध परिवार है जो उनके इलाज के लिए स्वयं सक्षम है. दिल्ली में बीते 3 नवंबर को श्रीलाल जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ था. उससे भी ज़ाहिर होता है कि परिवार को पैसे की कमी नहीं है. लेखकों ने इस तरह की अपील जारी कर श्रीलाल जी का अपमान किया. बेवजह उनको दयनीय बनाने की कोशिश की गई. मुझे लगता है कि अगर जीते जी श्रीलाल जी को इस बात का पता चल गया होता तो वह बेहद नाराज़ होते. लखनऊ के उनके कई क़रीबी लोगों से मेरी बात हुई. सबने यही कहा कि श्रीलाल जी बेहद स्वाभिमानी व्यक्ति थे और अगर वह इसका प्रतिरोध करने की स्थिति में होते तो ज़रूर करते. मेरे हिसाब से इलाज की समुचित व्यवस्था कराने की अपील अनावश्यक और ग़ैर ज़रूरी थी. यह अपील जारी करके लेखकों ने श्रीलाल जी का घोर अपमान किया है और उन्हें माफ़ी मांग कर अपनी ग़लती सुधारनी चाहिए. क्या अशोक वाजपेयी, राजेंद्र यादव, पंकज बिष्ट, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह यह साहस दिखा पाएंगे और श्रीलाल जी और उनके परिवार से माफ़ी मांग कर मिसाल क़ायम करेंगे. करना चाहिए, बड़प्पन इसी में है.

*(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)*

anant.ibn@gmail.com

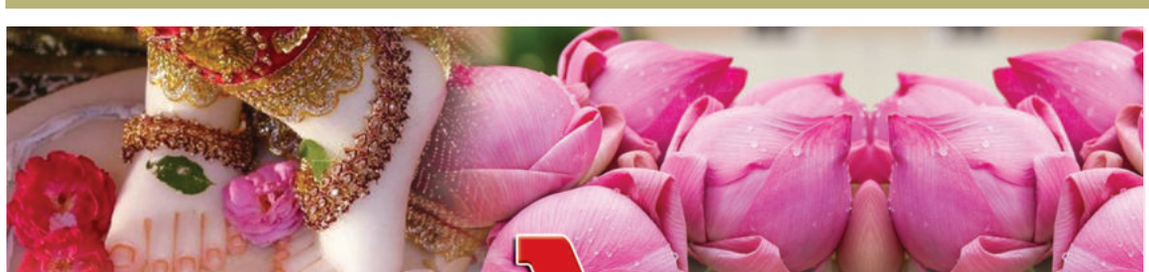

# पूजा के फूल

फूल...फ़िज़ा में भीनी–भीनी महक बिखेरते रंग–बिरंगे फूल किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफ़ी हैं...सुबह का कुहासा हो या गुलाबी शाम की ठंडक...पौधों को पानी देते वक़्त कुछ लम्हे बेला, गुलाब और चंपा–चमेली के साथ बिताने का मौक़ा मिल ही जाता है...गुलाबों में तो अभी नन्हीं कोंपलें ही फूट रही हैं, जबकि चमेली और चंपा के फूल शाम को महका रहे हैं...फूलों के बिना ज़िंदगी का तसव्वुर ही बेमानी लगता है...फूल प्रेम का प्रतीक हैं...आस्था और श्रद्धा प्रकट करने के लिए भी फूलों से बेहतर और कोई सांसारिक वस्तु नहीं है...कहते हैं कि देवी–देवताओं को उनके प्रिय फूल भेंट कर प्रसन्न किया जा सकता है... श्रद्धालु अपने इष्ट देवी–देवताओं को उनके प्रिय फूल अर्पित कर मनचाही मुराद पाते हैं...

हमारे देश में ख़ासकर हिंदू धर्म में विभिन्न धार्मिक कार्यों में फूलों का विशेष महत्व है. धार्मिक अनुष्ठान, पूजा और आरती आदि फूलों के बिना पूरे ही नहीं माने जाते हैं. भगवान विष्णु को कमल, मौलसिरी, जूही, चंपा, चमेली, मालती, वासंती, वैजयंती कदम्ब, केवड़ा और अशोक के फूल बहुत प्रिय हैं. भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है. इसलिए उनकी पूजा में पीले रंग के फूल विशेष रूप से शामिल किए जाते हैं. भगवान श्रीकृष्ण को परिजात यानी हरसिंगार, पलाश, मालती, कुमुद, करवरी, चणक, नंदिक और वनमाला के फूल प्रिय हैं. इसलिए उन्हें ये फूल अर्पित करने की परंपरा है. कहा जाता है कि परिजात का पेड़ स्वर्ग का वृक्ष है और यह देवताओं को बहुत प्रिय है. रुक्मणि को परिजात के फूल बहुत पसंद थे, इसलिए श्रीकृष्ण परिजात को धरती पर ले आए थे. भगवान शिव को धतूरे के फूल, नागकेसर के फूल, कनेर, सूखे कमल गट्टे, कुसुम, आक, कुश और बेल–पत्र आदि प्रिय हैं. सूर्य देव को कूटज के फूल, कनेर, कमल, चंपा, पलाश, आक और अशोक आदि के फूल भी प्रिय हैं. धन और एश्वर्य की देवी लक्ष्मी को कमल सबसे प्रिय है. उन्हें लाल रंग प्रिय है. देवी दुर्गा को भी लाल रंग प्रिय है और देवी सरस्वती को सफ़ेद रंग प्रिय है. इसलिए लक्ष्मी और दुर्गा को लाल और सरस्वती को सफ़ेद रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं. कमल का फूल सभी देवी–देवताओं को बहुत प्रिय है. इसकी पंखुड़ियां मनुष्य के गुणों की प्रतीक हैं, जिनमें पवित्रता, दया, शांति, मंगल, सरलता और उदारता शामिल है. इसका आशय यही है कि मनुष्य जब इन गुणों को अपना लेता है तब वह भी ईश्वर को कमल के फूल की तरह ही प्रिय हो जाता है. कमल कीचड़ में उगता है और उससे ही पोषण लेता है, लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग ही रहता है. यह इस बात का भी प्रतीक है कि सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन किस तरह गुज़ारा जाए. क़ाबिले–ग़ौर है कि किसी भी देवता के पूजन में केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते. ये फूल वर्जित माने जाते हैं...जबकि गणेश जी को तुलसीदल को छोड़कर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं. शिव जी को केतकी के साथ केवड़े के फूल चढ़ाना भी वर्जित है. देवी–देवताओं को उनके प्रिय फूल अर्पित कर उन्हें प्रसन्न करने और मनचाही मुरादें मांगने की सदियों पुरानी परंपरा है...

फ़िरदौस ख़ान
firdaus@chauthiduniya.com

किताब मिली

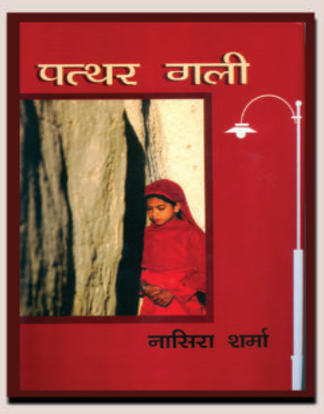


पुस्तक का नाम
पत्थर गली
लेखक
नासिरा शर्मा
प्रकाशक
राजकमल प्रकाशन
मूल्य
225 रुपये

यह किताब मुस्लिम समाज पर आधारित कहानियों का संग्रह है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

ब्राईट® की सभी के लिए उपयोगी पुस्तकें

FROM THE HOUSE OF : BRIGHT® Career's® BOOKS | COMPETITION REFRESHER | SCIENCE REFRESHER | G.K. GENERAL KNOWLEDGE REFRESHER

BRIGHT PUBLICATIONS®
Publishers of INDIA'S LARGEST SELLING Competition & School Books
2767, Kucha Chellan, Darya Ganj, New Delhi-110 002 (India) —— (ESTD. 1968)
Ph.: 011-64632226 & 3226, 23282226 & 3226 Fax: 011-23269227 Telefax: 64633226
E-mail: sales@brightpublications.com | Web Site: http://www.brightpublications.com

FOR VPP ORDERS, SEND ₹ 25/- AS ADVANCE & FOR FREE CATALOGUE WRITE TO US

एमटीएस ने नया स्मॉर्ट फोन लाइव वायर एंड्रॉयड लांच किया है. यह 2.2 फ्रोयो से लैस है और आधुनिक सीडीएमए ईवी-डीओ नेटवर्क पर चलता है.



# अनोखे लेंस स्पीकर

**इन्हें आप अपने कंप्यूटर में लगाकर म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हैं. इनमें 3.5 एमएम का जैक भी है, जिसकी मदद से आप इसे दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं.**

लोगों की नज़र में आने के लिए कंपनियां अपने उत्पादों में फीचर्स के साथ-साथ डिज़ाइन में भी कई तरह के प्रयोग करती रहती हैं. कार से लेकर मोटर साइकिल तक, डिज़ाइन में ऐसे फेरबदल किए जाते हैं कि उनसे नज़र ही नहीं हटती. स्टिल कैमरे बनाने वाली दिग्गज कंपनी निकॉन ने भी अपने एक नए उत्पाद में कुछ ऐसा ही किया है. देखने में तो ये बिल्कुल कैमरे के लेंस की तरह लगते हैं, मगर हैं लेंस की डिज़ाइन वाले ऑडियो स्पीकर. ये 55-200 एमए लेंस की तरह दिखते हैं. इन्हें आप अपने कंप्यूटर में लगाकर म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हैं. इनमें 3.5 एमएम का जैक भी है, जिसकी मदद से आप इसे दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं. लेंस के बैरल में स्पीकर कंट्रोल करने के लिए बटन का ऑप्शन है, जिसकी मदद से आप वॉल्यूम कंट्रोल करने के अलावा ऑडियो ट्रैक को पॉज़ भी कर सकते हैं. यही नहीं, इसमें माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट और यूएसबी पोर्ट की भी सुविधा है. देश के रिटेल सेंटरों के अलावा ऑनलाइन साइट ईबे पर निकॉन लेंस स्पीकर 1000 से लेकर 2000 रुपये में उपलब्ध हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# फॉर्मूला वन रेस कार बैट्री

**भारतीय रेसर नारायण कार्तिकेयन ने इन बैट्रियों का लांच किया. एचआरटी फॉर्मूला वन कारों के लिए एडवांस तकनीक से बनाई गई इस विशेष बैट्री का वजन 0.9 किलोग्राम है और यह 12 वोल्ट 2.3 एम्पीयर ऑवर बैट्री है.**

हाल में ग्रेटर नोएडा में हुई फॉर्मूला वन रेस का बुखार अभी तक लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है. भारत की पहली फॉर्मूला वन रेस में ट्रैक पर हवा से बातें करती कारों के लिए ऊर्जा का इंतज़ाम किया अग्रणी बैट्री निर्माता कंपनी बेस बैट्रीज ने. कंपनी ने फॉर्मूला वन एचआरटी टीम के साथ तकनीकी साझेदारी करके रेसिंग कारों के लिए विशेष बैट्रियां लांच कीं. भारतीय रेसर नारायण कार्तिकेयन ने इन बैट्रियों का लांच किया. एचआरटी फॉर्मूला वन कारों के लिए एडवांस तकनीक से बनाई गई इस विशेष बैट्री का वजन 0.9 किलोग्राम है और यह 12 वोल्ट 2.3 एम्पीयर ऑवर बैट्री है. बैट्री की लंबाई- चौड़ाई 1143987 मिमी है. बेस बैट्रीज के बिजनेस डेवलपमेंट प्रमुख कुलदीप वर्मा ने बताया कि इस बैट्री को एब्जॉर्ब्ड ग्लास मैट (एजीएम) सेपरेटर के साथ डिज़ाइन किया गया है. यह एक उन्नत टेक्नालॉजी है, जो बैट्री में पानी डालने की ज़रूरत हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है. इस बैट्री में कई ख़ास बातें हैं, जैसे बेहद डिस्चार्ज स्थिति से बेहतर चार्ज रिकवरी क्षमता, लंबा शेल्फ जीवन, बेहतर जीवन चक्र प्रदर्शन, परम कंपन प्रतिरोध, वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड (वीआरएलए) और ऐसी डिजाइन कि छलकने अथवा गिरने का डर नहीं. इससे बैट्री का पूरा एसिड विशेष प्लेट में समा जाता है. इसमें उन्नत लेड कैल्शियम टेक्नालॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसका विशिष्ट घनत्व परंपरागत लेड एंटिमनी बैट्री के मुक़ाबले तीन गुना समय तक बनाए रखती है. नारायण कार्तिकेयन ने भारतीय कंपनी द्वारा फार्मूला वन रेस कार बैट्री जैसा अभिनव उत्पाद बनाने पर ख़ुशी जताई. बेस बैट्रीज भारत की एक अग्रणी बैट्री निर्माता कंपनी है. यह उच्च गुणवत्ता वाली बैट्रियों, इनवर्टरों और यूपीएस का निर्माण करती है.

# लाइव वायर एंड्रॉयड

***यह स्मॉर्ट फोन गूगल मेल, यू-ट्यूब, गूगल टॉक और गूगल मैप्स तक आसान पहुंच प्रदान करता है. एंड्रॉयड 2,00,000 से अधिक एप्लीकेशनों तक की सुविधा मुहैया कराने में सक्षम है.***

सिस्तेमा श्याम टेली सर्विसेज लिमिटेड (एसएसटीएल) रूस के सिस्तेमा, रूसी सरकार और भारत के श्याम समूह के बीच इक्विटी भागीदारी से जुड़ा एक संयुक्त उपक्रम है, जिसमें सिस्तेमा बड़ी हिस्सेदार है, जो एमटीएस ब्रांड के तहत दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराती है. एमटीएस ने नया स्मॉर्ट फोन लाइव वायर एंड्रॉयड लांच किया है. यह 2.2 फ्रोयो से लैस है और आधुनिक सीडीएमए ईवी-डीओ नेटवर्क पर चलता है, जो यात्रा के दौरान भी हाई स्पीड डेटा तक पहुंच प्रदान करता है. यह स्मॉर्ट फोन गूगल मेल, यू-ट्यूब, गूगल टॉक और गूगल मैप्स तक आसान पहुंच प्रदान करता है. एंड्रॉयड 2,00,000 से अधिक एप्लीकेशनों तक की सुविधा मुहैया कराने में सक्षम है. एमटीएस एमटैग 3.1 स्मॉर्ट फोन 2.8 इंच की टच स्क्रीन से लैस है, जो 240/320 पिक्सल डिस्प्ले पेश करती है.

# स्टाइलिश लेनोवो लैपटॉप

**लिनोवो बी-570 में साधारण डीवीडी राइटर के साथ नई ब्लू रे डिस्क है. अगर आप तेज म्यूज़िक का मज़ा लेना चाहते हैं तो लैपटॉप से 2.0 वर्जन के एक्सटर्नल स्पीकर अटैच कर सकते हैं. इसमें इनबिल्ड 0.3 मेगा पिक्सल कैमरा है, जिसके साथ आप अपने दोस्तों से वीडियो चैटिंग कर सकते हैं.**

पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप के क्षेत्र में लिनोवो की एक अलग पहचान है. हाल में लिनोवो ने बी-570 नामक नया बजट लैपटॉप लांच किया है. लिनोवो बी-570 में एडवांस तकनीक के साथ कई नए फीचर्स हैं. इसमें विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ 15.6 इंच की बड़ी ग्लॉसी स्क्रीन है, जो 1366/768 पिक्सल रेज्योलूशन की वजह से किस्टल क्लियर पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करती है. लैपटॉप में 2310 एम का इंटल कोर आई-3 प्रोसेसर है, जो इसे फास्ट परफार्मेंस प्रोवाइड करता है. लिनोवो बी-570 में साधारण डीवीडी राइटर के साथ नई ब्लू रे डिस्क है. अगर आप तेज म्यूज़िक का मज़ा लेना चाहते हैं तो लैपटॉप से 2.0 वर्जन के एक्सटर्नल स्पीकर अटैच कर सकते हैं. इसमें इनबिल्ड 0.3 मेगा पिक्सल कैमरा है, जिसके साथ आप अपने दोस्तों से वीडियो चैटिंग कर सकते हैं. फास्ट परफार्मेंस के लिए लिनोवो-570 में 320 जीबी हार्डड्राइव के साथ 3 जीबी रैम है. इस बजट लैपटॉप में ब्लूटुथ, वाईफाई एवं यूएसबी पोर्ट जैसे कई कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ इंटल 82579-एलएम गीगा बिट लेन कनेक्टिविटी की सुविधा है, जो लिनोवो बी-570 की क़ीमत देखते हुए एक अच्छा फीचर है. इसका भार 2.37 किलो है. कोर आई 3-2310 एम प्रोसेसर से लैस बी-570 की क़ीमत 30 हज़ार रुपये है.

# वायरलेस माउस

**यह वेब ब्राउजिंग के लिए ख़ास तौर पर उपयुक्त है. इसमें 1600 डीपीआई सेंसर और स्क्रोल व्हील इस तरह फिट हैं कि गेम खेलने वालों और सामान्य यूजर्स को गूगल सर्च या दूसरे ब्राउजिंग टूल ऑपरेट करने में आसानी हो. इस वायरलेस माउस में एक अनूठा व्हील है, जो नेविगेशन का एक अलग अनुभव देता है.**

टॉप नॉच इंफोट्रॉनिक्स ने नवीनतम वायरलेस ब्लूटुथ माउस ब्लूक मो पेश किया है, जो तार के जंजाल से मुक्ति दिलाता है. इसकी ख़ूबसूरत डिज़ाइन एवं आसान पकड़ ब्राउजिंग और नेविगेशन बेहद आसान बना देती है. इसमें स्मार्ट स्लीप मोड है और उन्नत 3.0 ऑप्टिकल तकनीक से लैस ऑन/ऑफ स्विच भी. यह ख़राब से ख़राब सरफेस पर भी अच्छा काम करता है और कम ऊर्जा की खपत कर बैट्री की लाइफ बढ़ाता है. अच्छे आकार और बेहतर ग्रिप के कारण ब्लू मो बिना किसी रुकावट या खिंचाव के लगातार काफी देर तक इस्तेमाल किया जा सकता है. यह वेब ब्राउजिंग के लिए ख़ास तौर पर उपयुक्त है. इसमें 1600 डीपीआई सेंसर और स्क्रोल व्हील इस तरह फिट हैं कि गेम खेलने वालों और सामान्य यूजर्स को गूगल सर्च या दूसरे ब्राउजिंग टूल ऑपरेट करने में आसानी हो. इस वायरलेस माउस में एक अनूठा व्हील है, जो नेविगेशन का एक अलग अनुभव देता है. इसके ज़रिए आप लंबे वेब पेज पर भी आसानी और तेजी से स्क्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा यह आपको महज़ स्वाइप कर वेब पेज पर आगे-पीछे (फारवर्ड-बैकवर्ड) जाने की सुविधा देता है. टॉप नॉच इंफोट्रॉनिक्स के कंट्री मैनेजर राजेश दोषी ने कहा कि तेज स्क्रोलिंग, व्हील नेविगेशन और लेजर ग्रेड प्रिसीजन जैसी ख़ूबियों के ज़रिए वेब सर्फिंग बेहद आसान हो सकती है.

ब्लू मो बेजोड़ प्रदर्शन और आराम का तालमेल पेश करता है और डिजिटल दुनिया से जुड़े रहने में काफी मदद करता है. यह हर बार इस्तेमाल पर अपने आप रि-कनेक्ट हो जाता है और बिना किसी व्यवधान के काम करने लगता है. 1600 डीपीआई सेंसर तकनीक स्क्रीन से 10 मीटर तक की दूरी से ऑपरेशन सुनिश्चित कराती है. ब्लूटुथ ब्लू मो पूरी तरह वायरलेस कनेक्टिविटी देता है और रिसीवर, यूएसबी पोर्ट या अन्य डिवाइस की ज़रूरत पूरी तरह ख़त्म कर देता है.

राजधानी दिल्ली में राडो घड़ी की शानदार नई सीरीज पेश करतीं मॉडल्स.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

# क्या यह आर्थिक शक्ति का अश्लील प्रदर्शन है!




राजेश एस कुमार

आख़िरकार तमाम ब्रेकरों को पार करते हुए बुद्धा सर्किट में फॉर्मूला वन रेस का महाआयोजन संपन्न हो गया. रेस के बाद अंतराष्ट्रीय पॉप स्टार लेडी गागा का शो भी धूमधड़ाके के साथ रात भर चला. हालांकि शुरुआत में रेसिंग ट्रैक पर अचानक कुत्ता घुस जाने, प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बिजली गुल होने और मीडिया सेंटर में चमगादड़ उड़ता दिखने केकारण कुछ आशंकाएं ज़रूर उठीं, लेकिन फॉर्मूला वन रेस संपन्न हो गईं. सचिन तेंदुलकर ने हरी झंडी दिखाई, वहीं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने तीनों विजेता रेसरों को ट्रॉफी से नवाजा. रफ्तार और रोमांच की इस रेस में जर्मनी के 24 वर्षीय सेबस्टियन वेटल सब पर भारी पड़े. रेड बुल टीम के इस विश्व चैंपियन ड्राइवर ने प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर आयोजित पहली इंडियन ग्रां प्री जीत ली. मैक्लारेन के ड्राइवर ब्रिटेन के जेंसन बटन दूसरे और फेरारी के सवार स्पेन के फर्नांडो अलोंसो तीसरे स्थान पर रहे. घरेलू टीम सहारा फोर्स इंडिया के लिए भी यह रेस उपलब्धि भरी रही. इसके ड्राइवर एड्रियन सुतिल ने 9वें स्थान पर रहकर दो अंक अर्जित किए. भारत के दिग्गज फॉर्मूला वन रेसर नारायण कार्तिकेयन ने 17वां स्थान हासिल किया. रेस की शुरुआत से ही वेटल ने बढ़त हासिल की और अंत तक उसे बरक़रार रखा. 60 लैप की इस रेस में कोई भी ड्राइवर उन्हें चुनौती देता नज़र नहीं आया. देश-विदेश से आए दर्शकों का उत्साह देखते हुए एफ-वन के बाद बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर मोटो जीपी मोटरसाइकिल रेस कराने की तैयारी शुरू हो गई है. सूत्रों के मुताबिक़, मार्च 2012 तक लोग मोटरसाइकिल रेस का भी आनंद ले सकेंगे. वहीं अक्टूबर 2012 में फिर एफ-वन रेस का आयोजन होगा. यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे स्थित जेपी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में एफ-वन ट्रैक के निर्माण के साथ ही मोटरसाइकिल रेस कराने की भी तैयारी शुरू हो गई थी. रेस के लिए कंपनी को अभी इंटरनेशनल मोटो स्पोर्ट्स से अनुमति नहीं मिल पाई है. कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक़ , मोटो जीपी की अनुमति जल्द मिल जाएगी. इस तरह के आयोजन में होने वाले फ़ायदे को देखते हुए स्पोर्ट्स कार कंपनी फरारी ने बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक चैलेंजर सीरीज कराने की योजना बनाई है. फरारी स्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमेदेव फेलिसा के मुताबिक़, हमारा विचार है कि क्यों न हम भी अपनी चैलेंजर सीरीज रेसिंग प्रतिस्पर्धा और ग्राहक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करें, क्योंकि भारत में एक विश्वस्तरीय ट्रैक उपलब्ध है.

लेडी गागा के शो में जिस तरह ग्लैमर का तड़का लगाती सेलेब्रिटीज नज़र आईं, वैसे तो एकबारगी लगा कि मानों आईपीएल का जश्न मनाया जा रहा हो. ऐसा लगना इसलिए लाज़िमी है, क्योंकि पूरे आयोजन में जिस तरह पैसा, ग्लैमर और पार्टी का कॉकटेल दिखा, उसका ट्रेंड भारत में आईपीएल के फटाफट क्रिकेट ने ही शुरू किया है. आपको याद होगा कि पिछली बार आईपीएल में लेडी गागा की तरह अंतरराष्ट्रीय पॉप सिंगर एकॉन का शो रखा गया था. रेस के बाद हुई पार्टी में लेडी गागा ने जहां एक ओर सभी को लुभाया, वहीं अपने आपत्तिजनक माइक के ज़रिए विवाद भी खड़ा कर दिया. पुरुष जननांग के आकार के माइक पर अब काफी शोर मच रहा है, लेकिन जो लोग लेडी गागा को जानते हैं, उन्हें उनके इस क़दम से कोई आश्चर्य नहीं होगा. गागा के लिए ऐसा विवाद नया नहीं है. वह इससे पहले भी कई बार अश्लीलता की हद पार कर चुकी हैं. गागा पर अमेरिका में पॉप के ज़रिए पॉर्न को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं. उनके कई गाने बच्चों के लिए प्रतिबंधित किए गए हैं. जिस तरह आईपीएल में विभिन्न टीमों के मालिक अपनी-अपनी टीम के साथ मौजूद थे, उसी तरह विजय माल्या और सुब्रतो रॉय समेत कई मालिक अपने टीम रेसरों के साथ ग्रेटर नोएडा में मौजूद थे और साथ में थीं सचिन, शाहरुख, प्रीति, अर्जुन रामपाल, दीपिका, सोनम और अनिल कपूर जैसी हस्तियां. नजारा भी वही और शक्लें भी वही. कुल मिलकार इसे आईपीएल का एक्टेंडेड वर्जन कहा जा सकता है.

ग़ौर करने वाली बात यह है कि बुद्धा सर्किट में फॉर्मूला वन रेस के इस महाआयोजन में केंद्रीय खेल मंत्री अजय माकन को आमंत्रित नहीं किया गया. हालांकि आयोजकों की ओर से कहा गया कि उन्हें पास भेजे गए थे, लेकिन अजय माकन कहते हैं कि उन्होंने आयोजकों को 100 करोड़ रुपये की कर माफी नहीं दी, इसलिए उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ. बात सिर्फ़ वर्तमान खेल मंत्री तक सीमित नहीं है. अभी हाल में जब पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री मणिशंकर अय्यर से इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने इस फॉर्मूला वन रेस को बेतुका खेल बता डाला. उनके मुताबिक़ , रेसिंग बेहद बेतुका खेल है और इससे बड़ी मात्रा में रबर और ईंधन की बर्बादी होती है, जिन्हें आयात करना पड़ता है. फॉर्मूला वन को कर माफी के सवाल पर उन्होंने कहा, यह ट्रैक किसानों से अधिग्रहीत ज़मीन पर बनाया गया है और अधिग्रहण भी औने-पौने दामों पर किया गया. इसके बावजूद एफ वन के आयोजक चाहते हैं कि उन्हें इसके प्रचार-प्रसार के लिए कर में पूरी छूट दे दी जाए. यह कहीं से जायज़ नहीं है. इस तरह के खेलों के लिए टैक्स माफी जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए. एफ वन को बेवजह प्राथमिकता दी जा रही है. यह हमारी आर्थिक ताक़त का अश्लील प्रदर्शन है और पता नहीं, हम किस तरह की संस्कृति को प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं. इस बात से सभी वाक़िफ़ हैं कि ऐसे खेलों के आयोजन का मक़सद एक ख़ास वर्ग का शौक पूरा करना होता है, लेकिन इन चकाचौंध भरे कार्यक्रमों की रोशनी तले कितने किसानों और खेतों का ख़ात्मा होता है, उस तरफ़ लोगों की नज़र नहीं जाती. जेपी ग्रुप के स्पोर्ट्स कांप्लेक्स पर नज़र दौड़ाई जाए तो मालूम होगा कि कितना बड़ा भूभाग इस तमाशे की शोभा बढ़ा रहा था. जिस देश में लोग दो जून की रोटी और सिर ढकने के लिए एक छत के लिए तरस रहे हों, वहां ऐसे तमाशों के स्थान पर कई दूसरे महत्वपूर्ण काम किए जा सकते हैं. मणिशंकर की बात भले ही थोड़ी दकियानूसी लगती हो, लेकिन उनकी बातों पर ग़ौर करना चाहिए.

rajeshy@chauthiduniya.com

यह ट्रैक किसानों की ज़मीन का औने -पौने दामों पर अधिग्रहण करके बना है. इस तरह के खेलों के लिए टैक्स माफ़ी जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए.
- मणि शंकर अय्यर


मैं कोई स्टार-आइटम गर्ल नहीं हूं, जो मुझे निमंत्रण मिले. जब हम उन्हें टैक्स में माफ़ी नहीं दे रहे हैं तो उनसे निमंत्रण की उम्मीद भी नहीं कर सकते.
- अजय माकन







ETV पर देखिए दो टूक
देश का सबसे निर्णायक टीवी कार्यक्रम

शनिवार रात 8 : 30 बजे
रविवार शाम 6 : 00 बजे
ईटीवी के सभी हिन्दी चैनलों पर

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 14 नवंबर–20 नवंबर 2011

गागा जब इंडिया आईं तो इस बार उनके कपड़ों एवं माइक ने उन्हें विवादों में डाल दिया. लेडी गागा ने दिल्ली में अपने प्रशंसकों का अभिवादन नमस्ते कहकर किया.



# अभिनय मेरा शौक़ है, राजनीति मेरा पेशा

*सियासत को हमेशा अभिनय से जोड़ा जाता है और अभिनय में कई दफा सियासत करनी पड़ती है. बिहार के दिग्गज राजनीतिज्ञ, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सदस्य रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान फिल्म मिले ना मिले हम के ज़रिए बॉलीवुड में अपनी पारी शुरू की है. एक कहावत है, दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए, लेकिन रामविलास पासवान कहते हैं कि जब तक दिल न मिले, हाथ न मिलाइए. पिता की इसी बात से जोड़ते हुए बेटे चिराग पासवान ने अपनी पहली फिल्म का नाम रख दिया, मिले ना मिले हम. हालांकि इसका नाम पहले मी एंड ओनली रखा गया था. पिछले दिनों चौथी दुनिया की एडिटर (इंवेस्टिगेशन) रूबी अरुण ने उनसे एक लंबी बातचीत की. पेश हैं मुख्य अंश:*

*चिराग, यह शुरुआत अभिनय से सियासत की ओर है या सियासत से अभिनय की ओर?*

मैं किसी को भी माध्यम नहीं बना रहा हूं, न सियासत और न अभिनय को. सियासत तो मेरी रगों में है. मैं राजनीति से दूर नहीं था और मुझे ख़ुद लोगों से मिलने का शौक रहा है. मैं ख़ुशनसीब हूं कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, जहां मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूं. पापा के साथ चुनावी दौरे पर जाने या रैलियों में जाकर लोगों से सीधे मिलने का मौक़ा मिलता है, लेकिन अभिनय का शौक बचपन से रहा और इसी शौक को पूरा करने के लिए मैं यहां हूं.

*जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं, तब तमाम लोगों से रूबरू होते हैं. जब फिल्मों में हीरो का किरदार निभाते हैं तो ग्लैमर का टैग लग जाता है. आप उसमें भी लोगों से मिलते हैं, लेकिन उसमें एक दूरी आ जाती है. इस दूरी को आप कैसे पाटेंगे?*

मुझे ऐसा नहीं लगता कि ग्लैमर का टैग मुझ पर लगेगा, इसकी वजह से मुझे लोगों से दूर होना पड़ेगा या होने की कोशिश करनी पड़ेगी. आज भी मैं उतना ही साधारण हूं और आने वाले पांच वर्षों तक ऐसा ही रहूंगा. मैंने आपको बताया भी कि लोगों से मिलना मेरा शौक है, अगर अपने आसपास भीड़ नहीं दिखती या लोग नहीं दिखते तो मुझे घबराहट होती है, क्योंकि मैं ऐसे घर में पला-बढ़ा हूं, जहां आदत सी हो गई है लोगों के बीच रहने की. उनसे दूर रहना या उन्हें अवाइड करने की बात मैं सोच भी नहीं सकता.

*आप बिहार चुनाव में गए, पापा की पार्टी के लिए आपने प्रचार भी किया. उस वक़्त कहा जा रहा था कि आप और तेजस्वी मिलकर राहुल के ख़िलाफ़ लामबंदी करेंगे, इसमें आप लोग थोड़े सफल भी हुए, लेकिन अभिनय के क्षेत्र में आना उस चीज के लिए बंदिशें तो नहीं पैदा करेगा?*

नहीं, बिल्कुल नहीं. उस वक़्त भी हम राहुल के ख़िलाफ़ नहीं थे. मैं पार्टी लाइन से हटकर कहूंगा कि मैं राहुल जी का बहुत आदर करता हूं. उन्होंने युवाओं को राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया, यह बहुत अच्छा काम है. कहीं न कहीं युवाओं का राजनीति से विश्वास उठता जा रहा था. जो मुहिम उन्होंने शुरू की है, मैं उसमें उनका हाथ बंटाना चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा राजनीति से जुड़ें. हम युवा मिलकर अपनी पार्टी भूलकर यह काम करें तो यह देशहित में होगा.

*यह आपने बहुत अच्छी बात कही कि पार्टी लाइन भूलकर किसी फिल्म में ऐसा किरदार करने की ख्वाहिश है, जिसके ज़रिए आप लोगों को संदेश दे सकें कि देश के लिए कुछ करना है...*

बिल्कुल, ऐसा किरदार करने की ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं राजनीतिज्ञ का किरदार पर्दे पर निभाना चाहूंगा या नहीं. अगर निभाना चाहूंगा तो वह अलग होगा. जिस तरह इंडस्ट्री में राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और सरकारी नौकरीपेशा लोगों की जो छवि बना दी गई है, कहने का मतलब यह कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होतीं, अच्छे-ग़लत लोग हर क्षेत्र में होते हैं, इसलिए केवल राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों को ही फोकस क्यों किया जाता है. मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस छवि को सुधारूं.

*फिल्म में मुख्यत: दो धाराएं चलती हैं, सार्थक सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा. इन दो चीजों को, चूंकि आपको पढ़ने का शौक रहा है और जो पढ़ने का शौक रखता है, वह उसे अपनी कल्पना में उतारता है. कभी आपके जेहन में ऐसा कोई किरदार आता है या जब आप एक्टिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो चीज आपने पढ़ी है, वह आपके किरदार से मैच करती है और इस चीज को जिस तरह निर्देशक कह रहा है, वैसे पेश न करके किसी दूसरे तरीक़े से पेश किया जाए, जो लोगों के दिलों को छुए. क्या इस तरह की कभी कशमकश होती है?*

कई बार ऐसी कशमकश रही कि हमारे डायरेक्टर ने यह बोला, लेकिन पर्सनली मैं उसे दूसरी तरह करने में कंफर्टेबल हूं. मेरी पहली फिल्म मिले ना मिले हम में एक ऐसे लड़के की कहानी है, जो एक ब्रोकेन फैमिली से आता है और मैं एक संयुक्त परिवार से हूं. कितनी बार यह किरदार एक वेयर्ड वे में रिएक्ट करता था, जो मुझे समझ में नहीं आता था कि यह इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि मैं उसकी जगह होता तो नहीं कर पाता, लेकिन एक्टर का काम यही है कि वह अपने किरदार में जान डाल दे, उसे समझे और उसकी ज़िंदगी जिए. मैंने इस फिल्म में यही कोशिश की और आगे भी यही करूंगा.

*मुश्किलें क्या आती हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप एक अनुशासित परिवार से आते हैं, तीनों भाई साथ रहते हैं, बड़े मर्यादित तरीक़े से आपका पालन-पोषण हुआ. ऐसे में उस परिवेश में जाना, जहां बिल्कुल खुलापन है, वहां आप कैसे तालमेल बैठाते हैं?*

इसका पूरा श्रेय मेरे परिवार को जाता है, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया. परिवार का प्रोत्साहन ही मुझे हर संघर्ष और विषम परिस्थितियों से निपटने में काफी मदद करता है. पारिवारिक सहयोग-समर्थन के चलते सारी चीजें मेरे लिए काफी सरल सी हो जाती हैं.

*मैं फिर राजनीति और अभिनय को जोड़ रही हूं, चूंकि अभी जो स्थिति है, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने शौक यानी अभिनय के सहारे अपने पेशे यानी पार्टी को मज़बूत बनाना चाहते हों, उसे एक मज़बूत जमीन देना चाहते हों?*

नहीं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है. अगर ऐसा कुछ होता है तो ग़लत भी नहीं है. लेकिन ऐसी मंशा रखकर, यह सोचकर मैंने कोई योजना नहीं बनाई कि पहले एक्टिंग के क्षेत्र में उतरूं, जिससे पार्टी को फ़ायदा मिले. अभिनय मेरा शौक है और राजनीति मेरा पेशा, यह दोनों चीजें अच्छी तरह चलें, यही कामना है.

feedback@chauthiduniya.com

# तुम जियो हजारों साल

## मीनाक्षी शेषाद्री : ख़ूबसूरती और अभिनय का संगम

अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्रि का जन्म वर्तमान झारखंड प्रांत के सिंदरी नामक शहर में 16 नवंबर को हुआ था. वैसे तो मीनाक्षी मूलत: तमिलनाडु से हैं, परंतु उनके पिता सिंदरी स्थित उर्वरक कारखाने में कार्यरत थे, इसलिए उनका परिवार इसी शहर में बस गया था. ख़ूबसूरती और नृत्य का जो संगम मीनाक्षी ने पर्दे पर पेश किया, उसकी नींव बचपन में रखी गई थी. चार साल की उम्र से ही उन्होंने मंच पर भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी. हालांकि उन्हें यह मालूम नहीं था कि आगे चलकर यही परफार्मेंस उन्हें सिल्वर स्क्रीन की तरफ़ खींच ले जाएगा. उन्होंने भरतनाट्यम, कत्थक एवं ओड़िसी जैसे भारतीय नृत्यों की विधिवत शिक्षा प्राप्त की. 1981 में मिस इंडिया बनीं मीनाक्षी के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई हिंदी फिल्म पेंटर बाबू से, जिसमें उनके साथ थे मनोज कुमार के भाई राजीव गोस्वामी. इसके बाद सिल्वर स्क्रीन पर जादू बिखेरने की जो अदा मीनाक्षी ने अपनाई, उसने लोगों को उनका कायल बना दिया. हीरो, मेरी जंग, विजय, शहंशाह, घायल, दामिनी एवं डुएट जैसी लाजवाब फिल्मों ने उनकी कामयाबी की दास्तान लिखी. 15 साल के करियर में उन्होंने लगभग 80 फिल्मों में काम किया. मीनाक्षी ने नृत्य का शौक बरक़रार रखा. 2006 में 50 साल की उम्र में पुणे के एक उत्सव में ख़ूबसूरत नृत्य पेश किया. मीनाक्षी के जीवन में यू-टर्न तब आया, जब उनकी एक ख़ास सहेली ने उन्हें किसी पार्टी के दौरान अपने भाई हरीश मायर से मिलवाया. पार्टी के बाद मीनाक्षी हरीश से मिलने लगीं. अमेरिका में इंवेस्टमेंट बैंकर के पद पर काम कर रहे हरीश मीनाक्षी के दिल में बस गए और फिर दोनों परिणय सूत्र में भी बंध गए. परिवार को महत्व देने वाली मीनाक्षी ने पति के साथ टेक्सास में रहने का फ़ैसला कर लिया और अपने फिल्मी सफर को विराम दे दिया. टेक्सास जाकर उनकी ज़िंदगी बदल गई. ड्राइविंग से भय खाने वाली मीनाक्षी ने वहां पहुंच कर सबसे पहले कार चलाना सीखा. हरीश के प्यार एवं सहयोग ने वहां की दूसरी परेशानियों से पार पाने में मदद की. इस बीच मीनाक्षी ने दो प्यारे बच्चों को जन्म दिया. मीनाक्षी सुपर मॉम बनकर टेक्सास की सड़कों पर कार भी चलाती हैं और अपनी बेटी एवं बेटे को उनके हॉबी क्लासेस-स्कूल आदि ले जाती हैं. मीनाक्षी ने पति के सहयोग से अपने शौक पर भी ध्यान दिया और अमेरिका में एक डांसिंग स्कूल की शुरुआत की, जहां वह अपने सपनों को आकार दे रही हैं. फिल्म इंडस्ट्री की तरफ़ वापसी का विचार उनका नहीं है, क्योंकि परिवार उनकी पहली प्राथमिकता है, लेकिन इंडस्ट्री में उनके योगदान को कभी कम नहीं आंका जा सकता. उनकी इसी उपलब्धि पर फिल्म निर्माता मार्गेट स्टीफंस दो घंटे की म्यूजिकल डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं.

# क़िस्मत की धनी नूपुर

हल्की भूरी आंखों और लंबे भूरे बालों वाली नूपुर पटवर्धन को यक़ीन नहीं था कि उनकी क़िस्मत इस तरह करवट लेगी. करियर की शुरुआत में अक्षय कुमार जैसे अभिनेता के साथ स्क्रीन शेयर करना मामूली बात नहीं, चाहे वह कोई विज्ञापन ही क्यों न हो. अक्षय के साथ कोल्डड्रिंक थम्सअप के विज्ञापन में काम करने वाली प्रख्यात मॉडल नूपुर पटवर्धन डायरेक्टर राकेश जैन की आने वाली फिल्म ये स्टूपिड प्यार में मुख्य भूमिका में नज़र आएंगी. नूपुर ने पिछले साल बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो से कोर्स किया है. ये स्टूपिड प्यार उनकी पहली फिल्म है, जिसके हीरो हैं जतिन. उनकी भी यह पहली फिल्म है. नूपुर कहती हैं कि वह इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं और ख़ुद को बहुत लकी मानती हैं. फिल्म की कहानी दो युवा प्रेमियों पर आधारित है, जो असमंजस में हैं कि उन्हें प्यार है कि नहीं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# गागा का जलवा

मदर ऑफ मोनेस्टर उर्फ पॉप स्टार लेडी गागा और विवादों का चोली-दामन का साथ है. ट्वीटर पर जिसके एक करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर हों, वह यदि विवादों में आए तो सुर्ख़ियां बनना लाज़िमी है. गागा जब इंडिया आईं तो इस बार उनके कपड़ों एवं माइक ने उन्हें विवादों में डाल दिया. लेडी गागा ने दिल्ली में अपने प्रशंसकों का अभिवादन नमस्ते कहकर किया. फॉर्मूला वन रेस के अवसर पर हुए उनके कार्यक्रम के टिकट का दाम 40 हज़ार रुपये था, बावजूद इसके लोगों में ज़बरदस्त उत्साह देखा गया. ग्रेटर नोएडा के जेपी इंडिग्रेडेट कांप्लेक्स में हुए इस कार्यक्रम में गागा का जादू सिर चढ़कर बोला. इस मौक़े पर शाहरुख ख़ान, गौरी ख़ान, सोनम कपूर, बिपाशा बसु, अनिल कपूर, चंकी पांडे, अर्जुन रामपाल, इमरान ख़ान, प्रीति जिंटा, दीपिका पादुकोण, संजय कपूर, फरदीन ख़ान, क्रिकेटर युवराज सिंह, आशीष नेहरा, उद्योगपति विजय माल्या एवं सिद्धार्थ माल्या की मौजूदगी ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए.

## फिल्म प्रीव्यू

### शक्ल पे मत जा

निर्देशक शुभ मुखर्जी ने देश में हुए आतंकी हमलों पर एक फिल्म बनाई है, जिसका नाम है शक्ल पे मत जा. एक्टर-प्रोड्यूसर हृषिता भट्ट की इस फिल्म की शूटिंग बिना अनुमति के संसद परिसर में हो गई. देश के अति सुरक्षित क्षेत्र में जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तब सुरक्षाकर्मी तमाशा देख रहे थे. फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग दिल्ली एयरपोर्ट और संसद परिसर में हुई है. 2001 में संसद में जिस जगह हमला हुआ था, उसी जगह शूटिंग हुई. शूटिंग करते वक़्त उन्हें किसी ने नहीं रोका. जबकि इस फिल्म की शूटिंग से पहले जब उन्होंने एक डाक्यूमेंट्री के लिए संसद परिसर में शूटिंग करनी चाही थी, उस समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. फिल्म की कहानी चार ऐसे युवकों पर आधारित है, जिन्हें आतंकवादी होने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया जाता है. निर्देशक के अनुसार, इसके बाद चारों युवक व्यवस्था की पोल खोलने का फ़ैसला करते हैं, वे कड़ी सुरक्षा वाले इलाक़ों में बम लगाते और फिर ख़ुद उन्हें बेकार करते हैं. अपनी इन हरकतों की वे रिकॉर्डिंग भी करते हैं, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि कड़ी सुरक्षा वाले स्थानों पर कैसी ख़ामियां हैं. शुभ का कहना है कि फ़िल्म शक्ल पे मत जा क़रीब आठ महीने पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर हुई एक वास्तविक घटना पर आधारित है. घटना के पीड़ितों में वह ख़ुद भी शामिल हैं. मुखर्जी ने बताया कि उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर संदेहवश रोक लिया गया था. तस्वीरें लेते समय पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और आठ घंटे से ज़्यादा पूछताछ की. हृषिता भट्ट ने फ़िल्म में अभिनय नहीं किया है, मगर पटकथा बेहतर होने के कारण उन्होंने सह निर्माता बनने का फ़ैसला किया.

# चौथी दुनिया

दिल्ली, 14 नवंबर–20 नवंबर 2011

www.chauthiduniya.com

# कौन दूर करेगा ग़रीबों का दर्द

प्रवीण महाजन

राज्य में ग़रीबी ख़त्म हो गई है या ग़रीब ख़त्म हो गए हैं? अथवा ग़रीबों का मज़ाक़ बनाया जा रहा है? बात कुछ भी हो राजा से रंक बनने और रंक से राजा बनने की कहावत के चरितार्थ होने का चमत्कार होना ही भारतीय संस्कृति में कहा जाता है. आज के दौर में अमीरों के ग़रीब बनने और ग़रीब के अमीर बनने का चमत्कार सिर्फ़ कैसिनो (जुआघर) और टी.वी. शो में ही देखा जा सकता है. महाराष्ट्र सरकार दावा करती है कि राज्य प्रगति की ओर अग्रसर है. इसकी गणना देश के विकासशील राज्यों में की जाती है. औद्योगिक विकास के साथ ही राज्य में ग़रीबी का निर्देशांक कम हो रहा है, लेकिन ग़रीबी के कम होते निर्देशांक का असर कहीं दिखाई नहीं देता है. वास्तविक तस्वीर यही है कि राज्य में ग़रीबी कहीं कम होती दिखाई नहीं देती है. शहरों की चमक-दमक के बीच आज भी ग़रीबी मुरझाई हुई खड़ी नज़र आती है. वहीं तेज़ी से बढ़ रही बेरोज़गारी के साथ ही ग़रीबी भी अपने पैर पसार रही है. इसी बीच ख़बर आती है कि देश के शीर्ष पूंजीपतियों व उद्योगपतियों की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई है. श्रीमंत ग़रीब हो रहे हैं. श्रीमंत के ग़रीब होने की बात हज़म नहीं होती है. उसकी वजह है यह है कि राज्य में झोपड़-पट्टियों का विस्तार तेज़ी से हो रहा है. राज्य के 31 प्रतिशत लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है. दो वक़्त की रोटी के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है. ऐसे हालात में महलों में रह रहे अमीरों की संपत्ति में कुछ कमी होने को उनके ग़रीब होने की बात कहना ग़रीबों का मज़ाक़ नहीं तो और क्या कहा जाएगा?

एक ओर शहरी क्षेत्र में 32 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 26 रुपये रोज़ ख़र्च करने वालों को सरकार ग़रीब नहीं मानती है. उन्हें ग़रीबी रेखा से ऊपर बताकर ग़रीबों का मज़ाक़ उड़ाया जाता है. वहीं हर रोज़ हज़ारों रुपये अपने खाने पर ख़र्च करने वाले पूंजीपतियों के ग़रीब होने की बात कही जाती है. अरबपतियों की पूंजी में 10-15 प्रतिशत की कमी आने से उनके रहन-सहन पर आख़िर क्या फ़र्क़ पड़ता है? उनके गाड़ी, बंगले, फैक्ट्रियां बिक तो नहीं जाती हैं? दूसरी ओर ग़रीब की कमाई में दस रुपये की कमी भी आती है तो उसको अपने बिगड़े बजट को बनाने में काफ़ी आगे-पीछे सोचना पड़ता है. इसलिए मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, रतन टाटा, बिरला समूह व देश के अन्य जाने-माने उद्योगपतियों की संपत्ति पर आने वाले उतार-चढ़ाव पर पूरा मीडिया संवेदनशील हो उठता है, लेकिन ग़रीब की दुर्दशा में आने वाले बदलाव की ओर देखने की फ़ुर्सत किसी को नहीं रहती है. संभवत: यही वजह है कि महाराष्ट्र के अख़बारों में श्रीमंतों के ग़रीब होने की न केवल ख़बरें छपीं, बल्कि उन पर लंबे-चौड़े संपादकीय भी लिखे गए, लेकिन राज्य में महंगाई से हलकान ग़रीबों के बिगड़ते बजट की तस्वीर कहीं दिखाई नहीं दी.

ग़ौरतलब है कि 1991 में चली आर्थिक सुधार के झोंके में राज्य व देश के उद्योगपति देखते-देखते अरबपति हो गए. इस आर्थिक सुधार का करिश्मा ऐसा था कि अमीर और अमीर होता गया व ग़रीब और ग़रीब होता गया. नतीजतन साल 2010 में देश में अरबपति क्लब के 57 सदस्यों उद्योगपतियों के पास 300 अरब डॉलर की संपति जमा हो गई. इस पर विश्व भर में भारतीय उद्योगपतियों के साथ ही भारत की उभरती अर्थव्यवस्था का कौतुक किया गया. आज भी अमेरिका, यूरोपीय देश भविष्य की उभरती आर्थिक शक्ति बताकर भारत व चीन में अपने यहां के उद्योगपतियों को स्थापित करने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं, ताकि विश्वव्यापी मंदी से उबरा जा सके, लेकिन विश्वव्यापी मंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बताने वालों के लिए ख़तरे के संकेत मिले हैं. इसीलिए राज्य व देश के लक्ष्मीपुत्रों के ख़ज़ाने में जो कमी आई है उससे उनकी अमीरी पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा है. हक़ीक़त में मंदी की छाया भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ती नज़र आ रही है, इसलिए देश के अरबपतियों की संपत्ति में 5-10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. 50-55 लोगों की संपत्ति में यदि कमी आती है तो उसका राज्य या देश में व्याप्त ग़रीबी पर क्या असर पड़ता है. ज़्यादा से ज़्यादा यह होगा कि अरबपति क्लब के सदस्यों में कुछ कमी और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इस अरबपति क्लब के सदस्यों में फ़िलहाल कमी आने के कोई आसार दिखाई नहीं देते हैं. दूसरी ओर जिस तरह से देश में मुद्रास्फीति और महंगाई अपना मुंह फैला रही है, उससे देश की आबादी का 40 प्रतिशत ग़रीब भारतवासी कराह रहे हैं. उसका जीना दुश्वार हो रहा है. उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वे अपना बजट किस तरह संतुलित करे. किस तरह परिवार की ज़रूरतों को पूरा करें. अपने बच्चों को पढ़ाए. भरपेट खाना खाये कि अन्य ज़रूरतों को पूरा करें, क्योंकि जिस गति से महंगाई बढ़ रही है, उस गति से आमदनी नहीं बढ़ रही है. इसलिए उसके सामने रोज़ यह सवाल खड़ा हो उठता है कि वह दाल-रोटी खाये या सब्ज़ी-रोटी. आज दाल और सब्ज़ियों के दाम आसमान छू रहे हैं और उसके सामने नमक-रोटी खाने का विकल्प मात्र बचा रह जाता है.

**अगर श्रीमंतों की संपत्ति में गिरावट आने के साथ ही ग़रीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो या उनकी संपत्ति में वृद्धि हो तो माना जा सकता है कि अमीर ग़रीब हो रहे हैं, लेकिन श्रीमंतों की संपत्ति में घट-बढ़ से देश के ग़रीबों की बदहाल अवस्था में कोई सुधार होता दिखाई नहीं देता है.**

महाराष्ट्र में ग़रीबों की दशा और भी अधिक ख़राब हैं. टाटा समाज विज्ञान संस्थान में कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में झोपड़-पट्टियों का फैलाव तेज़ी से हो रहा है. ख़ासकर उन मध्यम व छोटे शहरों में जहां कोई औद्योगिक इकाई चल रही है. वहां लोग मज़दूरी की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से पलायन कर पहुंच रहे हैं. रोज़ी-रोटी के लिए संघर्षरत हैं. दो वक़्त की रोटी के जुगाड़ के दौरान उन्हें कभी काम मिलता है, कभी बेकार बैठे रहते हैं. इन परिस्थितियों में अगर राज्य सरकार द्वारा पिछले साल 2010 के जारी आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर नज़र डालें तो महाराष्ट्र की स्थिति आज उत्तर प्रदेश और बिहार से वह पीछे नज़र आता है. आर्थिक सर्वे में साफ़ कहा गया है कि राज्य के शहरी इलाक़ों में ग़रीबी तेज़ी से बढ़ रही है. औद्योगिक और प्रगतिशील राज्य की छवि वाला महाराष्ट्र अब ग़रीबी के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे पिछड़े माने जाने वाले राज्यों के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है. आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि योजना आयोग द्वारा पेश किए गए ग़रीबों के आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में ग़रीबी का अनुपात 30.7 फ़ीसदी है जो देश के राष्ट्रीय ग़रीबी के 27.5 फ़ीसदी के आंकड़े से 3.2 फ़ीसदी अधिक है. पिछले पांच सालों में राज्य में ग़रीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या में 12.2 लाख की बढ़ोतरी हुई. यह बढ़ोतरी मुख्य तौर पर शहरी इलाक़ों में दर्ज की गई है. उक्त आंकड़े सरकारी दस्तावेज़ों में दर्ज हैं. वास्तविक तस्वीर सामने आने पर इन आंकड़ों में किसी तरह के कमी आने के संकेत नहीं हैं, बल्कि और इज़ाफ़ा हो सकता है.

अब यदि इन आंकड़ों का गंभीरता से विश्लेषण किया जाए तो राज्य की आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा किसी न किसी रूप से ग़रीबी की समस्या से ग्रस्त हैं. ऊपर से महंगाई उनकी कमर तोड़ रही है. इस चालीस प्रतिशत ग़रीबी में संघर्षरत लोगों में मज़दूर, दुकान में काम करने वाले, चाय की टपरियों में काम करने वाले, रिक्शा-हाथ ठेला चलाने वाले लोग, घरों में बर्तन-कपड़े धाने वाले लोग शामिल हैं. ये जीवन भर संघर्ष करने के लिए अभिशापित नज़र आते हैं. इन ग़रीबों के बजट की चिंता न सरकार करती है और न ही कोई अन्य. इनकी ज़िंदगी में आर्थिक मंदी का मतलब सिर्फ़ एक ही होता है- वह है बेकारी. जब काम नहीं मिलता तो घर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता है. इन्हें अपना बजट संतुलित बनाये रखने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें रोज़गार मिलता रहे. उन्हें इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है कि देश का सेंसेक्स किस ओर जा रहा है. अर्थव्यवस्था का क्या मिज़ाज है? रिज़र्व बैंक मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए कैसी रणनीति अपना रहा है? उसे सिर्फ़ यह पता है कि दाल-चावल-गेंहू के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है. रही श्रीमंतों यानी अमीरों की बात तो उनके जीवन में महंगाई का असर कहीं पड़ता दिखाई नहीं देता है. मुकेश अंबानी की पिछले साल कुल चल-अचल संपत्ति 27 अरब डॉलर से कम होकर इस वर्ष 22.6 अरब डॉलर हो गई है. इसका मतलब यह तो नहीं है कि मुकेश अंबानी अपनी संपत्ति में क़रीब 5 अरब डॉलर की कमी आने पर हवाई यात्रा करना छोड़ देंगे या 27 मंज़िला एंटिलिया टॉवर पर रहना छोड़ देंगे. लक्ष्मी मित्तल अपनी संपत्ति कम होने पर लंदन छोड़कर भारत में आकर अपने पैतृक घर में जाकर रहने लगेंगे, लेकिन ग़रीब के लिए उसकी मज़दूरी में दस रुपये की कमी आना भी उसके लिए आघात से कम नहीं होता है. उसके लिए एक-एक पैसा क़ीमती रहता है. इसलिए वह शिद्दत से मेहनत करता है और अपने परिवार के भरण-पोषण की व्यवस्था करता है. इस लिहाज़ से देखा जाए तो श्रीमंतों के ग़रीब होने की बात करना भी ग़रीबों के जख्मों पर नमक छिड़ने के समान ही है. हां, अगर श्रीमंतों की संपत्ति में गिरावट आने के साथ ही ग़रीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो या उनकी संपत्ति में वृद्धि हो तो माना जा सकता है कि अमीर ग़रीब हो रहे हैं, लेकिन श्रीमंतों की संपत्ति में घट-बढ़ से देश के ग़रीबों की बदहाल अवस्था में कोई सुधार होता दिखाई नहीं देता है. इसका मतलब यह है कि राज्य सहित देश में अमीरी-ग़रीबी के बीच बढ़ती खाई में कोई कमी नहीं आई है.


feedback@chauthiduniya.com


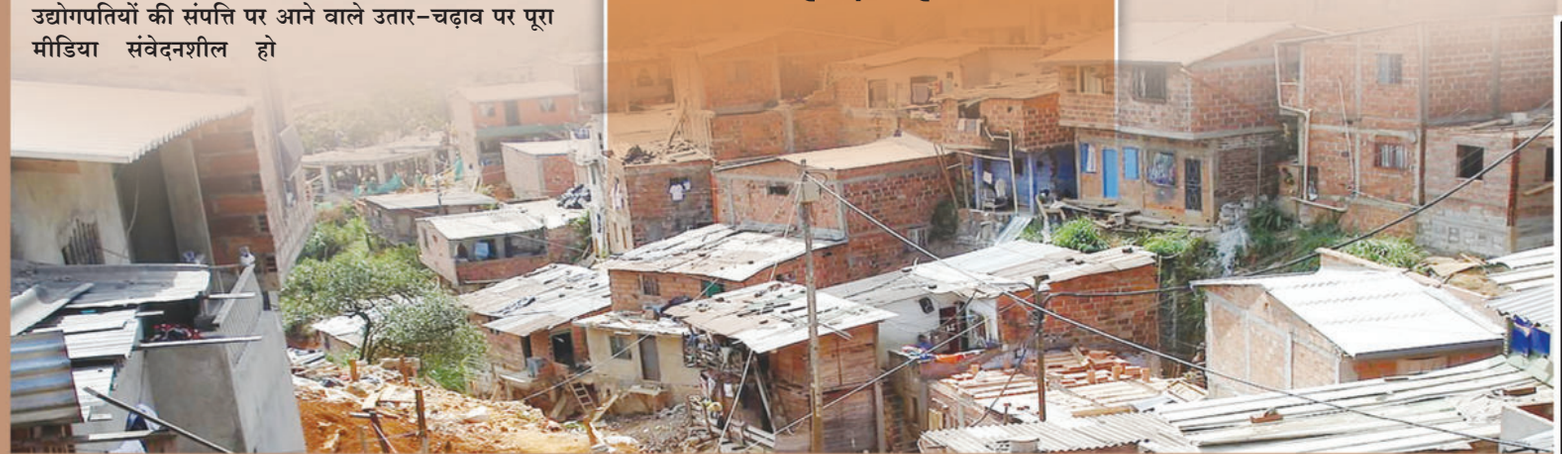


## पाठकों से आवाहन

चौथी दुनिया

विधानमंडल का शीतकालीन सत्र नागपुर में होने जा रहा है. अतः सभी सुधी पाठको से आवाहन है कि वे जनता से जुड़े मुद्दों के विषय में अपने सुझाव व विचार लिख कर अपनी पासपोर्ट फोटो सहित साप्ताहिक चौथी दुनिया के कार्यालय में भेजें. उचित सुझावों को आपकी फोटो के साथ प्रकाशित किया जाएगा.

साप्ताहिक चौथी दुनिया

आशीर्वाद पब्लिकेशन प्रा. लि.

मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाड़ा के सामने, होटल गणराज के बाजू में, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी नागपुर

E-mail : chauthiduniyaa@gmail.com

महाराष्ट्र में संचालित तक़रीबन 12 हज़ार से अधिक आंगनवाड़ियों में हज़ारों बच्चे रोज़ जाते हैं. यहां उन बच्चों को अक्षर ज्ञान से परिचय कराया जाता है.

राज्य में एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होमियोपैथिक सहित विविध चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा प्रदान करने वाले कुल 311 चिकित्सा महाविद्यालय हैं.

## महाराष्ट्र हलचल

















# निजी मेडिकल कॉलेजों की ठगी पर अंकुश लगेगा

अब निजी मेडिकल कॉलेज अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे. उनके द्वारा विद्यार्थियों से फीस के रूप में मोटी रक़म वसूल किए जाने और उन्हें समुचित सुविधाएं न दिए जाने की बढ़ती शिकायतों के मद्देनज़र सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के मार्फ़त सभी मेडिकल कॉलेजों पर नियम-क़ानून सख्ती से लागू करने का फ़ैसला ले लिया है. यह फ़ैसला इसलिए लिया गया है, ताकि योग्य चिकित्सकों को तैयार किया जा सके. इसके लिए ज़रूरी है कि मेडिकल कॉलेजों में व्याप्त अनियमितताओं पर रोक लगाई जाए और विद्यार्थियों के साथ होने वाली धोखाधड़ी पूरी तरह बंद हो. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए मेडिकल कॉलेजों के लिए सेंट्रल कौंसिल द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देशों पर गंभीरता से अमल किया जाएगा. मेडिकल कॉलेजों के जरिये राज्य में योग्य चिकित्सक तैयार करने के लिए स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की विद्या परिषद ने कई महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए हैं. इन फ़ैसलों के तहत आगामी शिक्षा सत्र वर्ष 2012-13 में राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में यह लागू किया जाएगा. इसके अलावा यह भी जांच की जाएगी कि सेंट्रल कौंसिल के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है कि नहीं. इतना ही नहीं विश्वविद्यालय की जांच समिति के अध्यक्ष की रिपोर्ट की कॉपी महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को उपलब्ध कराने का निर्णय विद्या परिषद ने लिया है. उल्लेखनीय है कि राज्य में एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होमियोपैथिक सहित विविध चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा प्रदान करने वाले कुल 311 चिकित्सा महाविद्यालय हैं. इनमें जिन महाविद्यालयों को वर्ष 2012-13 के लिए संलग्नीकरण, नवीनीकरण अथवा विस्तारीकरण कराना है उनको विश्वविद्यालय की जांच समिति की रिपोर्ट में दर्शायी गई कमियों-ख़ामियों को पूरा करके उसकी रिपोर्ट तैयार करना अनिवार्य है. इसके बिना उस महाविद्यालय को स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संलग्न नहीं किया जा सकता है. यदि किसी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय ने विद्या परिषद की जांच समिति द्वारा रेखांकित की गई कमियों को दूर नहीं किया तो उसका पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा और उसके संलग्नीकरण, नवीनीकरण व विस्तारीकरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी. यह निर्णय विद्या परिषद ने लिया है. सबसे अहम बात यह है कि जांच समिति जब महाविद्यालय का निरीक्षण करेगी उस वक़्त वीडियो सूटिंग भी की जाएगी. इस वीडियो सूटिंग का पूरा खर्च संबंधित महाविद्यालय को उठाना होगा और उसकी दो सीडी बनवा कर विश्वविद्यालय के पास जमा करना होगा.

विद्या परिषद ने जांच समिति के निरीक्षण की वीडियो सूटिंग कराने का निर्णय इसलिए लिया है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जांच के दरम्यान निजी चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन झूठे अध्यापक, मरीज़ और अन्य सुविधाओं को पूरा करके दिखाते हैं. विश्वविद्यालय अथवा सेंट्रल कौंसिल की समिति के दौरे के दौरान उनके देखने के लिए दूसरे जगह कार्य करने वाले प्राध्यापकों, दूसरे निजी अस्पतालों से बेड-बिस्तर, मरीज आदि लाकर पूरा दृश्य रंगमंच की तरह बना डालते हैं. यह सब जांच समिति के सदस्यों को धोखा देने के लिए किया जाता है, लेकिन भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रबंधन या संचालकों द्वारा न की जा सके इसके लिए अब संबंधित महाविद्यालय के प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों व अध्यापकों को भी रिपोर्ट की प्रति देने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा अब निजी चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित जांच रिपोर्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी जारी किया जा सकेगा, ताकि किसी को उक्त महाविद्यायल के विषय में जानकारी चाहिए तो वह आसानी से उपलब्ध हो सके. यह सब इसलिए किया जा रहा ताकि मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के साथ निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा किसी तरह की धोखाधड़ी न की जा सके. यह सर्वविदित है कि कई बार अच्छी पढ़ाई करने के उद्देश्य से निजी मेडिकल कॉलेजों में छात्र मोटी रकम भर कर प्रवेश लेते हैं पर वहां न पढ़ाने के लिए अध्यापक होते हैं और न अन्य सुविधाएं. वे खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं. यहां तक देखा गया है कि निजी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन आपत्ति दर्ज़ कराने और कॉलेज छोड़कर जाने वाले छात्रों को फीस तक लौटाने से साफ इनकार कर देते हैं. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संलग्न प्रत्येक मेडिकल कॉलेजों को सेंट्रल कौंसिल द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार विद्यार्थियों को सभी विषयों के अध्यापक नियुक्त करना आवश्यक है. इसके लिए वर्ष 2012-13 के शैक्षणिक सत्र में हर फैक्लटी को मिला कर चिकित्सा महाविद्यालयों में कम से कम 75 प्रतिशत अध्यापकों को नियुक्त करना जरूरी है. यह नियम विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनिवार्य किया गया है. इसके पहले जांच समिति के जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में काफी समय लगता था, जिससे कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया देर से शुरू होती थी और छात्रों की पढ़ाई का नुकसान होता था. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने दिसंबर-जनवरी माह के आख़िर में मेडिकल कॉलेजों के लिए जांच समिति गठित कर भेजने का फ़ैसला लिया है. उक्त समितियों द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट अब मार्च-अप्रैल माह के अंत तक विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य किया गया है. नतीजतन सभी पद्धति के चिकित्सा महाविद्यालय में एक साथ अगस्त माह में शैक्षणिक सत्र शुरू हो सकेगा. यह विश्वास व्यक्त किया जा रहा है. इसके साथ ही छात्रों की पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा. सूत्रों का कहना है कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति चिकित्सा शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए सतत प्रयासरत हैं. साथ ही छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न किया जा सके, इसके लिए ठोस कदम उठा रहे हैं. इससे राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी पर रोक लग सकेगी. ऐसी आशा व्यक्त की जा रही है.

**चौथी दुनिया ब्यूरो**
feedback@chauthiduniya.com

ये क्या हो रहा है...

## मतभेद दूर करने की क़वायद

राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के बीच हो रहे गुटीय वार से मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण बेहद चिंतित नज़र आ रहे हैं. उनकी परेशानी की मुख्य वजह है आगामी स्थानीय निकाय चुनाव. इसके अलावा कई ज़िलों में भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आपसी गुटबाज़ी शुरू कर दी है. इससे स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी की नैया भंवर में फंस सकती है. ऐसे में बाबा का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी अगुआई वाली सरकार में पहली बार कोई चुनाव हो रहा है. इसी के मद्देनज़र खुसफुसिया मुहिम रूठों को मनाने के लिए छेड़ रखी है. क्यों बाबा जी यह क्या हो रहा है? आपने पार्टी में गुपचुप मुहिम चलाकर लोगों के कान खड़े कर दिए हैं. आपकी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं के बीच के मतभेद व भेद मिटाने का अभियान गुप-चुप तरीके से चला रखा है. हर ज़िले का दौरा करके वहां के नेताओं के मनभेद का जायजा लेते हैं. पहले गुटीय लीडरों की बात पूरी शांति से सुनते हैं और फिर गुटों के बड़े लीडरों की मीटिंग फिक्स करते हैं. किसी के घर, पार्टी, कार्यालय या किसी कार्यक्रम के दरम्यान गुट लीडरों को लेकर आमने-सामने लाकर बैठते हैं. उसके बाद बाबा का प्रवचन शुरू होता है. दोनों को समझाया जाता है कि भाई, तुम लोगों के गुटों में बंटे होने से पार्टी का नुकसान हो रहा है. भला ऐसी गुटबाज़ी का क्या मतलब जिससे न पार्टी का भला हो और न आपका. इसलिए यह गुटबाज़ी छोड़ो और पार्टी व अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए गले मिल लो. भाई राजनीति में मन मिले या न मिले, पर गले ज़रूर मिलते रहना चाहिए ताकि दूरियों में भी नज़दीकियां बनी रहें. कहा जा रहा है कि बाबा के इस गुप-चुप अभियान के नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं. कई ज़िलों में उनको अपने मिशन में कामयाबी भी मिली है. एक-दूसरे के ख़िलाफ़ तलवार भांज रहे कई नेताओं को गले मिलवाने में वे कामयाब हुए हैं. इससे पार्टी में उनके प्रति सकारात्मक संकेत भी जा रहे हैं. उदाहरण के तौर पर बाबा ने चंद्रपुर ज़िले में विजय वडेट्टीवार और नरेश पुगलिया को गले मिलाने में कामयाब रहे हैं. गढ़चिरोली जिले में सांसद नामदेव कवासे और वडेट्टीवार का भी मेल मिलाप करा दिया है. इसी तरह नागपुर ज़िले में पिछले दिनों आयोजित एक कार्यक्रम के दरम्यान पार्टी महासचिव व सांसद विलास मुत्तेमवार और सतीश चतुर्वेदी के बीच व्याप्त मतभेद से भेद को निकाल बाहर किया. दोनों ने भविष्य में मिलजुल कर पार्टी हित में कार्य करने का वादा किया. उसके बाद आया वर्धा का मामला जहां सांसद दत्ता मेघे और राज्य के मंत्री रणजीत कांबले गुट आपस में टकरा रहे थे. एक-दूसरे की टांग खींचने का कोई अवसर नहीं गवां रहे थे. यह बात बाबा के ध्यान में लायी गई. फिर क्या बाबा ने दोनों गुटों के नेताओं से बातचीत की. नागपुर आए गोंड राजा बख्तबुलंद शाह की प्रतिमा का अनावरण करने. अनावरण समारोह के पश्चात सांसद दत्ता मेघे और मंत्री रणजीत कांबले को लेकर रामगिरी पहुंच गए. दोनों को पता नहीं बाबा ने क्या प्रवचन दिया कि वहां से निकलने के बाद सांसद दत्ता मेघे का बयान आया कि अब वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि पुत्र सागर मेघ को मैदान में उतारेंगे, लेकिन मंत्री कांबले ने बाहर आने के बाद कुछ नहीं कहा. पार्टी कनफुसियों की बात मानी जाए तो बाबा ने दोनों के बीच सुलह करा दी है. दोनों पार्टी हित में मतभेद भुलाकर स्थानीय निकाय चुनाव में कार्य करने को राजी हो गए हैं. यानी बाबा का गुटीय बीमारी का उपचार अभियान सफलता पूर्वक जारी है. अब बाबा को जरूरत है यवतमाल में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे और पूर्व सांसद उत्तम राव पाटिल, अमरावती में देश के महामहिम के पुत्र राजेंद्र शेखावत और पूर्व मंत्री डॉ. सुनील देशमुख, नागपुर ग्रामीण में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध मोहिते व चन्द्रपाल चौकसे, नागपुर शहर में पूर्व महापौर विकास ठाकरे व प्रफुल्ल गुडधे पाटिल में सुलह कराने की सख़्त ज़रूरत है.







**चौथी दुनिया ब्यूरो**
feedback@chauthiduniya.com

## आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ाई नहीं होती



निशा वर्मा

छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने और उनके अंदर प्रारंभिक शिक्षा के प्रति बोध जगाने, उनमें स्कूल जाने के प्रति लगन पैदा करने के मक़सद से देश भर में आंगनवाड़ियों की शुरुआत की गई थी, लेकिन ये आंगनवाड़ियां मौजूदा समय में शिक्षा के लिए कम और खाऊ के लिए अधिक जानी-पहचानी जाती हैं. यहां पर बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से रू-ब-रू कराने का कार्य ठप्प पड़ गया है. यानी आंगनवाड़ी से अक्षर ज्ञान कराने वाली शिक्षा पद्धति पूरी तरह ग़ायब नज़र आ रही है. आंगनवाड़ी में जो बच्चे पहुंच रहे हैं वे वहां मिलने वाले खाद्य पदार्थ की वजह से ही आते हैं.

ग़ौरतलब है कि महाराष्ट्र में संचालित तक़रीबन 12 हज़ार से अधिक आंगनवाड़ियों में हज़ारों बच्चे रोज़ जाते हैं. यहां उन बच्चों को अक्षर ज्ञान से परिचय कराया जाता है. इसके बावजूद यहां कार्यरत शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने अब तक कोई योग्य कार्यप्रणाली नहीं बना पाई है. सरकार के पास इतना वक़्त नहीं है कि वह ध्यान दे कि राज्य के आंगनवाड़ियों में बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है.लापरवाही का आलम यह है कि इन आंगनवाड़ियों के लिए अभी तक कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं बनाया जा सका है.

इस संबंध में मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता सीमांतिनी धुरू ने बताया कि न्यायमूर्ति मोहित शहा व न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़ की खंडपीठ के समक्ष हमने आंखों देखा हाल पेश की थी. रिपोर्ट में एकात्मिक बाल विकास योजना के अंतर्गत ठाणे ज़िले में संचालित पालना घर, विक्रमगढ़, जव्हार व राज्य के अन्य आदिवासी भागों में संचालित अधिकांश आंगनवाड़ियों में मात्र खाऊ (खाने की चीजों) पाने के लिए बच्चे आते हैं. यहां आने वाले बच्चों का सरोकार मात्र खाने से रह गया है. याचिकाकर्ता ने कई आंगनवाड़ियों में जाकर स्थिति का जायजा लिया. जिनमें से अधिकतर आंगनवाड़ियों में कार्यरत शिक्षिकाएं नदारद पाई गईं. मात्र एक आंगनवाड़ी में शिक्षिका उपस्थित थी, पर वहां भी बच्चों की हाज़िरी नहीं हुई थी. इसका मतलब साफ है कि आज आंगनवाड़ी महज़ बच्चों को खाना मिलने का केंद्र बनकर रह गए हैं, लेकिन हाज़िरी रजिस्टर बराबर भरा जाता है चाहे बच्चें आएं या न आएं.



दरअसल, आंगनवाड़ियों को स्थापित करने का जो उद्देश्य था वह अब पूरी तरह विफल होता दिखाई दे रहा है. आंगनवाड़ियों का हाल यह है कि वहां जो सामान बच्चों के खेलने या बच्चों के उपयोग के लिए आता है वह शिक्षिका और संचालिका के घर पहुंच जाता है. कई आंगनवाड़ियों से ब्लैकबोर्ड तक ग़ायब पाए गए हैं. कुछ जगह तो मात्र आंगनवाड़ी का बोर्ड टंगा दिखाई देता है, पर शिक्षिका व बच्चे महीनों ग़ायब रहते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि आंगनवाड़ियों का समय होता है सुबह 9 बजे से दोपहर साढ़े बारह बजे तक, लेकिन अधिकांश आंगनवाड़ी केंद्रों का आलम यह रहता है कि बच्चे आते है तो अक्सर शिक्षिका की सहायता के लिए नियुक्त बाई बच्चों की हाज़िरी भरती हैं और खाना बांटती दिखाई देती है. शिक्षिका के आने-जाने का समय उनकी मर्ज़ी पर निर्भर रहता है. हाज़िरी का काम कभी भी पूरा कर लिया जाता है. इस परिदृश्य को देखने के बाद तो यही लगता है कि राज्य की आंगनवाड़ियां अब मात्र बच्चों को खाना बांटने का ठिकाना बन गईं हैं. अक्षर ज्ञान या प्राथमिक शिक्षा से उनका कोई सरोकार नहीं रह गया है.

कुछ स्थानों में एक ही जगह पर तीन-चार आंगनवाड़ियां मौजूद हैं. वहां आने वाले बच्चे किस आंगनवाड़ी में आते हैं, वहां के दृश्य को देखकर बता पाना मश्किल होता है. नागपुर ज़िले की रामटेक तहसील की मनसर ग्राम पंचायत के नज़दीक एक ही जगह तीन-चार आंगनवाड़ियां है. सूत्रों का कहना है कि यहां आने वाले बच्चों का नाम एक साथ कई आंगनवाड़ियों में दर्ज़ हैं. इन आंगनवाड़ियों में कार्यरत शिक्षिकाओं को कभी भी बच्चों को पढ़ाते नहीं देखा गया. हां, जब किसी अधिकारी के आने की ख़बर आती है तो बच्चों को घरों से बुलाकर क्लास लगा ली जाती है. बाकी समय यहां की सभी आंगनवाड़ी शिक्षिकाओं को बैठकर आपस में गप्प-शप्प मारते देखा जा सकता है. यहां बच्चों को लोग यह सोचकर भेजते हैं कि आंगनवाड़ी में जाने पर बच्चों को समय पर खाना मिल जाता है. फिर चाहे शिक्षिका आंगनवाड़ी में उपस्थित रहे या न रहे. वहां के कर्मचारी अपना कार्य पूरा करके बच्चों को घर भेज देते हैं. कोर्ट में पेश रिपोर्ट में बताया गया है कि एक गांव की आंगनवाड़ी ऐसी भी है जहां छप्पर नहीं है, हालांकि उसके मरम्मती का कार्य पिछले दो वर्ष से शुरू है.

इस संबंध में नागपुर ज़िला परिषद की महिला-बाल कल्याण अधिकारी सौ. दया राऊत का कहना है कि आंगनवाड़ियों में 2 से 3 साल के बच्चों को आंगनवाड़ियों में पौष्टिक आहार देने के साथ ही प्रारंभिक शिक्षा भी प्रदान करने का काम सुचारू रूप से किया जा रहा है. हो सकता है कि कुछ आंगनवाड़ियों से लोगों को शिकायत हो. इससे संबंधित शिकायत मिलने पर लापरवाही बरतने वाली शिक्षिका के खिलाफ यथोचित कार्रवाई की जाएगी. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आंगनवाड़ियों की जांच भी उसी तर्ज़ पर की जानी चाहिए जैसे की राज्य के स्कूलों में छात्रों की गई. यदि इस तरह की जांच होती है तो भारी मात्रा में यहां भी बच्चों की अधिक संख्या दर्शा कर पौष्टिक खाद्य पदार्थों में घोटाला उजागर हो सकता है. इसकी वजह यह है कि एक ही बच्चे का नाम गांव की एक ही जगह स्थित आंगनवाड़ियों में दर्ज़ होने की बात कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन इस ओर किसी अधिकारी ने ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा है.

feedback@chauthiduniya.com

## आदिवासी विकास मंत्रालय कठघरे में

राज्य में आदिवासी समाज के लोगों के उद्धार के लिए राज्य व केंद्र सरकार लाखों-करोड़ों का बजट बना कर दर्जन भर से अधिक योजनाएं संचालित करती है, लेकिन योजनाओं का लाभ आदिवासियों तक नहीं पहुंच पाता है. मामला चाहे कुपोषण का हो या उनको आर्थिक संबल प्रदान करने का. इन सबमें उनसे जुड़ी योजनाओं का बंटाधार करने में शासन-प्रशासन कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं. इससे आदिवासियों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया जाता है. एक बार फिर बोगस आश्रम शालाओं को लेकर राज्य का आदिवासी विकास मंत्रालय से लेकर पूरा आदिवासी विभाग ही कठघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है. वैसे तो आश्रम शालाओं में अनियमितताओं की शिकायतें आना कोई नई ख़बर नहीं है, लेकिन इस बार मामला 61 आश्रम शालाओं की मान्यता रद्द करने की सिफारिश और पुनः उन्हें मनमाने तरीके से मंज़ूरी दिए जाने का है. इस पर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने आदिवासी विकास मंत्री सहित दर्जन भर से अधिक आदिवासी विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया.

राज्य की आवासीय आश्रम शालाओं में आर्थिक अनियमितता व अन्य गड़बड़ियों की ओर ध्यान दिलाने के लिए करीब एक साल पहले मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. सुनवाई के पश्चात राज्य की निजी अनुदानित आश्रम शालाओं को अपने अधीन लेने का आदेश सरकार को कोर्ट ने दिया था. साथ ही राज्य सरकार के आदिवासी विभाग से जबाव-तलब किया था. तब आदिवासी विकास मंत्रालय के तत्कालीन प्रधान सचिव उत्तम खोब्रागड़े ने न्यायालय के समक्ष पेश शपथपत्र में दावा किया था कि राज्य में संचालित कुल आश्रम शालाओं में से 95 प्रतिशत बोगस हैं. राज्य में आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से 556 अनुदानित आदिवासी आश्रम शालाओं को संचालित किया जाता है. इनमें से नागपुर विभाग में 152 और अमरावती विभाग में 125 आश्रमशालाएं हैं. बीच में 279 आश्रम शालाओं के बोगस होने की चर्चा थी. उसके बाद राज्य भर में आदिवासी आश्रम शालाओं में व्याप्त अनियमितता के ख़िलाफ़ जांच अभियान शुरू किया गया था. जांच अभियान में अनियमित पाई गई विदर्भ की 29 सहित पूरे राज्य की 61 आश्रम शालाओं को आदिवासी विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजा था और उनकी मान्यता को निलंबित कर दिया था. इन आश्रम शालाओं के संचालकों के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के निर्देश भी उपसचिव ने संबंधित अतिरिक्त आयुक्तों को दिया था, लेकिन कुछ ही समय में सब कुछ बदल गया. उत्तम खोब्रागड़े का आदिवासी विकास मंत्रालय के प्रधान सचिव के पद से बदली हो गई. मंत्री भी बदल गए. इस परिवर्तन के साथ ही उक्त स्कूलों के प्रति आदिवासी विकास मंत्रालय का दृष्टिकोण भी बदल गया और जिन 61 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, उनसे उनकी उद्देश्य पूर्ति के लिए अपील मंगा ली. आदिवासी





विकास मंत्री ने अपील की सुनवाई भी यथाशीघ्र कर पुनः उक्त स्कूलों में व्याप्त अनियमितता की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश अतिरिक्त आयुक्त को दिया. सूत्रों का कहना है कि मंत्री के निर्देश पर अमल करते हुए अतिरिक्त आयुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय के सुपुर्द कर दी. अतिरिक्त आयवुत की रिपोर्ट के आधार पर इस साल के जुलाई-अगस्त माह में उक्त 61 आश्रम शालाओं को सैद्धांतिक तौर पर शुरू रखने की अनुमति आदिवासी विकास मंत्री ने प्रदान कर दी. बताया जाता है कि उक्त आश्रम शालाओं से संबंधित अनेक शिक्षण संस्थाओं से राज्य के कई पूर्व मंत्रियों, पूर्व शिक्षा मंत्रियों का संबंध है. आश्रम शालाओं में व्याप्त अनियमितता व उससे जुड़ी समस्या मुख्यमंत्री के ध्यान में लाने के लिए महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद आश्रम शाला विभाग नागपुर व अनुदानित आदिवासी आश्रम शाला अन्यायग्रस्त कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कई बार उनका कहना है कि इसके लिए आंदोलन कर उन्हें कई बार आवेदन-निवेदन भी दिए हैं. इसके बाद भी दोषियों के ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. अंततः उक्त संगठनों के पदाधिकारियों ने इस मुद्दे पर समाजसेवी उमेश चौबे से विचार-विमर्श किया. उसके बाद उन्होंने 21 अक्टूबर को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में न्यायमूर्ति शरद बोबड़े और न्यायमूर्ति एम.एन. गिलानी की अदालत में पीआईएल 66-2011 क्रमांक की जनहित याचिका पेश की. याचिका में आदिवासी विकास मंत्री द्वारा की गई उक्त कार्रवाई को एक तरह से न्यायालय के आदेश की अवमानना माना बताया जा रहा है और इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने की आशंका जताई जा गई है. न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए. उक्त सभी स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए. इसके लिए जिम्मेदार आदिवासी विकास मंत्री व मंत्रालयीन उपसचिव के विरूद्ध कार्रवाई की जाए. उक्त जनहित याचिका को सुनवाई के लिए मंज़ूर करते हुए न्यायमूर्ति शरद बोबड़े व न्यायामूर्ति एम.एन. गिलानी ने आदिवासी विकास मंत्री, आदिवासी विकास मंत्रालय के प्रधान सचिव, उपसचिव, नासिक के आदिवासी विकास आयुक्त, अमरावती के अतिरिक्त आयुक्त, नागपुर के सहायक आयुक्त और संबंधित शिक्षण संस्थाओं को नोटिस जारी कर उनसे जबाव मांगा है. इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, आश्रमशाला विभाग नागपुर के सचिव संजय वामनराव बडवाईक का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में आदिवासी विकास मंत्री पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. उनकी अनुमति के बिना किसी अधिकारी में हिम्मत नहीं है कि जिन आश्रमशालाओं की मान्यता रद्द हो और जिनको अनियमितताओं के लिए दोषी पाया गया हो, उन्हें पुनः शुरू करने की अनुमति प्रदान करे. संभवतः इसीलिए मुख्यमंत्री भी इस मामले में पूरी तरह चुप्पी साधे रहे हैं. बहरहाल मामले की हक़ीक़त न्यायालीन कार्रवाई में सामने आ ही जाएगी, लेकिन आज राज्य का आदिवासी विकास मंत्रालय अदालत और जनअदालत दोनों के बीच कठघरे में खड़ा नज़र आ रहा है.

**चौथी दुनिया ब्यूरो**
feedback@chauthiduniya.com

## महाराष्ट्र हलचल

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 14 नवंबर–20 नवंबर 2011

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने हाल ही में राज्य के शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर खूब टीका-टिप्पणी की थी.



## शिक्षा माफ़ियाओं पर नकेल

# स्कूलों में बायोमेट्रिक हाज़िरी होगी

बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का स्वाभाविक अधिकार है. ऐसा शिक्षा अधिकार अधिनियम का निहितार्थ है. इस क़ानून को देश में लागू हुए डेढ़ साल से अधिक वक़्त हो गया है पर राज्य का शिक्षा मंत्रालय उसे लागू करने को अब तक तैयार दिखाई नहीं देता है. इस अधिनियम के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षण के लिए स्कूल में लाना, शिक्षा देना सरकार के लिए बंधन कारक है. लड़के-लड़कियां कम से कम प्राथमिक शिक्षा अवश्य प्राप्त करें, ड्राप आउट ( बीच में ही स्कूल छोड़कर जाना) का प्रमाण कम हो, बीच में ही पढ़ाई छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या पर रोक लगे यही सर्व शिक्षा अभियान शुरू करने का उद्देश्य है. केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार क़ानून डेढ़ साल पहले लागू कर दिया है, लेकिन उसका क्रियान्वयन करना राज्य सरकार की जबावदारी है. महाराष्ट्र सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने में बरती जा रही उदासीनता के प्रति केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने अफ़सोस ज़ाहिर किया है. अपने राज्य में स्कूल न जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक से डेढ़ प्रतिशत ही है. यह ढिंढोरा पीटने का कार्य राज्य का शिक्षा मंत्रालय कर रहा है, लेकिन उनका यह दावा पिछले माह ही छात्र गणना के बाद झूठा साबित हो गया है.

राज्य भर में सरकार ने स्कूलों में छात्रों की जांच मुहिम चलायी. शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा के अभी तक के काल में उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण कार्य यह जांच मुहिम ही है. इसी वजह से शिक्षा मंत्री का अभिनंदन है, लेकिन इसके साथ ही आघाड़ी सरकार के घटक कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक, छोटे-बड़े नेता, कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री की इस जांच मुहिम से परेशान हो गए होंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों की सबसे अधिक स्कूल राज्य भर में हैं. वंश परंपरा में मिली स्कूल, वंशानुक्रमानुसार ही अन्य स्कूलों की मान्यता प्राप्त कर लिया है. यह सब स्कूल नहीं है, बल्कि इन्हें दुकान कहना ही उचित रहेगा. बोगस विद्यार्थियों को दिखाकर पिछले कई सालों से स्कूल संचालक सरकारी खजाने को लूट रहे हैं. स्कूल में जांच अभियान चलाये जाने से बोगस विद्यार्थियों की भारी संख्या उजागर होने पर लुटेरे स्कूल संचालकों ने शिक्षा मंत्री को इसके लिए दोषी ठहराना शुरू कर दिया है.जांच अभियान में स्कूलों के बोगस कारोबार का खुलासा होने पर स्कूल न जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या डेढ़ प्रतिशत से कई गुना ज्यादा होने की आशंका वयक्त की जा रही है. ऐसी जालसाजी, सरकारी खजाने को लूटने और जनता से बेईमानी करने का कार्य यदि पूरे राज्य में शिक्षा विभाग की शह पर चल रहा है तो यह सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है क्या? शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा को सबसे पहले महत्वपूर्ण काम जो करने की गरज है वह शिक्षा विभाग का शुद्धिकरण करना है, जिसकी अत्यंत आवश्यकता है.

मंत्रालय का ही एक स्वीय सहायक को कुछ हज़ार रुपये की रिश्वत लेते भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस ने रंगेहाथ पकड़ा है. वह अकेला नहीं है. पिछले पांच सालों में शिक्षा विभाग के 16 अधिकारियों को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने पकडे. हैं. उक्त सभी 16 अधिकारी निलंबित हैं और उनके ख़िलाफ़ जांच चल रही है. हालांकि, शिक्षा विभाग में हर जगह पर भ्रष्टाचार व्याप्त होने की बात कही जाती है, लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से तेरी भी चुप, मेरी भी चुप की स्वार्थपूर्ण नीति की वजह से सैकड़ों भ्रष्टाचारी सामने नहीं आ पाते हैं. एक दाने की वजह से भात नहीं पका, अगर इसका परीक्षण करना पड़ा तो संपूर्ण शिक्षा विभाग, शिक्षा संस्थानों की तत्काल शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है. भ्रष्ट व कामचोर अधिकारी और कर्मचारियों को दंड मिलना चाहिए, निलंबित अधिकारियों की विभागीय जांच तत्परता से पूरी करनी चाहिए. सभी भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों को न्यायालय के सामने खड़ा करने की, शिक्षा विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने, राजनीति हस्तक्षेप पर पाबंदी लगाने आदि ऐसी बहुत सी चुनौतियां शिक्षा मंत्री के समक्ष हैं. बहुत से कार्य की सूची शिक्षा मंत्री के सामने है.

शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा को घोषणाबाजी करने की आदत पिछले कई महीनों से नज़र आ रही है, लेकिन घोषणा करने की आदत सिर्फ दर्डा को नहीं है, बल्कि सभी मंत्रियों को होती है. बोगस विद्यार्थी व बोगस स्कूल मिलने की जानकारी सरकार को पांच साल पहले ही मिल गई थी, लेकिन सरकार काफी देर बाद हरकत में आई. इस जांच अभियान को शुरू करने में पांच साल लगे और उस पर कार्रवाई सरकार कब करेगी? लुटेरों को सज़ा कब मिलेगी? यह सभी प्रश्न अंधकार में हैं. कोई जबाव देने को तैयार नहीं है. हालांकि, ग्राम विकास मंत्री जयंत पाटिल ने राज्य भर के एक हज़ार स्कूलों में बायोमेट्रिक पद्धति पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है. प्रत्येक महसूल विभाग में एक और इसी तरह छह तहसीलों के स्कूलों के विद्यार्थी और शिक्षकों की हाज़िरी के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था की जाएगी. इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रारंभ में एक हज़ार स्कूलों में यह व्यवस्था की जाएगी. उसके बाद चरणबद्ध तरीके से राज्य भर के स्कूलों में बायोमेट्रिक हाज़िरी सिस्टम लागू किया जाएगा. जांच अभियान चलाने के लिए पांच साल का समय लगा. तभी लाखों बोगस विद्यार्थियों के होने का खुलासा हुआ. मुंबई जैसे शहर में जगह-जगह पर सीसी टीवी कैमरे लगाने की घोषणा पिछले चार वर्षों में कई बार की गई, लेकिन इसे पूरी तरह अमल में नहीं लाया जा सका है. आतंकवादी मुंबई में बम धमाके करते रहे, जिससे आम इंसानों को जान गंवानी पड़ी. बावजूद इसके सीसीटीवी कैमरे लगाने में कोताही बरती जा रही है. अब सरकार गांवों में स्थित स्कूलों में बायोमेट्रिक्स पद्धति से विद्यार्थियों और शिक्षकों की हाज़िरी लेने वाली है. मंत्री जयंत पाटिल को शायद ध्यान नहीं है इसलिए मुंबई को छोड़कर अन्य जगह पर 6 से 12 घंटे बिजली ग़ायब रहती है. बिजली ही नहीं होगी तो बायोमेट्रिक तकनीक कैसे काम करेगी?

feedback@chauthiduniya.com

युधिष्ठिर जोशी

शिक्षामंत्री राजेंद्र दर्डा यानी उत्साह की मूर्ति. वे स्वतः हंसते-मुस्कराते काम करते हैं और आपने मातहत अधिकारी व कर्मचारियों से काम जल्दी करवाने की कला में सिद्ध हस्त हैं. दर्डा बंधु आज की तारीख़ में महाराष्ट्र के मीडिया सम्राट हैं. राज्य के गांव-गांव में लोकमत जैसा अख़बार पहुंचाने का स्मरणीय योगदान दर्डा बंधु का है, लेकिन राज्य मंत्रिमंडल में कैबिनेट शिक्षा मंत्री बनने के पश्चात राजेंद्र दर्डा का उत्साह, काम कराने की दक्षता और अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कार्य कराने की क्षमता क्यों कम हो गई? इस विषय पर उन्हें आत्म परीक्षण करने की ज़रूरत है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने हाल ही में राज्य के शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर खूब टीका-टिप्पणी की थी. पिछले कुछ माह से शिक्षा विभाग अनियमितता व घपलों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है. उसमें व्याप्त गड़बड़झाले को लेकर अख़बारों में बहुत कुछ छप चुका है. स्वयं शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा के मंत्रालयीन दरबार के एक निजी सहायक को कुछ माह पहले रिश्वत लेते मंत्रालय में ही रंगेहाथ पकड़ा गया, लेकिन उससे शिक्षा मंत्री का कोई संबंध है, ऐसा निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है. वैसे शराब की दुकान में कोई आदमी दूध पी रहा है, तो वह दूध होते हुए भी दूध नहीं दारू है. सामान्यतः शराब की दुकान पर वह शराब ही पी रहा था, ऐसा किसी ने समझा तो यह उसकी ग़लती नहीं मानी जाएगी. तर्क-वितर्क करना, मनुष्य का स्वभाव ही है. मंत्रालय में हज़ारों कर्मचारी हैं. उसमें कुछ कर्मचारी व्यवहारिक तौर पर व्यभिचार, अनाचार में लिप्त होंगे, लेकिन ऐसे एक या कुछ लोगों की ग़लती से शिक्षा मंत्रालय बदनाम हो रहा है.

शिक्षा का अधिकार क़ानून महाराष्ट्र में लागू ही नहीं किया गया है. इस बात को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार के कान मरोड़े हैं, जिससे उसकी बोतली बंद हो गई है. प्रत्येक

चौथी दुनिया
हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार
महाराष्ट्र

सदस्यता फार्म (वार्षिक)

सदस्यता शुल्क- २५० /- रुपये

मैं "चौथी दुनिया" साप्ताहिक समाचार पत्र का सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ।

मेरा नाम श्री./ श्रीमती .....

मेरा पता .....

जिला.....राज्य .....पिन कोड.....

फोन (आ).....(का).....मोबाईल.....

ई -मेल.....

मैं रु. वार्षिक सदस्यता के लिए चेक क्रमांक.....

दिनांक .....बैंक.....शाखा..... द्वारा भेज रहा/ रही हूँ

नोट- यह सदस्यता शुल्क भारत में ही मान्य है तथा यह योजना सीमित अवधि के लिए है। समाचार पत्र केवल साधारण डाक द्वारा भेजा जाएगा।

सदस्यता शुल्क केवल चेक द्वारा आशीर्वाद पब्लिकेशन प्रा. लि. नागपुर के पक्ष में सदस्यता फार्म के साथ निम्नलिखित पते पर प्रषित करे या फिर हमारे प्रतिनिधी को फार्म कलेक्ट करने के लिए फोन पर सूचित करे.

कार्यालय

"चौथी दुनिया"- महाराष्ट्र,
आशीर्वाद पब्लिकेशन प्रा.लि.,
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने,होटल गणराज के बाजू में, टेम्पल बाजार रोड,सीताबर्डी, नागपुर.
फोन नं.- 0712-2544988, 2549846
Email: chauthiduniyaa@gmail.com

पाठक ध्यान दें

जिन पाठको कों चौथी दुनिया की वार्षिक सदस्यता चाहिए वे फार्म भरकर भेजें या कार्यालय में संपर्क करें.

Postal Regn. No.RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 14 नवंबर–20 नवंबर 2011

गागा जब इंडिया आईं तो इस बार उनके कपड़ों एवं माइक ने उन्हें विवादों में डाल दिया. लेडी गागा ने दिल्ली में अपने प्रशंसकों का अभिवादन नमस्ते कहकर किया.



# अभिनय मेरा शौक़ है, राजनीति मेरा पेशा

*सियासत को हमेशा अभिनय से जोड़ा जाता है और अभिनय में कई दफा सियासत करनी पड़ती है. बिहार के दिग्गज राजनीतिज्ञ, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सदस्य रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान फिल्म मिले ना मिले हम के ज़रिए बॉलीवुड में अपनी पारी शुरू की है. एक कहावत है, दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए, लेकिन रामविलास पासवान कहते हैं कि जब तक दिल न मिले, हाथ न मिलाइए. पिता की इसी बात से जोड़ते हुए बेटे चिराग पासवान ने अपनी पहली फिल्म का नाम रख दिया, मिले ना मिले हम. हालांकि इसका नाम पहले मी एंड ओनली रखा गया था. पिछले दिनों चौथी दुनिया की एडिटर (इंवेस्टिगेशन) रूबी अरुण ने उनसे एक लंबी बातचीत की. पेश हैं मुख्य अंश:*

***चिराग, यह शुरुआत अभिनय से सियासत की ओर है या सियासत से अभिनय की ओर?***

मैं किसी को भी माध्यम नहीं बना रहा हूं, न सियासत और न अभिनय को. सियासत तो मेरी रगों में है. मैं राजनीति से दूर नहीं था और मुझे ख़ुद लोगों से मिलने का शौक रहा है. मैं ख़ुशनसीब हूं कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, जहां मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूं. पापा के साथ चुनावी दौरे पर जाने या रैलियों में जाकर लोगों से सीधे मिलने का मौक़ा मिलता है, लेकिन अभिनय का शौक बचपन से रहा और इसी शौक को पूरा करने के लिए मैं यहां हूं.

***जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं, तब तमाम लोगों से रूबरू होते हैं. जब फिल्मों में हीरो का किरदार निभाते हैं तो ग्लैमर का टैग लग जाता है. आप उसमें भी लोगों से मिलते हैं, लेकिन उसमें एक दूरी आ जाती है. इस दूरी को आप कैसे पाटेंगे?***

मुझे ऐसा नहीं लगता कि ग्लैमर का टैग मुझ पर लगेगा, इसकी वजह से मुझे लोगों से दूर होना पड़ेगा या होने की कोशिश करनी पड़ेगी. आज भी मैं उतना ही साधारण हूं और आने वाले पांच वर्षों तक ऐसा ही रहूंगा. मैंने आपको बताया भी कि लोगों से मिलना मेरा शौक है, अगर अपने आसपास भीड़ नहीं दिखती या लोग नहीं दिखते तो मुझे घबराहट होती है, क्योंकि मैं ऐसे घर में पला-बढ़ा हूं, जहां आदत सी हो गई है लोगों के बीच रहने की. उनसे दूर रहना या उन्हें अवाइड करने की बात मैं सोच भी नहीं सकता.

***आप बिहार चुनाव में गए, पापा की पार्टी के लिए आपने प्रचार भी किया. उस वक़्त कहा जा रहा था कि आप और तेजस्वी मिलकर राहुल के ख़िलाफ़ लामबंदी करेंगे, इसमें आप लोग थोड़े सफल भी हुए, लेकिन अभिनय के क्षेत्र में आना उस चीज के लिए बंदिशें तो नहीं पैदा करेगा?***

नहीं, बिल्कुल नहीं. उस वक़्त भी हम राहुल के ख़िलाफ़ नहीं थे. मैं पार्टी लाइन से हटकर कहूंगा कि मैं राहुल जी का बहुत आदर करता हूं. उन्होंने युवाओं को राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया, यह बहुत अच्छा काम है. कहीं न कहीं युवाओं का राजनीति से विश्वास उठता जा रहा था. जो मुहिम उन्होंने शुरू की है, मैं उसमें उनका हाथ बंटाना चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा राजनीति से जुड़ें. हम युवा मिलकर अपनी पार्टी भूलकर यह काम करें तो यह देशहित में होगा.

***यह आपने बहुत अच्छी बात कही कि पार्टी लाइन भूलकर किसी फिल्म में ऐसा किरदार करने की ख्वाहिश है, जिसके ज़रिए आप लोगों को संदेश दे सकें कि देश के लिए कुछ करना है...***

बिल्कुल, ऐसा किरदार करने की ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं राजनीतिज्ञ का किरदार पर्दे पर निभाना चाहूंगा या नहीं. अगर निभाना चाहूंगा तो वह अलग होगा. जिस तरह इंडस्ट्री में राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और सरकारी नौकरीपेशा लोगों की जो छवि बना दी गई है, कहने का मतलब यह कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होतीं, अच्छे-ग़लत लोग हर क्षेत्र में होते हैं, इसलिए केवल राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों को ही फोकस क्यों किया जाता है. मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस छवि को सुधारूं.

***फिल्म में मुख्यत: दो धाराएं चलती हैं, सार्थक सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा. इन दो चीजों को, चूंकि आपको पढ़ने का शौक रहा है और जो पढ़ने का शौक रखता है, वह उसे अपनी कल्पना में उतारता है. कभी आपके जेहन में ऐसा कोई किरदार आता है या जब आप एक्टिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो चीज आपने पढ़ी है, वह आपके किरदार से मैच करती है और इस चीज को जिस तरह निर्देशक कह रहा है, वैसे पेश न करके किसी दूसरे तरीक़े से पेश किया जाए, जो लोगों के दिलों को छुए. क्या इस तरह की कभी कशमकश होती है?***

कई बार ऐसी कशमकश रही कि हमारे डायरेक्टर ने यह बोला, लेकिन पर्सनली मैं उसे दूसरी तरह करने में कंफर्टेबल हूं. मेरी पहली फिल्म मिले ना मिले हम में एक ऐसे लड़के की कहानी है, जो एक ब्रोकेन फैमिली से आता है और मैं एक संयुक्त परिवार से हूं. कितनी बार यह किरदार एक वेयर्ड वे में रिएक्ट करता था, जो मुझे समझ में नहीं आता था कि यह इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि मैं उसकी जगह होता तो नहीं कर पाता, लेकिन एक्टर का काम यही है कि वह अपने किरदार में जान डाल दे, उसे समझे और उसकी ज़िंदगी जिए. मैंने इस फिल्म में यही कोशिश की और आगे भी यही करूंगा.

***मुश्किलें क्या आती हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप एक अनुशासित परिवार से आते हैं, तीनों भाई साथ रहते हैं, बड़े मर्यादित तरीक़े से आपका पालन-पोषण हुआ. ऐसे में उस परिवेश में जाना, जहां बिल्कुल खुलापन है, वहां आप कैसे तालमेल बैठाते हैं?***

इसका पूरा श्रेय मेरे परिवार को जाता है, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया. परिवार का प्रोत्साहन ही मुझे हर संघर्ष और विषम परिस्थितियों से निपटने में काफी मदद करता है. पारिवारिक सहयोग-समर्थन के चलते सारी चीजें मेरे लिए काफी सरल सी हो जाती हैं.

***मैं फिर राजनीति और अभिनय को जोड़ रही हूं, चूंकि अभी जो स्थिति है, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने शौक यानी अभिनय के सहारे अपने पेशे यानी पार्टी को मज़बूत बनाना चाहते हों, उसे एक मज़बूत जमीन देना चाहते हों?***

नहीं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है. अगर ऐसा कुछ होता है तो ग़लत भी नहीं है. लेकिन ऐसी मंशा रखकर, यह सोचकर मैंने कोई योजना नहीं बनाई कि पहले एक्टिंग के क्षेत्र में उतरूं, जिससे पार्टी को फ़ायदा मिले. अभिनय मेरा शौक है और राजनीति मेरा पेशा, यह दोनों चीजें अच्छी तरह चलें, यही कामना है.

feedback@chauthiduniya.com

# तुम जियो हजारों साल

## मीनाक्षी शेषाद्री : ख़ूबसूरती और अभिनय का संगम

अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्रि का जन्म वर्तमान झारखंड प्रांत के सिंदरी नामक शहर में 16 नवंबर को हुआ था. वैसे तो मीनाक्षी मूलत: तमिलनाडु से हैं, परंतु उनके पिता सिंदरी स्थित उर्वरक कारखाने में कार्यरत थे, इसलिए उनका परिवार इसी शहर में बस गया था. ख़ूबसूरती और नृत्य का जो संगम मीनाक्षी ने पर्दे पर पेश किया, उसकी नींव बचपन में रखी गई थी. चार साल की उम्र से ही उन्होंने मंच पर भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी. हालांकि उन्हें यह मालूम नहीं था कि आगे चलकर यही परफार्मेंस उन्हें सिल्वर स्क्रीन की तरफ़ खींच ले जाएगा. उन्होंने भरतनाट्यम, कत्थक एवं ओड़िसी जैसे भारतीय नृत्यों की विधिवत शिक्षा प्राप्त की. 1981 में मिस इंडिया बनीं मीनाक्षी के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई हिंदी फिल्म पेंटर बाबू से, जिसमें उनके साथ थे मनोज कुमार के भाई राजीव गोस्वामी. इसके बाद सिल्वर स्क्रीन पर जादू बिखेरने की जो अदा मीनाक्षी ने अपनाई, उसने लोगों को उनका कायल बना दिया. हीरो, मेरी जंग, विजय, शहंशाह, घायल, दामिनी एवं डुएट जैसी लाजवाब फिल्मों ने उनकी कामयाबी की दास्तान लिखी. 15 साल के करियर में उन्होंने लगभग 80 फिल्मों में काम किया. मीनाक्षी ने नृत्य का शौक बरक़रार रखा. 2006 में 50 साल की उम्र में पुणे के एक उत्सव में ख़ूबसूरत नृत्य पेश किया. मीनाक्षी के जीवन में यू-टर्न तब आया, जब उनकी एक ख़ास सहेली ने उन्हें किसी पार्टी के दौरान अपने भाई हरीश मायर से मिलवाया. पार्टी के बाद मीनाक्षी हरीश से मिलने लगीं. अमेरिका में इंवेस्टमेंट बैंकर के पद पर काम कर रहे हरीश मीनाक्षी के दिल में बस गए और फिर दोनों परिणय सूत्र में भी बंध गए. परिवार को महत्व देने वाली मीनाक्षी ने पति के साथ टेक्सास में रहने का फ़ैसला कर लिया और अपने फिल्मी सफर को विराम दे दिया. टेक्सास जाकर उनकी ज़िंदगी बदल गई. ड्राइविंग से भय खाने वाली मीनाक्षी ने वहां पहुंच कर सबसे पहले कार चलाना सीखा. हरीश के प्यार एवं सहयोग ने वहां की दूसरी परेशानियों से पार पाने में मदद की. इस बीच मीनाक्षी ने दो प्यारे बच्चों को जन्म दिया. मीनाक्षी सुपर मॉम बनकर टेक्सास की सड़कों पर कार भी चलाती हैं और अपनी बेटी एवं बेटे को उनके हॉबी क्लासेस-स्कूल आदि ले जाती हैं. मीनाक्षी ने पति के सहयोग से अपने शौक पर भी ध्यान दिया और अमेरिका में एक डांसिंग स्कूल की शुरुआत की, जहां वह अपने सपनों को आकार दे रही हैं. फिल्म इंडस्ट्री की तरफ़ वापसी का विचार उनका नहीं है, क्योंकि परिवार उनकी पहली प्राथमिकता है, लेकिन इंडस्ट्री में उनके योगदान को कभी कम नहीं आंका जा सकता. उनकी इसी उपलब्धि पर फिल्म निर्माता मार्गेट स्टीफंस दो घंटे की म्यूजिकल डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं.

# क़िस्मत की धनी नूपुर

हल्की भूरी आंखों और लंबे भूरे बालों वाली नूपुर पटवर्धन को यक़ीन नहीं था कि उनकी क़िस्मत इस तरह करवट लेगी. करियर की शुरुआत में अक्षय कुमार जैसे अभिनेता के साथ स्क्रीन शेयर करना मामूली बात नहीं, चाहे वह कोई विज्ञापन ही क्यों न हो. अक्षय के साथ कोल्डड्रिंक थम्सअप के विज्ञापन में काम करने वाली प्रख्यात मॉडल नूपुर पटवर्धन डायरेक्टर राकेश जैन की आने वाली फिल्म ये स्टूपिड प्यार में मुख्य भूमिका में नज़र आएंगी. नूपुर ने पिछले साल बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो से कोर्स किया है. ये स्टूपिड प्यार उनकी पहली फिल्म है, जिसके हीरो हैं जतिन. उनकी भी यह पहली फिल्म है. नूपुर कहती हैं कि वह इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं और ख़ुद को बहुत लकी मानती हैं. फिल्म की कहानी दो युवा प्रेमियों पर आधारित है, जो असमंजस में हैं कि उन्हें प्यार है कि नहीं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# गागा का जलवा

मदर ऑफ मोनेस्टर उर्फ पॉप स्टार लेडी गागा और विवादों का चोली-दामन का साथ है. ट्वीटर पर जिसके एक करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर हों, वह यदि विवादों में आए तो सुर्ख़ियां बनना लाज़िमी है. गागा जब इंडिया आईं तो इस बार उनके कपड़ों एवं माइक ने उन्हें विवादों में डाल दिया. लेडी गागा ने दिल्ली में अपने प्रशंसकों का अभिवादन नमस्ते कहकर किया. फॉर्मूला वन रेस के अवसर पर हुए उनके कार्यक्रम के टिकट का दाम 40 हज़ार रुपये था, बावजूद इसके लोगों में ज़बरदस्त उत्साह देखा गया. ग्रेटर नोएडा के जेपी इंडिग्रेडेट कांप्लेक्स में हुए इस कार्यक्रम में गागा का जादू सिर चढ़कर बोला. इस मौक़े पर शाहरुख ख़ान, गौरी ख़ान, सोनम कपूर, बिपाशा बसु, अनिल कपूर, चंकी पांडे, अर्जुन रामपाल, इमरान ख़ान, प्रीति जिंटा, दीपिका पादुकोण, संजय कपूर, फरदीन ख़ान, क्रिकेटर युवराज सिंह, आशीष नेहरा, उद्योगपति विजय माल्या एवं सिद्धार्थ माल्या की मौजूदगी ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए.

## फिल्म प्रीव्यू

### शक्ल पे मत जा

निर्देशक शुभ मुखर्जी ने देश में हुए आतंकी हमलों पर एक फिल्म बनाई है, जिसका नाम है शक्ल पे मत जा. एक्टर-प्रोड्यूसर हृषिता भट्ट की इस फिल्म की शूटिंग बिना अनुमति के संसद परिसर में हो गई. देश के अति सुरक्षित क्षेत्र में जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तब सुरक्षाकर्मी तमाशा देख रहे थे. फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग दिल्ली एयरपोर्ट और संसद परिसर में हुई है. 2001 में संसद में जिस जगह हमला हुआ था, उसी जगह शूटिंग हुई. शूटिंग करते वक़्त उन्हें किसी ने नहीं रोका. जबकि इस फिल्म की शूटिंग से पहले जब उन्होंने एक डाक्यूमेंट्री के लिए संसद परिसर में शूटिंग करनी चाही थी, उस समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. फिल्म की कहानी चार ऐसे युवकों पर आधारित है, जिन्हें आतंकवादी होने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया जाता है. निर्देशक के अनुसार, इसके बाद चारों युवक व्यवस्था की पोल खोलने का फ़ैसला करते हैं, वे कड़ी सुरक्षा वाले इलाक़ों में बम लगाते और फिर ख़ुद उन्हें बेकार करते हैं. अपनी इन हरकतों की वे रिकॉर्डिंग भी करते हैं, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि कड़ी सुरक्षा वाले स्थानों पर कैसी ख़ामियां हैं. शुभ का कहना है कि फ़िल्म शक्ल पे मत जा क़रीब आठ महीने पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर हुई एक वास्तविक घटना पर आधारित है. घटना के पीड़ितों में वह ख़ुद भी शामिल हैं. मुखर्जी ने बताया कि उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर संदेहवश रोक लिया गया था. तस्वीरें लेते समय पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और आठ घंटे से ज़्यादा पूछताछ की. हृषिता भट्ट ने फ़िल्म में अभिनय नहीं किया है, मगर पटकथा बेहतर होने के कारण उन्होंने सह निर्माता बनने का फ़ैसला किया.

# चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 14 नवंबर-20 नवंबर 2011

www.chauthiduniya.com



Website : sanjeevanibuildcon.in

"संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI STATION
BIT Pithoria, Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9386045623/9470981772

9470943888, 9471763171


## राज्यसभा व विधान परिषद के लिए ज़ोरदार लॉबिंग शुरू

# अनार कम, बीमार ज़्यादा

*अगर दोबारा मनोनयन न करने का फॉर्मूला लागू किया गया तो चुनावी अखाड़े में कूदना नीतीश कुमार, भीम सिंह व नरेंद्र सिंह की मजबूरी हो जाएगी. यह विकल्प अपने आप में समाधान है तो सवाल भी है. लेकिन फ़िलहाल कमज़ोर विपक्ष को देखते हुए जदयू अपने मंत्रियों को चुनाव लड़ाने के विकल्प को तवज्जो दे सकता है.*

भीम सिंह



नरेंद्र सिंह



वशिष्ठ नारायण सिंह



संजय सिंह



उपेंद्र चौहान



छोटू सिंह



शकील अहमद

सरोज सिंह

बिहार से राज्यसभा की छह और विधान परिषद की 23 सीटों के लिए निर्वाचन व मनोनयन की प्रकिया भले ही अगले साल फरवरी से शुरू होगी पर सत्ता के गलियारों में इसके दावेदारों ने अभी से ही मज़बूत लॉबिंग शुरू कर दी है. सारी मारामारी जदयू व भाजपा में ही है, क्योंकि राजद, लोजपा व कांग्रेस को इस चुनाव व मनोनयन से कुछ मिलना नहीं है. नए जनादेश में जदयू व भाजपा का संख्याबल बढ़ा है, इसलिए सारा कुछ इनके ही हिस्से में आना है. जिन माननीय सदस्यों का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है वे फिर सत्ता का लॉलीपाप चाहते हैं और जो अब तक आश्वासनों के ऑक्सीजन पर हैं, वे अपनी सीट इस बार हर हाल में पक्की करा लेना चाहते हैं. कुछ दावेदार सामाजिक व जातीय समीकरण का पिटारा खोलकर बैठे हैं तो कुछ ने सीट न मिलने पर खेल बिगाड़ने का स्पीकर खोलने का मन बना रखा है. इस पूरे खेल का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं, जिन्हें न तो राज्यसभा में जाना है और न ही परिषद में, पर वे कुछ ऐसे खिलाड़ियों का खेल बिगाड़ देना चाहते हैं जो भविष्य की राजनीति में उनके लिए ख़तरा बन सकते हैं. प्रदेश की राजनीति में बिछी इसी बिसात की वजह से समय के काफी पहले ही किला फ़तह करने की कवायद अपने-अपने ढंग से माननीय नेताओं ने शुरू कर दी है. इस खेल में कुछ परदे के सामने हैं तो कुछ परदे के पीछे.

पहले इन माननीय सदस्यों को जान लेना ज़रूरी है, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है. राज्यसभा से रविशंकर प्रसाद, प्रो जाबिर हुसैन, अली अनवर, किंग महेंद्र, राजनीति प्रसाद और अनिल सहनी का टर्म ख़त्म हो रहा है. जबकि विधान परिषद के लिए मनोनीत सदस्यों में संजय कुमार सिंह उर्फ़ गांधी जी, शिव प्रसन्न यादव, प्रो. असलम आजाद, गणेश भारती, ब्रह्मदेव नरायण आजाद, गंगा प्रसाद, राजवंशी सिंह, डॉ. रामकिशोर सिंह, संजय कुमार झा और राजेंद्र गुप्ता का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है. प्रेम कुमार मणि की सदस्यता रद्द कर दी गई और शंभु शरण श्रीवास्तव ने ख़ुद इस्तीफ़ा दे दिया. इसी तरह विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में जिन नेताओं का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, उनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी, ग्रामीण कार्यमंत्री भीम सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह, रामश्रय प्रसाद सिंह, चंदन बागची, उदय नारायण राय, राजवंशी सिंह, उपेंद्र प्रसाद, ताराकांत झा और बालेश्वर भारती शामिल हैं. सूत्रों पर भरोसा करें तो जदयू व भाजपा में राज्यसभा की छह सीटों का बंटवारा तीन-तीन के हिसाब से हो सकता है, जबकि परिषद की 23 सीटों के लिए भाजपा 11 सीटों पर अपना दावा कर सकती है. मतलब 12 सीट जदयू के कोटे में आ सकती हैं. बताया जा रहा है कि अगर राज्यसभा में बराबरी का बंटवारा हुआ तो परिषद में जदयू ज़्यादा सीटों पर अपना दावा ठोकेगा. ऐसे में 13 व 10 का फॉर्मूला लागू हो सकता है. इतना तय है कि इन सीटों के बंटवारे से कहीं ज़्यादा इन दलों के शीर्ष नेताओं को सीटों को भरने में ज़्यादा मगजमारी करनी पड़ सकती है. अभी हाल में ही नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की ख़बरें उछलने लगीं. पार्टी प्रमुख वशिष्ठ सिंह ने यह कहकर मामले को हल्का किया कि अभी उसका समय नहीं आया है. समय आने पर पार्टी इसका फ़ैसला करेगी. उन्होंने सही ही कहा कि अभी यह घोषणा करने का समय नहीं है कि मुख्यमंत्री फलां विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं. लेकिन सूत्र बताते हैं कि अंदरखाने यह तैयारी भी हो रही है कि हिलसा से उनको चुनाव लड़ाया जाए और प्रो. इशा सिन्हा को परिषद में जगह दी जाए. बताया जा रहा है कि एक रणनीति के तहत ही नीतीश कुमार परिषद का रास्ता छोड़ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. वह यह संदेश देना चाहते हैं कि जदयू में लगातार दो बार एमएलसी बनाने की परंपरा नहीं रही है और वह इसी परंपरा का पालन कर रहे हैं. ऐसा करना उनको इसलिए भी ज़रूरी लग रहा है कि इतने नए नेता जदयू में आ चुके हैं कि अगर पुराने लोगों को ही दोबारा जगह दे दी गई तो नए लोगों का क्या होगा.

ग़ौरतलब है कि पिछली बार वीरेंद्र चौधरी को दोबारा परिषद के लिए मनोनीत नहीं किया गया था. देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस परंपरा को तोड़ कुछ नेताओं को दोबारा परिषद भेजते हैं या ऐसे नेताओं के साथ ख़ुद भी चुनावी अखाड़े में उतरते हैं. अगर ऐसा हुआ तो मंत्री पद पर बने रहने के लिए भीम सिंह व नरेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में कूदना पड़ सकता है. दोनों ही विकल्प अपने आप में समाधान भी हैं और सवाल भी. दोबारा मनोननय में बहुत सारे नए चेहरे बाहर ही रह जाएंगे और चुनावी विकल्प में मालिक तो जनता ही होती है. हालांकि कमज़ोर विपक्ष के कारण चुनावी विकल्प बेहतर रास्ता हो सकता है. परिषद के लिए जिन नेताओं की दावेदारी जदयू में हैं, उनमें रामश्रय सिंह, भीम सिंह, नरेंद्र सिंह, संजय सिंह, रामवचन राय, शकील अहमद खान, नवीन आर्या, रविंद्र सिंह, नीतीश कुमार के परम मित्र मिथिलांचल के नरेंद्र सिंह, उपेंद्र चौहान, लोकप्रकाश सिंह, राजकुमार सिंह, बलियावी जी व युवा छोटू सिंह प्रमुख हैं. इसके अलावा कई ज़िले के पार्टी अध्यक्ष भी इस बार अपना दावा ठोक रहे हैं. महिला नेत्रियों का भी दबाव पार्टी पर है. राज्यसभा में किंग महेंद्र का दावा दरकिनार करना नीतीश कुमार के लिए काफ़ी मुश्किल होगा. नीतीश कुमार अगर जाबिर हुसैन को मनाने मे सफल रहे तो अली अनवर की राह मुश्किल हो सकती है. पार्टी अध्यक्ष वशिष्ठ सिंह का दावा बेहद मज़बूत माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि शरद यादव अपना कोई नाम चलाकर परेशानी पैदा कर सकते हैं. दिल्ली में ऐसे कई नाम आजकल शरद यादव के आगे पीछे चल रहे हैं. जहां तक भाजपा का सवाल है तो रविशंकर प्रसाद को लेकर परेशानी हो रही है. रविशंकर प्रसाद सभी की पसंद हैं पर एक बार फिर मनोनयन उनके रास्ते में रोड़ा अटका सकता है. सूत्र बताते हैं कि अगर यह बाधा आई तो बिहारी बाबू को राज्यसभा भेजकर रविशंकर प्रसाद को पटना के मैदान में उतारकर दिल्ली भेजा जा सकता है. लेकिन पार्टी से जुड़े लोग बताते हैं कि यह केवल अफ़वाह है, इस तरह की कोई नौबत नहीं आएगी और रविशंकर फिर राज्यसभा जाएंगे. राज्यसभा के दावेदारों में एक नाम संजय झा का भी उभर रहा है. भाजपा अपने वरिष्ठ नेताओं को भी पार्टी शासित राज्यों से भेजती रही है. ऐसे में एक नाम अश्विनी कुमार का भी सामने आ रहा है. भाजपा में परिषद के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं, उनमे सुशील मोदी, ताराकांत झा, गंगा प्रसाद, विवेक ठाकुर, संजय मयूख, सुधीर शर्मा, मंगल पांडे, लालबाबू प्रसाद, सतेंद्र कुशवाहा, संजीव चौरसिया, ब्रजेश सिंह रमण, रामकिशोर सिंह, रणवीर नंदन, डॉ. राजेंद्र गुप्ता, बालेश्वर भारती, कामेश्वर सिंह, राजवंशी सिंह, मिथिलेश तिवारी व अरविंद सिंह प्रमुख हैं. कोसी के इलाक़े से भाजपा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व न रहने के कारण आरती सिंह का दावा मज़बूत बन रहा है. वैसे सुषमा साहू व श्वेता वशिष्ठ के नाम भी चर्चा में हैं. विवेक ठाकुर के बारे में कहा जा रहा है कि पिता राज्यसभा में व पुत्र परिषद की शोभा एक साथ कैसे बढ़ा सकते हैं. वैसे सुशील मोदी, अश्विनी चौबे और सीपी ठाकुर अपने चेहेतों को सीट दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

इस तरह दोनों ही दलों मे दावेदारों की लंबी फ़ेहरिस्त है यानी एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति है पर निर्णय का आधार निश्चित तौर पर सामाजिक व जातीय समीकरण होगा. दिल्ली से लेकर पटना तक जिसकी लॉबिंग मज़बूत होगी वह सत्ता का लॉलीपाप पा सकता है. लेकिन यह तय है कि अगर दोबारा कोई सदस्य मनोनीत नहीं हो पाता है तो उसकी जगह उसी जाति से लोगों को लिया जाएगा. हां, यह ख्याल ज़रूर रखा जाएगा कि नया चेहरा हर कसौटी में कसा हुआ मिल जाए तो सोने पर सुहागा.


feedback@chauthiduniya.com


**पिछली बार वीरेंद्र चौधरी को दोबारा परिषद के लिए मनोनीत नहीं किया गया था. देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस परंपरा को तोड़ कुछ नेताओं को दोबारा परिषद भेजते हैं या ऐसे नेताओं के साथ खुद भी चुनावी अखाड़े में उतरते हैं. अगर ऐसा हुआ तो मंत्री पद पर बने रहने के लिए भीम सिंह व नरेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में कूदना पड़ सकता है.**

ताराकांत झा



गंगा प्रसाद



मंगल पांडे



संजय मयूख



सुधीर शर्मा



सूरज नंदन मेहता



विवेक ठाकुर